YouTube kanwhizztimes
@kanwhizztimes
@kanwhizztimes
www.kanwhizztimes.com

कैनविज टाइम्स

सिर्फ सच

❑ वर्ष-14 ❑ अंक-210 ❑ बुधवार, 03 सितम्बर 2025 ❑ नगर संस्करण ❑ लखनऊ से प्रकाशित एवं दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में प्रसारित ❑ मूल्य- ₹ 3.00 ❑ पृष्ठ-12

स्टार्ट-अप से लेकर स्मार्ट शहरों तक, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें बैंक मदद कर सकते हैं। बैंक एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं।

द्रौपदी मुर्मु

चुनाव आयोग ने दो जगह वोटर सूची में नाम होने पर पवन खेड़ा से मांगा जवाब 11

बिहार मंत्रिमंडल ने 49 एजेंडों पर लगाई मुहर 12

संक्षेप

भूटान के प्रधानमंत्री पांच सितंबर को आयेंगे अयोध्या

अयोध्या। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग पांच सितंबर को सुबह अयोध्या आकर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन अर्चन करेंगे। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने आज एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर के साथ भूटान के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। भूटान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसका निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक बलरामाचारी दुबे ने राममंदिर में तैनात सुरक्षा अधिकारियों एवं सुरक्षा बल के जवानों के साथ विदेशी मेहमान के प्रोटोकाल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त रखने की योजना को अंतिम रूप दिया। फुंडे ने बताया कि पांच सितंबर को सुबह 9:30 बजे भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, और दो घंटे तक राम मंदिर परिसर में रहेंगे। प्रधानमंत्री के दर्शन और भ्रमण का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। निखिल टी फुंडे और डॉ गौरव ग्रोवर ने बताया कि राममंदिर में श्रद्धालु दर्शन करते रहेंगे। राममंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन और आवागमन में कोई परेशानी न हो इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है।

केसीआर की बेटी के कविता बीआरएस से निलंबित

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मंगलवार को कठोर कदम उठाते हुए पार्टी विधायक के. कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया। बीआरएस महासचिव सोमा भारत कुमार और टी. रविंदर राव के एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने दलीय अनुशासन के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया। सुश्री कविता, केसीआर की बेटी और विधानपरिषद की सदस्य हैं। वह निजामाबाद सांसद भी रह चुकी हैं। बीआरएस ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हाल के घटनाक्रमों और पार्टी की जानकारी में लाए गए मुद्दों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। नेतृत्व ने सुश्री कविता की हालिया गतिविधियों को गंभीरता से लिया है। गौरतलब है कि सुश्री कविता ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना में कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं को इसके लिए सीधे तौर पर दोषी ठहराया था। केसीआर के बेटे के टी रामाराव सिरीसिला से विधायक हैं।

आगरा में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, आठ गिरफ्तार

आगरा। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की शाहगंज पुलिस ने मंगलवार को अवैध धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा करते हुये मुख्य आरोपी समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त नगर सोनम कुमार ने बताया कि हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का खेल शाहगंज में चल रहा था। मुख्य आरोपी राजकुमार लालवानी मुंबई से लौट कर आया था और धर्म परिवर्तन के काम में लगा हुआ था। दिव्य शक्तियों का हवाला देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कहता था।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन

आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितों के लिए योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

कैनविज टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी, जिसमें कम्पनीज एक्ट-2013 के सेक्शन-8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी देना भी शामिल रहा। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन तीन वर्ष के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है। इस निर्णय के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं को बेहतर अवसर देगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार और सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित करेगा।

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे। लेकिन, लगातार यह शिकायतें

- ❑ अब आउटसोर्सिंग होगी अधिक पारदर्शी, कर्मचारियों को मिलेगा पूरा मानदेय
- ❑ मासिक वेतन के साथ ही पीएफ और ईएसआई खातों में सीधे जाएगा पैसा
- ❑ आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विभाग की बजाए अब निगम द्वारा किया जाएगा
- ❑ निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से करेगा एजेंसी का चयन
- ❑ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 16 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित
- ❑ प्रावधान के तहत 3 साल तक विभाग में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे कर्मचारी
- ❑ कानपुर और लखनऊ में नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालित होंगी ई-बसें
- ❑ शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति

सामने आ रही थीं कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का नियमित अंशदान भी कई बार एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता था। इन अनियमितताओं को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह निगम गठित किया गया है। आउटसोर्सिंग के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रावधान किया गया है। इससे बेहतर गुणवत्ता वाले और योग्य कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का भी अधिकार दिया जाएगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 हजार रुपये अंतिम संस्कार सहायता के रूप में दिए जाएंगे।

ऐसी होगी नई व्यवस्था

- अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी तय करेगा।
- कर्मचारियों का मानदेय 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
- आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी।
- कर्मचारी तीन वर्षों के लिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे
- कर्मचारियों का वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे उनके खातों में जाएगा।
- ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान अब सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा, पहले यह राशि सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाती थी।
- किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी।

नगरीय परिवहन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी कैबिनेट ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर तथा उसके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में ई-बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि अभी तक प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 700 बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट ● शेष पेज 11 पर

यूपी में पैतृक संपत्तियों का बंटवारा अब 10 हजार में

कैनविज टाइम्स ब्यूरो

- ❑ 5000 स्टांप व 5000 देना होगा रजिस्ट्री शुल्क
- ❑ अभी संपत्ति की कुल कीमत का पांच प्रतिशत लगता था

लखनऊ। राज्य सरकार ने पारिवारिक (पैतृक) संपत्तियों का बंटवारा करना आसान कर दिया है। ऐसी संपत्तियों को 5000 रुपये स्टांप शुल्क और 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी 10 हजार रुपये देकर पंजीकृत बंटवारा किया जा सकेगा। अभी तक ऐसी संपत्तियों के बंटवारे पर कुल कीमत का पांच प्रतिशत देना होता था। इसमें चार प्रतिशत स्टांप व एक प्रतिशत शुल्क देना होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य सरकार के इस फैसले से 5.58 करोड़ स्टांप शुल्क और 80.67 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क का नुकसान होगा। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद की बातें सामने आ रही थीं।

उत्तर प्रदेश राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है तथा देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में जनसामान्य के पास संयुक्त/अविभाजित संपत्तियां हैं। बंटवारा विलेख का रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 के धारा-17 के अनुसार रजिस्ट्री कीराना अनिवार्य है। ऐसी संपत्तियों के बंटवारे पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क अधिक होने के कारण बंटवारा नहीं हो पाने से विवाद की स्थिति आ रही थी। इसीलिए तय किया गया कि पारिवारिक संपत्ति के विभाजन पर देय स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्री शुल्क को कम करने का फैसला किया गया

है। इससे पारिवारिक सदस्य बिना आर्थिक बोझ महसूस किए आसानी से संपत्तियों का बंटवारा करा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि परिवार में संपत्ति के सौहार्दपूर्ण बंटवारे के लिए विभाजन विलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुधा अचल संपत्ति के विवाद न्यायालयों में काफी समय तक लटके रहते हैं और पारिवारिक विवाद हल नहीं हो पाते हैं। संपत्ति के विवाद में परिवारजनों के मध्य हिंसक घटनाएं भी हो जाती है। कई बार आपसी सहमति होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, कैबिनेट के फैसले से विवाद कम होगा और बंटवारा आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के अन्य राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पैतृक अचल संपत्तियों के बंटवारे पर लगाने वाला स्टांप व रजिस्ट्रेशन शुल्क कम करते हुए प्रोत्साहित किया गया।

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण को लेकर सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन व सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 79 प्रतिशत आरक्षण के सम्बंध में पारित शासनादेशों को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल सरकार की विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अपील पर सुनवायी करते हुए, अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि उक्त निर्णय में क्या कमी है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जे एन माथुर ने दलील दी कि एकल पीठ के फैसले व आदेश से इन चारों जिलों के मेडिकल कालेजों में दाखिलों के लिए फिर से काउंसिलिंग करनी पड़ेगी। इससे प्रदेश के ने जिलों के मेडिकल कालेजों में दाखिलों के लिए हो रही काउंसिलिंग पर भी असर पड़ेगा।

उन्होने कहा कि नई काउंसिलिंग से पहले सीट पे अभ्यर्थी बाहर ही जाएंगे।

अन्य मेडिकल कालेजों में काउंसिलिंग पूरी होने की वजह से उनके पास विकल्प भी नहीं बचेंगे। उधर, याची अभ्यर्थी के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के कानूनी प्रावधानों के तहत कहकर इस पर पूरी तरह से अमल किए जाने का तर्क दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। हालांकि, याची के अधिवक्ता के मुताबिक शुरुआत में याचिका दाखिल करने वाली अभ्यर्थी सबरा अहमद को अंबेडकरनगर या पास के किसी मेडिकल कालेज में काउंसिलिंग में शामिल करने पर गौर करने का मौखिक निर्देश भी दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ● शेष पेज 11 पर

एकेटीयू दीक्षांत समारोह में मेधावियों को मिलेंगे 88 पदक, शुभांशु शुक्ला के नाम पर लगी मुहर

लखनऊ। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में मंगलवार को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को प्रदान किये जाने वाले पदक और डिग्रियों को अनुमोदन दिया गया। साथ ही समारोह के मुख्य अतिथि अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम का भी अनुमोदन किया गया। विवि के कुलपति प्रो जेपी पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में कुल 88 पदक दिये जाने पर सहमति बनी। जिसमें 37 स्वर्ण पदक तो 26 रजत और 25 कान्स्य पदक हैं। साथ ही बैठक में चार नये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें आरईसी बस्ती, आरईसी, गोण्डा, आरईसी प्रतापगढ़ एवं आरईसी मिर्ज़ापुर में नये इमर्जिंग पाठ्यक्रमों के संचालन को मंजूरी दी गयी। जिससे कि छात्र नई तकनीकी की पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा बैठक में पिछले वित्त समिति के प्रस्तावों का अनुमोदन दिया गया। इसमें करीब 142 करोड़ रूपये के बजट पर चर्चा की गयी। साथ ही विभिन्न ● शेष पेज 11 पर

सबसे अधिक राजस्व मामले निस्तारित कर लखनऊ अव्वल, जनपदीय न्यायालयों में जौनपुर ने मारी बाजी

कैनविज टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनीटरिंग का असर साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री खुद हर माह जिलावार मामलों की समीक्षा भी करते रहते हैं।

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) द्वारा अगस्त की जारी रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मामलों का निस्तारण राजधानी लखनऊ में किया गया है। जनपद स्तरीय न्यायालय में राजस्व के मामले निपटाने में एक बार फिर जौनपुर ने बाजी मारी है। जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण में पिछले 10 माह से जौनपुर टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है। राजधानी में सबसे अधिक कुल 19,178 मामले निस्तारित किये गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर

- ❑ राजस्व वादों के मामलों के तेजी से निस्तारण के सीएम योगी के निर्देशों का दिख रहा असर
- ❑ कुल राजस्व मामले के निस्तारण में प्रयागराज दूसरे, गोरखपुर तीसरे और जौनपुर चौथे स्थान पर
- ❑ जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व मामलों के निस्तारण में जौनपुर पहले, लखीमपुर खीरी दूसरे और आजमगढ़ तीसरे स्थान पर
- ❑ पिछले दस माह से जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण में जौनपुर टॉप फाइव में

सुलझाया जाए। राजस्व परिषद की अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में पूरे प्रदेश में कुल 3,69,293 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में 19,178 मामले निस्तारित किए गए, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद प्रयागराज में 10,693 मामलों को निस्तारित कर पूरे प्रदेश में दूसरे, गोरखपुर 9,560 मामलों को निस्तारित कर तीसरे स्थान पर है। इसी तरह जौनपुर ने 8,779 मामले निस्तारित कर चौथा और बाराबंकी ने 8,615 मामलों का निस्तारण कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है। जनपद स्तरीय न्यायालयों में जौनपुर ने मारी बाजी, सबसे अधिक 612 मामले किए निस्तारित जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के निर्धारित मानक निस्तारण से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। ● शेष पेज 11 पर

राष्ट्रपति के मामले में संविधान की व्याख्या करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह संविधान की व्याख्या सिर्फ राष्ट्रपति के मामले में करेगा, किसी राज्य या व्यक्ति से जुड़े अलग-अलग मामलों में नहीं। कोर्ट ने यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा भेजे बिलों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के साइन करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाले मामले में की।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण देंगे, तो केंद्र को भी जवाब दाखिल करना होगा। इस पर एख्क्र बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने कहा हम अलग-अलग राज्यों के मामलों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि केवल संविधान की धाराओं को देखेंगे।

सुनवाई में सिंघवी ने कहा कि अगर विधानसभा किसी बिल को वापस नहीं भेजना चाहती तो वह अपने आप

❑ किसी व्यक्तिगत मामले में नहीं, राज्यपालों-राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़ा मामला

अस्वीकृत हो सकता है। अगर राज्यपाल बिल को विधानसभा को लौटाते ही नहीं हैं, तो अनुच्छेद 200 की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। दरअसल, मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या अदालत राज्यपालों और राष्ट्रपति को बिलों पर फैसला करने के लिए समय-सीमा तय कर सकती है। सीजेआई ने सिंघवी से पूछा कि अगर राज्यपाल बिल को रोक कर रखें और वापस विधानसभा को न भेजें तो क्या होगा? इस पर सिंघवी ने कहा कि ऐसी स्थिति में बिल आगे नहीं बढ़ पाता और पहले के फैसलों के अनुसार वह 'फॉल थ्रू' मान लिया जाता है, जब तक कि अनुच्छेद 200 की ● शेष पेज 11 पर

जो लोग भारत माता का अपमान करने से बाज नहीं आते उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है: पीएम

कांग्रेस-आरजेडी ने मेरी मां को गाली दी, यह देश की हर मां का अपमान

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भावुक शब्दों में कहा कि जो लोग भारत माता को गाली देने से बाज नही आते हैं, उन्होंने अगर मेरी मां को गाली दी तो ऐसे लोगों से ऐसी ही अपेक्षा की जा सकती है।

श्री मोदी ने जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करने के बाद महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में यात्रा के दौरान राजद और कांग्रेस के लोगो ने गाली देकर सिर्फ़ मेरी माता का ही अपमान नही किया बल्कि उन करोड़ो माताओं के हृदय को चोट पहुंचाया जो मुफलिसी में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत कठिनाई से की और जब मैं उसकी सेवा के लायक हुए तो मुझे देश सेवा की अनुमति दे दी। अपनी मां से इजाजत ले कर मैं घर से बाहर निकला तथा देश और समाज के साथ करोड़ों माताओं की सेवा कर सका। आज अपनी बात कहते हुए यहां बैठी माताओं की आंखों में आंसू

देख कर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक गरीब माँ की पीड़ा को बड़े खानदान में पैदा हुए युवराज या नामदार लोग कभी नही समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि सौ साल पूरे कर मेरी माँ जा चुकी है और उसका राजनीति से कोई लेना देना नही था, ऐसी स्थिति में उसके नाम को घसीटना, उसे गली देना राजद और कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस देश मे नामदार लोगो को बिल्कुल पसंद नही आता कि कोई पिछड़ा, अतिपिछड़ा या गरीब आदमी ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और कहा जाता है कि 'माई के स्थान देवता पितर से भी उपर होला' उंस धरती पर मेरी मां को गाली दी गयी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि आने वाली है और पूरे देश मे दशहरा मनाया जाएगा लेकिन बिहार और पूर्वी क्षेत्र की पूजा में सात माताओं की पूजा होती है जी माताओं के प्रति उनके अनुराग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दशहरे और दीवाली के बाद होने वाली छठ पूजा माता के परस्ती अनुराग की पराकाष्ठा होती है और उसी धरती पर किसी मा को गाली दी जाए इसे बिहार की महिलाएं और पुरुष कैसे बर्दास्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मां ही तो ● शेष पेज 11 पर

भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी: मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतिगत स्थिरता का भरोसा दिलाते हुये मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी। श्री मोदी ने यहां द्वारका स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये सेमीकंडक्टर क्षेत्र के देश के नवाचारियों और स्टार्टअप को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और वे डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना तथा चिप्स-टू-स्टार्टअप कार्यक्रम का लाभ उठायें। सेमीकंडक्टर विनिर्माण की दिशा में देश की उपलब्धियां का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को भारत में बनी चिप्स से शक्ति मिले, इस पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा, नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे हमारे डिजाइन सेंटर दुनिया की कुछ आधुनिकतम चिप्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी चिप्स हैं जिसमें अरबों ट्रांजिस्टर्स को स्टोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब बैकएंड से निकलकर पूर्ण रूपेण सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, वह दिन दूर नहीं है, जब भारत की सबसे छोटी चिप, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारक बनेगी। निस्संदेह हमारी यात्रा कुछ देर से शुरू हुई है, लेकिन अब कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती इस सेक्टर में निवेश के लिए नवाचारियों और स्टार्टअप कंपनियों का आह्वान करते हुये उन्होंने कहा कि आज सेमीकंडक्टर डिजाइन तैयार करने वाली दुनिया की 20 प्रतिशत प्रतिभा भारतीय है। उन्होंने कहा, ळ्मैं अपने युवा उद्यमियों से, नवाचारियों से, स्टार्टअप्स से कहूंगा कि आप आगे आयें, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना और चिप्स-टू-स्टार्टअप कार्यक्रम आपके लिए ही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार डिजाइन आधारित नवाचार योजना को नया रूप देने ● शेष पेज 11 पर

मंत्री परिषद ने यूपी में 1607 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी : नन्द गोपाल नन्दी

देवरिया, शाहजहांपुर, गौतमबुद्धनगर एवं फरुखाबाद में चार कम्पनियों को जल्द ही जारी होंगे लेटर ऑफ कम्फर्ट

कैनविचज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में निवेश को लेकर मंजूर प्रस्तावों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि परिषद की बैठक में देवरिया, गौतमबुद्ध नगर, फर्रुखाबाद एवं शाहजहांपुर में 1607 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके आधार पर जल्द ही सभी कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश के गन्तव्य के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 अधिसूचित की गयी थी। जिसके अन्तर्गत वृहद श्रेणी में 50-200 करोड़, मेगा श्रेणी में 200-500 करोड़, सुपर मेगा श्रेणी में 500-3000 करोड़ व अल्ट्रा मेगा श्रेणी में 3000 करोड़ से अधिक की लागत वाली औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न प्रोत्साहन कैपिटल सब्सिडी, भूमि लागत पर सब्सिडी, नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, प्लान्ट एवं मशीनरी पर लिए गये ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट, इलेक्ट्रिसिटी में छूट, औद्योगिक अनुसंधान हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति आदि प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में चार प्रस्तावों पर विचार हुआ। जिनमें मेसर्स फॉरएवर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड-उसका बाजार औद्योगिक क्षेत्र (यूपीसीडा) के 250.12 करोड़, वाईटीटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र शाहजहांपुर के 277.86 करोड़, मेसर्स ओकासगंगा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड दादरी (गौतमबुद्धनगर) के 510.20 करोड़ एवं वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड फर्रुखाबाद के 570 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। निवेश प्रस्तावों को मंजूरी के बाद जल्द ही लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाएगा। मंत्री नन्दी ने कहा कि इन निवेश से प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की इकोनामी की ओर ले जाने में सहायता मिलेगी और वृहद रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

राज्यपाल से भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मंगलवार को राजभवन में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। विदेश मंत्रालय के अधीन मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत ये अधिकारी एक सितम्बर से पांच सितम्बर तक उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर आए हुए हैं। राज्यपाल ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारियों को जमीनी स्तर पर शासन-प्रशासन, विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली समझने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन अधिकारियों का यह अनुभव, विदेश सेवा में कार्य करते हुए भारत की छवि को और सशक्त बनाने में सहायक होगा। राज्यपाल ने अधिकारियों से संवाद करते हुए उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-बाल विकास, स्टार्ट-अप, कृषि, निवेश, पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहर से सम्बन्धित पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और विदेशों के साथ निवेश तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अनेक अवसर यहां उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापन संपन्न हुए हैं। विश्वविद्यालयों ने नैक में सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त कर अपनी गुणवत्ता को प्रमाणित किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विदेशी विद्यार्थी अब उत्तर प्रदेश में आकर हिंदी और संस्कृत सहित अन्य विषयों का भी अध्ययन कर रहे हैं।

पीईटी परीक्षा की निष्पक्ष व नकलविहीन सम्पन्न कराने को लेकर डीएम ने की समीक्षा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 6 व 7 सितम्बर को आयोजित की जाने वाली प्रारम्भिक पात्रता परीक्षा (घ्क्ष्ठ) को सकुशल, निष्पक्ष एवं नकलविहीन रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में एक समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने की।बैठक में जिलाधिकारी ने परीक्षा संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे पूर्ण जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सर्वोपरि है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता कदापि क्षम्य नहीं होगी।जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने या व्यवधान डालने की कोई भी कोशिश की गई, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे टीम भावना के साथ कार्य करते हुए परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराएं।प्रशासन की ओर से सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, निगरानी तंत्र और अन्य सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन घ्क्ष्ठ परीक्षा को शांति, सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है।इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, परीक्षा केंद्रों के नोडल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आईजीआरएस प्रकरणों में लापरवाही पर दो लेखपाल मुख्यालय से सम्बद्ध

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मंगलवार को तहसील मेजा में तैनात दो लेखपालों—कमला प्रसाद पाण्डेय एवं धवल पाण्डेय—के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें जनपद मुख्यालय से सम्बद्ध करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई इन लेखपालों द्वारा आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रिवेंस रिड्रेसल सिस्टम) से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में समयबद्धता, गुणवत्ता एवं गंभीरता की कमी के कारण की गई है। जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया है कि नियमानुसार अग्रेत्तर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता और जन शिकायतों के प्रति लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयसीमा के भीतर, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण किया जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करता है, खराब फीडबैक प्राप्त होता है, या निस्तारण में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है, तो ऐसे मामलों में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि शासन स्तर से लगातार शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है और इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोताही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और जनहित के कार्यों में पूर्ण जिम्मेदारी के साथ भागीदारी सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की समीक्षा बैठक

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष अंतर्गत जिला संचालन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, जिला प्रोबेशन कार्यालय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया कि योजना के अंतर्गत अब तक 492 प्रकरण पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 273 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 219 प्रकरण अभी भी लंबित हैं। इनमें से:83 केस जिला संचालन समिति के स्तर पर114 केस नोडल चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर22 केस नोडल पुलिस अधिकारी के स्तर पर लंबित हैं।बैठक में जिला समिति के स्तर पर लंबित 83 मामलों में से 33 मामलों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से 24 को स्वीकृति और 9 को अस्वीकृति प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने नोडल चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि शेष 114 लंबित मामलों की चिकित्सीय रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अपलोड कर जिला संचालन समिति को अग्रसारित की जाए। वहीं, 22 पुलिस से संबंधित प्रकरणों में चार्जशीट व अन्य आवश्यक दस्तावेजों को भी एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश नोडल पुलिस अधिकारी को दिए गए।इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां पीड़िता के बैंक विवरण, चार्जशीट या अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें स्थानीय थाने के माध्यम से प्राप्त कराए जाने के लिए पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि महिला एवं बाल अपराध से जुड़े प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और पीड़िताओं को समय से न्याय व सहायता मिल सके, इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को समन्वयात्मक प्रयास करने होंगे।

त्यौहारों के मद्देनजर बढ़ेगा ट्रेनों का फेरा

वाराणसी। रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी दशहरा, दीवाली एवं छठ पूजा त्यौहारों पर यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व से चलाई जा रही 04090/04089 आनन्द विहार टर्मिनस-पटना-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी वाया गाजीपुर सिटी, बलिया एवं छपरा के संचलन अवधि का विस्तार 29 नवम्बर, 2025 तक आनन्द विहार टर्मिनस से तथा 30 नवम्बर, 2025 तक पटना से 22 फ़ेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा। 04090 आनन्द विहार टर्मिनस-पटना विशेष गाड़ी 29 नवम्बर, 2025 तक आनन्द विहार टर्मिनस से प्रतिदिन 14.25 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेण्ट्रल से 21.35 बजे, दूसरे दिन प्रयागराज जं0 से 00.25 बजे, वाराणसी से 03.20 बजे, गाजीपुर सिटी से 05.00 बजे, बलिया से 06.00 बजे, सहतवार से 06.22 बजे, सुरेमनपुर से 06.50 बजे, छपरा से 08.15 बजे तथा पाटलिपुत्र से 10.20 बजे छूटकर पटना 11.00 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में 04089 पटना-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी 30 नवम्बर, 2025 तक पटना जं0 से प्रतिदिन 18.20 बजे प्रस्थान कर पाटलिपुत्र से 18.55 बजे, छपरा से 21.10 बजे, सुरेमनपुर से 21.50 बजे, सहतवार से 22.13 बजे, बलिया से 22.40 बजे, गाजीपुर सिटी से 23.40 बजे, दूसरे दिन वाराणसी से 01.55 बजे, प्रयागराज जं0 से 04.45 बजे तथा कानपुर सेण्ट्रल से 07.55 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 14.50 बजे पहुँचेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय सह तृतीय श्रेणी का 01, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 02, शयनयान श्रेणी के 12, साधारण द्वितीय श्रेणी के 04 तथा एस.एल.आर. के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे।

नगर निगम ने काशी एप के माध्यम से दी मलवा हटाने की सुविधा

वाराणसी। नगर निगम सीमा में बिल्डिंग मेटेरियल से सम्बन्धित निकलने वाले मलबा के निस्तारण हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा स्मार्ट काशी एप के माध्यम से सुविधा प्रदान की है। इस हेतु नगर निगम द्वारा शहर क्षेत्र में विभिन्न 14 स्थानों पर सी0एण्ड0डी0 वेस्ट इकट्ठा करने के लिये स्थान चिन्हित किया गया है। इन 14 स्थानों की पूर्ण सूचना नगर निगम के स्मार्ट काशी एप पर उपलब्ध है, जहॉ से कोई भी नागरिक अपने घरों से निकलने वाले सी0एण्ड0डी0 वेस्ट को अपने नजदीकी स्थान पर मलबा गिरा सकता है। स्मार्ट काशी एप को प्ले स्टोर के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट में यदि महिने में 300 टन मलबा या 20 टन प्रतिदिन निकलता है तो स्मार्ट काशी एप पर मलबा उठवाने की सूचना देने पर नगर निगम द्वारा कलेक्शन, ट्रान्पोटेशन इत्यादि कार्य हेतु रु0 525/- प्रति टन नगर निगम को शुल्क के रूप में देना होगा, यदि व्यक्ति स्वंय कलेक्शन, ट्रान्पोटेशन कर प्लाण्ट पर पहुँचाता है तो रु0 173/- प्रति टन निस्तारण हेतु नगर निगम को देय होगा। नगर निगम, वाराणसी द्वारा नव विस्तारित क्षेत्रों में 9 अतिरिक्त सी0एण्ड0डी0 वेस्ट कलेक्शन स्थान का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बन जाने से नव विस्तारित क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को सुविधा प्राप्त होगा।

चयनित रिक्रूट आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आचरण एवं व्यवहार के विषय पर व्याख्यान देते अपर पुलिस आयुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी राजेश कुमार

वैध दावे के बावजूद घर गिराने पर हाईकोर्ट ने डीएम रायबरेली को लगाई फटकार, 10 दिन में हलफनामा तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैध राजस्व अभिलेखों में दर्ज संपत्ति को ध्वस्त किए जाने पर रायबरेली के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब भूमि का दावा राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज था, तो फिर आवास को ध्वस्त करने की जल्दबाजी क्यों की गई। पीड़ित व्यक्ति द्वारा घर गिराए जाने की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़ित का दावा वैध और दस्तावेज़ों में दर्ज था, बावजूद इसके प्रशासन ने बिना उचित प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस पर कोर्ट ने प्राधिकारियों की तीखी आलोचना की और कार्रवाई को गंभीर प्रशासनिक त्रुटि बताया। हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में की गई कार्रवाई पर जुर्माना लगाने की भी बात कही है और जिलाधिकारी रायबरेली को निर्देश दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण दें।

नरेश पाल सिंह ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार संभाला

कैनविचज टाइम्स संवाददाता

प्रयागराज । भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी नरेश पाल सिंह ने सोमवार को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है । यह पद उपेन्द्र चंद्र जोशी के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुआ था। श्री सिंह को यह दायित्व उनके वर्तमान कार्यभार-महाप्रबंधक, बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका)-के साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है।

श्री सिंह भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने आईआईटी रुड़की से वर्ष 1987 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अपने तीन दशक से अधिक के करियर में उन्होंने रेलवे के

तकनीकी नवाचार और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं श्री सिंह

विभिन्न तकनीकी, संचालन एवं प्रशासनिक पदों पर उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने मध्य रेलवे, मुंबई मंडल, मुंबई रेल विकास निगम एवं बरेका में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। बरेका के महाप्रबंधक के रूप में, श्री सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 में 477 लोकोमोटिव का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। उनके नेतृत्व में बरेका ने एयरोडायनामिक डइ्घ-7 लोको का सफल निर्माण किया और रेल ट्रैक पर सोलर पैनल लगाकर हरित ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया।

इसके अलावा, मध्य रेलवे में उनके कार्यकाल के दौरान 2ब25द्मठ्ठ ट्रैक्शन सिस्टम में ग्च्क्ड तकनीक का उपयोग कर संचार व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया गया। इस परियोजना से न केवल ''कवच'' और सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, बल्कि गैर-किराया राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही, ग्राउंड मेकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेलवे को प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है। श्री नरेश पाल सिंह का नेतृत्व भारतीय रेलवे को तकनीकी नवाचार, हरित ऊर्जा, और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बना रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में उनकी नियुक्ति से संगठन को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद की जा रही है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर चार अस्पताल और क्लीनिक सील, एक का पंजीकरण निलंबित

कैनविचज टाइम्स संवाददाता

प्रयागराज। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज अधोहस्ताक्षरी की टीम द्वारा जनपद के विभिन्न निजी अस्पतालों व क्लीनिकों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर चार संस्थानों को सील किया गया तथा एक अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया।

स्वाती हॉस्पिटल, ममफोर्डगंज : अस्पताल में दो दिन पूर्व इलाज के दौरान एक 5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हुई थी, जिस पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि अस्पताल के पैनल में कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ नहीं था, जिस पर तत्काल प्रभाव से अस्पताल को सील कर दिया गया।

अपना हॉस्पिटल, हरखपुर महरौड़ा : यह अस्पताल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए टीम ने इस अस्पताल को सील कर दिया।

विवेक मेडिकल क्लीनिक, गौरीगंज बाजार (निकट कल्याणपुर, सोरांव) : श्री जगदीश प्रसाद सोनी की शिकायत पर टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में क्लीनिक अवैध रूप से संचालित पाया गया। टीम के पहुंचने पर संचालक मौके से लापता हो गया, जिसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया।

न्यू प्रीति हॉस्पिटल, ददौली, लकमंडी, मऊआइमा : श्री विकास पटेल की शिकायत पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि हॉस्पिटल में अनाधिकृत रूप से पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही थी, जिसे सील किया गया। साथ ही, बिना नवीनीकरण के ओटी, ओपीडी चैम्बर का संचालन हो रहा था, जिस पर ओटी व ओपीडी चैम्बर को सील करते हुए हॉस्पिटल का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई जनहित में एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद में संचालित सभी निजी चिकित्सा संस्थानों की नियमित जांच जारी रहेगी, और किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम विरुद्ध संचालन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी-मुख्य चिकित्सा अधिकारी

डीएम ने मृत घोषित करने की गलत रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत अधिकारी को दिए निलंबित करने का आदेश

कैनविचज टाइम्स संवाददाता

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरण में गंभीर लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करने तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को पीड़ित की पेंशन तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है।

सोमवार को आयोजित जनता दर्शन के दौरान प्रार्थी सुकुरू पुत्र सम्पत, निवासी ग्राम पालीकरनपुर, विकासखंड बहादुरपुर, ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें वर्ष 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वे जीवित हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती हर्षिका सिंह द्वारा की गई जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रंजना यादव ने सत्यापन रिपोर्ट में गलत जानकारी दर्ज की, जिसके कारण प्रार्थी की पेंशन बंद हुई।

जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) अखिलेश कुमार यादव की लापरवाही पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए गए।

व्यावसायिक शिक्षा से प्रदेश में तैयार हो रही है सशक्त तकनीकी मैनपावर

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 62% युवा उत्पादक आयु वर्ग में आते हैं, जिन्हें रोजगारपरक कौशल प्रदान करने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) में विभिन्न 01 व 02 वर्षीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं।

प्रदेश में वर्तमान में 324 आई.टी.आई. कार्यरत हैं, जिनमें से 38 पी.पी.पी. मॉडल पर संचालित हैं। प्रत्येक वर्ष 1.84 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में घोषित 35 नए आई.टी.आई. में से 23 का निर्माण पूरा कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अब तक 2.81 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 151 आई.टी. लैब व 144 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं।

टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (टी.टी.एल.) के सहयोग से 149 आई.टी.आई. में कौशलम केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 3-डी प्रिंटिंग जैसे 11 न्यू-एज कोर्स व 23 शॉर्ट-टर्म कोर्स संचालित हैं। आगामी वर्षों में 62 और आई.टी.आई. को अपग्रेड कर 7 नए कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। इन पहलों से प्रदेश में सशक्त तकनीकी मैनपावर तैयार हो रही है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएगी।

उत्तर रेलवे

खुली निविदा सूचना (ई-निविदा)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक (इंजीनियरिंग), उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु **सिंगल पैकेट पद्धति** से ई-निविदा प्रणाली द्वारा जिसकी अंतिम निविदा तिथि दिनांक **26.09.2025** को 15.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इस निविदा के मैनुअल आफर स्वीकार नहीं किये जायेगें यदि कोई मैनुवल ऑफर आता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म का मूल्य जमा नहीं करना है तथा निविदाकर्ता को धरोहर राशि का भुगतान केवल ireps पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन भुगतान प्रणाली में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि द्वारा करेगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिपॉजिट रसीद एवं एफ डी आर द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

निविदा सूचना संख्या		09402025 दिनांक 01.09.2025
कार्य का नाम	1.	वरि0 मण्डल इंजीनियर – तृतीय/उ0रे0/लख0 के कार्य क्षेत्र में सहायक मण्डल अभियंता/वाराणसी तथा सहायक मण्डल अभियंता/जौनपुर के अधीन दीनदयाल उपाध्याय-वाराणसी तथा जफराबाद-शाहगंज-अकबरपुर खण्ड में टी0आर0टी0 मशीन द्वारा टी0एस0आर0 (प्रा0) = 17.39 ट्रैक किमी0, दीनदयाल उपाध्याय-वाराणसी तथा वाराणसी-जफराबाद खण्ड में टी0आर.आर0 (प्रा0) = 20.781 ट्रैक किमी0 वाराणसी-जंघई, जौनपुर-औंरिहार तथा वाराणसी-जफराबाद खण्ड में टी0आर0आर0 (प्रा0) = 4.737 ट्रैक किमी0 का कार्य।
	2.	वरि0 मण्डल इंजीनियर – तृतीय/उ0रे0/लख0 के कार्य क्षेत्र में टी0टी0आर0 (टी0एस0आर0) – 22 सेट्स (1 इन 12 – 16 सेट्स तथा 1 इन 8.5 – 6 सेट्स) टी0टी0आर (एफ0एस0 + टी0डब्ल्यूएस0 + डब्ल्यूसी0एम0एस0सी0) – 5 सेट्स (1 इन 12 – 3 सेट्स तथा 1 इन 8.5 – 2 सेट्स) तथा टी0टी0आर0 (टी0डब्ल्यूएस0) – 10 सेट्स (1 इन 12 – 10 सेट्स), टी0एफ0आर0 = 98.263 ट्रैक किमी0 तथा टी0 एस0 आर0 (सेकेण्डरी) = 8.872 ट्रैक किमी0 जैसे विभिन्न प्रकार के रेल पथ संबंधी कार्य।

अनुमानित लागत	क्रम सं. 1 एवं 2 के लिए	रु.4,63,16,817.35 रु.3,29,98,355.44
धरोहर राशि	क्रम सं. 1 एवं 2 के लिए	रु.3,81,600.00 रु.3,15,000.00
कार्य की समापन अवधि	क्रम सं. 1 एवं 2 के लिए	स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि से बारह (12) माह।
निविदा डालने का प्रारंभ	क्रम सं. 1 एवं 2 के लिए	12.09.2025
निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	क्रम सं. 1 एवं 2 के लिए	26.09.2025 15:00 बजे
वेबसाईट		www.ireps.gov.in

नोट :
1. तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों के खुलने के बाद अतिरिक्त दस्तावेज की प्रस्तुति एवं उससे संबंधित निविदा उपरान्त किसी प्रकार के पत्राचार स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निविदादाता के निविदा उपरान्त पत्रो को भी शून्य एवं प्रभावहीन माना जायेगा। (प्रधान कार्यालय उ.रे. नयी दिल्ली का पत्र सं. **74-W/O/Pt.XXV/WA/Loose Dated : 07.04.2015**

2653/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

NORTHERN RAILWAY

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/टीआरडी/हजरतगंज, मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई निविदा सूचना संख्या	टीआरडी-07-सीनि.डी.ई.ई.-लखनऊ-25-3कॉल				
कार्य का नाम	लखनऊ मंडल के लखनऊ गुड्स यार्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के प्रावधान के संबंध में ओएचई संशोधन कार्य।				
अनुमानित लागत	₹ 89,29,421.82	बयाना राशि	₹ 1,78,600.00/-	कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 माह
निविदा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तथा खोलने की तिथि	दिनांक 30.09.2025 को 15:00 बजे तक तथा खुलने का समय उसी दिन 15:00 बजे के बाद।				
प्रस्ताव की वैधता	निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन।				
उत्तर रेलवे की वेबसाइट	अतिरिक्त सूचना उत्तर रेलवे की बेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर चेक की जा सकती है।				
पत्रता मापदण्ड	निविदाकर्ता तब तक निविदा डालने योग्य नहीं है, जब तक कि वह निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरा नहीं करता: **1.** निविदाकर्ता का न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार वी/एन या 'वी' जो भी कम हो होना चाहिए; जहां **वी**=निविदा का विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में **एन**=कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। **2.** निविदाकर्ता पिछले सात वित्तीय वर्ष (निविदा के आमंत्रित करने के एक महिने पहले के अन्तिम दिन तक) य "कम से कम एक समान प्रत्येक तीन कार्य का **30** प्रतिशत न्यूनतम विज्ञापित राशि का कार्य किया हो" या "कम से कम एक समान प्रत्येक दो कार्य का **40** प्रतिशत न्यूनतम विज्ञापित राशि का कार्य किया हो" या "कम से कम एक समान एक कार्य का **60** प्रतिशत न्यूनतम विज्ञापित राशि का कार्य किया हो"। एक समान कार्य की परिभाषा होगी: **Similar work means design, supply, erection, testing & commissioning of 50 Hz, Single Phase 25 KV AC OHE.** **3.** निविदाकर्ता अपने आफर के साथ बिजली के ठेकेदारों के वैध लाइसेंस की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य जमा करें।				

नोटः इस निविदा के लिए किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव नजरअंदाज/ खारिज कर दिया जाएगा। पूर्ण विवरण बेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है ।

सं.: टीआरडी-07-सीनि.डी.ई.ई.-लखनऊ-25-3कॉल दिनांक: 02.09.2025

2660/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

स्टेट रोलबॉल प्रतियोगता में लखनऊ की लड़कियों ने मचाया धमाल

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में चल रही स्टेट रोलबाल चैम्पियनशिप सफलता पूर्वक संपन्न हो गई, जिसमे लखनऊ की लड़कियों ने जूनियर और मिनी वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर विजेता का खिताब हासिल किया। जूनियर वर्ग लड़कों का खिताब आगरा व मिनी का जीबी नगर ने जीता। मुख्य अतिथि उत्तर रोलबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार त्यागी और विशिष्ट अतिथि अनुराग मिश्रा 'अन्नू', वरिष्ठ प्रचारक कृपा शंकर ने विजेताओं को ट्राफी और मैडल प्रदान किए।

रोलबाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ लखनऊ के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि स्टेट रोलबाल प्रतियोगिता में लखनऊ की अंडर 17 में लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले सेमीफाइनल में लखनऊ ने मुरादाबाद को 9- 0 से हराया, जिसमे काव्या ने 4 और आद्या ने गोल किये थे। फिर फाइनल में भी काव्या के 3 और आराध्या के 2 गोल के सहारे आगरा को 5- 4 के करीबी अंतर से मात दी। गोल कीपर परनिका वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 11 मिनी वर्ग गर्ल्स में भी लड़कियो ने पहले सेमीफाइनल में गाजियाबाद को 7- 0 से हराया फिर फाइनल में जी बी नगर को एकतरफा मैच में 5- 0 से हराकर खिताब हांसिल किया। लखनऊ की अरु, काव्या, आराध्या, ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। लखनऊ की लड़कियों ने जीत का श्रेय कोच नीरज श्रीवास्तव व मुस्कान को दिया। डीपीएस गोमतीनगर विस्तार लखनऊ के कोच नीरज श्रीवास्तव और सचिव रोलबॉल लखनऊ मंजू श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा, खेल के हर क्षेत्र में लखनऊ के खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया फिर चाहे वो गोलकीपरिंग हो या डिफ़ेन्स या अटैकिंग का मौका हो। उत्तर प्रदेश रोलबाल के सचिव संतोष श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष रविन्द्र कपिल, लखनऊ रोलबॉल के आदित्य बाजपेई, प्रकाश मिश्रा, गौरव साहनी, अनुपेंद्र, मनीष वर्मा, डॉ अभय, लक्ष्मी, डॉ मनोज पाठक, नफीस अहमद, रामगोपाल सिंह, मनोज तिवारी, अनंत, अभिषेक, अफजल, मुकेश, ऋषि, पंकज, प्रज्ज्वल, मंशुल, ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।

पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्ज़ा और आधुनिक नगरीय परिवहन व्यवस्था के लिए सरकार प्रतिबद्ध : शर्मा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश सरकार जनहित को केंद्र में रखकर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्ज़ा और आधुनिक नगरीय परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़े और ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में नगर विकास एवं ऊर्ज़ा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने आज कैबिनेट बैठक के उपरांत जानकारी दी कि प्रदेश में नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर आधारित इलेक्ट्रिक बसों का शीघ्र संचालन प्रारंभ किया जाएगा। इस परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट जनपद कानपुर नगर, लखनऊ एवं उनके समीपवर्ती प्रमुख कस्बों में लागू किया जाएगा। मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत निजी ऑपरेटरों द्वारा लखनऊ एवं कानपुर नगर में 10-10 मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक चयनित निजी ऑपरेटर को अपने निर्धारित मार्गों पर ही बस संचालन की अनुमति होगी और उस रूट पर किसी अन्य निजी ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था व्यवस्थित संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।उन्होंने बताया कि इस अनुबंध की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष की होगी। इस अवधि में चयनित निजी बस ऑपरेटर ही बसों की खरीद, निर्माण, आपूर्ति, अनुरक्षण (मेंटेनेंस) एवं अन्य अवसंरचना की स्थापना करेंगे। इसके अतिरिक्त किराया संग्रहण की संपूर्ण जिम्मेदारी भी निजी ऑपरेटर की होगी। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस मॉडल में किराया एवं टैरिफ शुल्क निर्धारण की जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह दरें समझौते की शर्तों के अनुरूप तय की जाएंगी ताकि यात्रियों को सुविधाजनक एवं किफायती परिवहन उपलब्ध हो सके। साथ ही परिवहन विभाग एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ/आरटीए) से आवश्यक रूट लाइसेंस प्राप्त कर निजी ऑपरेटरों को विशिष्ट मार्गों पर बसें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम केवल एक परिवहन व्यवस्था का विस्तार नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं जनहित से जुड़ी एक क्रांतिकारी पहल है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जहां आम नागरिकों को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण रहित यात्रा सुविधा मिलेगी, वहीं प्रदेश में स्वच्छ ऊर्ज़ा और हरित तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नगरों को सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी की ओर अग्रसर करना है। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर इसे अन्य नगरों एवं महानगरों में भी विस्तारित किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन और हरित ऊर्ज़ा को बढ़ावा देने के संकल्प के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से न केवल नवीन रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। निजी ऑपरेटरों की सक्रिय भागीदारी से सरकार के वित्तीय बोझ में भी कमी आएगी और बेहतर गुणवत्ता की सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध होंगी। मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है कि जनता को सुरक्षित, सुलभ, सस्ती एवं प्रदूषण रहित परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाए।

चरक चौराहे की रूपरेखा बदलेगी, जाम से मिलेगी राहत

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। राजधानी का चरक चौराहा, जो लंबे समय से ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, अब नए रूप में नजर आएगा। नगर निगम ने इस चौराहे की रूपरेखा बदलने की योजना बनाई है। मंगलवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर यातायात सुधार के लिए कई दिशा-निर्देश दिए। चरक चौराहा शहर का प्रमुख जंक्शन है, जहां केजीएमयू और चौक क्षेत्र से आने वाला भारी ट्रैफिक रोजाना जाम की स्थिति पैदा करता है। नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान कहा कि मौजूदा रोटरी जाम का मुख्य कारण है। इसलिए रोटरी को शिफ्ट कर वाहनों की आवाजाही सुचारू करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने पैदल यात्रियों की सुविधा को भी प्राथमिकता दी। नगर आयुक्त ने चौराहे पर सुरक्षित पाथवे बनाने के निर्देश दिए, ताकि सड़क पार करने में लोगों को परेशानी न हो। खासकर केजीएमयू आने वाले मरीजों और तीमारदारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। चौराहे की नई डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता को सौंपी गई है। साथ ही, चौराहे पर मौजूद नाले को कवर करने के लिए ब्रिज कॉरपोरेशन को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने मलबा देखकर नाराजगी जताई और तत्काल साफ कराने के आदेश दिए। नगर निगम का दावा है कि इन सुधारात्मक कदमों से चरक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ते मिलेंगे और हजारों लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।

जमीनी विवाद को लेकर मारपीट जान से मारने की धमकी

पीड़ित ने एसीपी से लगाई गुहार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नगराम, लखनऊ । नगराम थाना क्षेत्र के करोरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद मारपीट का मामले ने तूल पकड़ लिया दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसीपी रजनीश वर्मा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगराम थाना क्षेत्र के करोरा निवासी हरिराम गौतम बीते 27 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे टहलने के लिए करोरा से नगराम रोड की ओर निकले थे। जब वह नहर के पुल के पास पहुंचे तो वहीं गांव के ही विपक्षी भुइयादीन भी साइकिल से पहुंच गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद के चलते भुइयादीन ने हरिराम गौतम को घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की शुरू कर दी।पीड़ित का कहना है कि भुइयादीन ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा और धमकी भी दी कि यदि उसने अपनी जमीन पर से आपत्ति नहीं हटाई तो किसी दिन जान से मार देगा। इस विवाद का मुकदमा पहले से ही तहसीलदार मोहनलालगंज न्यायालय में विचाराधीन है।हरिराम गौतम ने बताया कि जमीन को लेकर भुइयादीन उनसे लगातार रंजिश रखता है। और आए दिन झगड़े की स्थिति पैदा करता है। इस बार गाली-गलौज और मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी दिए जाने से वह व उनका परिवार बेहद भयभीत है। पीड़ित ने एसीपी रजनीश वर्मा को शिकायती पत्र देकर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वही एसीपी ने नगराम थाना प्रभारी विवेक चौधरी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर जांच कर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करिए वही नगराम थाना प्रभारी ने जांच कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी है।

किसान नेता अनमोल तिवारी ने निजी खर्च से कराईं जल निकासी

लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के अतरौली गांव में जल निकासी न होने से लोगों का जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया है, किसान समेत ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी न होने से घरों के आसपास पानी जमा हो रहा है जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं किसानो एवं ग्रामीणो का आरोप है कि एक निजी प्लाटिंग कम्पनी के द्वारा सड़क बना कर जल निकासी की समस्या बढ़ा दी गई है, जिससे जन जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। मंगलवार को परेशान ग्रामीणों ने अपनी व्यथा किसान नेता भाकियू (लोकतांत्रिक) के प्रदेश सचिव अनमोल तिवारी से बताई , किसान नेता अनमोल तिवारी दर्जनों किसानों के साथ आनन–फानन में मौके पर पहुंचे और अपने निजी खर्च से औपचारिक जल निकासी की व्यवस्था कराई, तब जाकर ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी जाहिर हुई। किसान नेता अनमोल तिवारी ने कहा कि पानी निकासी व्यवस्था समुचित नहीं हुई तो सैकड़ों किसान प्रदर्शन करने को बाध्य होने पर मजबूर होंगे।

सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफ़ेयर द्वारा कोबरा सर्प का किया गया रेसक्यू

लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। बेज़ुबान की आवाज़ बन कर कार्य कर रहा सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफ़ेयर द्वारा बोरवल मे फंसे कोबरा सर्प को जान जोखिम मे डालते हुए उसका रेसक्यू किया गया और उसे वहां से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया जिससे ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। आपको बता दे कि सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफ़ेयर को फोन पर कोमल यादव द्वारा सूचना दी गई कि उनका खेत जो कि इटौंजा रायपुर राजा सीतापुर रोड में है वहां उस खेत मे बने बोरवेल के चैम्बर में जो कि लगभग 30फुट गहरा है उसमे कोई सांप है जो की तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहा है जिससे काफी डर का माहौल बना हुआ है। इसकी सूचना पर सर्प रक्षक अनूप और मुकेश दोनों सर्प रक्षक रेस्कयू करने घटना स्थल पर पहुंचे जहाँ खतरा बहुत था फिर भी जो हो सका वो सुरक्षा उपाय किया और ये भी कन्फर्म किया कि बोरवेल में अक्सीजन है या नहीं संतुष्ट होने पर रेसक्यू किया गया तो वो आवाज़ सर्प कोबरा की थी जो काफ़ी बड़ा और काला था दोनों सर्प रक्षको ने वहां के लोगों ने जानकारी दी और जागरूक भी किया और उसको सुरक्षित स्थान पर आज़ाद कर दिया गया।

यूपी एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी को लुधियाना से गिरफ्तार किया

लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) नोएडा इकाई ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इनामी बदमाश बदायूं जिले में एक रिश्तेदार की हत्या में वांछित चल रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ राजकुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि एसटीएफ नोएडा इकाई टीम ने सोमवार देर रात लुधियाना के साहनेवाल से 50 हजार के इनामी शशांक बजाज को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त बीए पास है और पीलीभीत के ग्राम जोगीपुर निवासी है। उसने बदायूं में परिवारिक रिश्तेदार सुभाष शर्मा की रंजिश के चलते बीती एक मई 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद वह अपने पिता को लेकर देहरादून भाग गया। इस दौरान उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर देहरादून पुलिस जेल भेज दिया था। कुछ साल बाद शशांक को पीलीभीत जेल में स्थानांतरण कर दिया गया। 2019 में वह बीमारी की वजह से पीलभीत जिला अस्पताल में भर्ती हुआ और वहां से चकमा देकर फरार हो गया। तब से पुलिस उसे तलाश कर रही थी। पुलिस महानिरीक्षक आईजी रेंज ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ ने अग्रिम कार्रवाई के लिए अभियुक्त को पीलीभीत पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।

शैलचित्रों के संरक्षण के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और पुरातत्व निदेशालय के मध्य हुआ समझौता

लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में मंगलवार को पर्यटन निदेशालय गोमतीनगर में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र नई दिल्ली के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह समझौता ज्ञापन भारतीय कलाओं, साहित्य, नृत्य, संगीत, नाटक तथा दृष्य कलाओं के अनुसंधान एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग, भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का एक साझा ढांचा तैयार करना है, ताकि संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 273 स्मारकों/पुरास्थलों संरक्षित है।

एलडीए ने बीकेटी, गुड़म्बा और सैरपुर में ध्वस्त की पांच अवैध प्लाटिंग

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। एलडीए ने मंगलवार को अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-4 और जोन-5 की टीमों ने बीकेटी, गुड़म्बा और सैरपुर क्षेत्रों में अभियान चलाकर 5 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। प्रवर्तन जोन-4 की जोनल अधिकारी संगीता राघव के अनुसार, सैरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलहरी में जयसीम उर्फ मिर्ज़ा द्वारा 8 बीघा और विष्णु अग्रवाल व अन्य द्वारा 2 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। दोनों ही प्लाटिंग बिना ले-आउट स्वीकृति के की जा रही थी, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। वहीं, प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि बीकेटी क्षेत्र में शगुन सिटी प्रबंधक द्वारा ग्राम भाखामऊ में करीब 25,000 वर्गमीटर और मो. शकील व अन्य द्वारा ग्राम राजपुर (रिंग रोड के पास) में 5,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसके अलावा गुड़म्बा थाना क्षेत्र के ग्राम पैकरामऊ में गार्डेन होमेज के खालिद व अन्य ने एसबीआई बैंक बेहटा शाखा के सामने लगभग 30,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध कालोनी विकसित कर रखी थी। इन तीनों स्थानों पर भी एलडीए टीम ने बुलडोजर चलाकर प्लाटिंग ध्वस्त कर दी।

उमर खालिद मामले का फैसला न्यायिक कम राजनीतिक ज़्यादा है : शाहनवाज़

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। कंग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उमर खालिद, शरजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत अन्य मुस्लिम युवकों का दिल्ली दंगों के मामले में ज़मानत ख़ारिज कर दिए जाने को न्यायिक फैसले के बजाये राजनीतिक फैसला बताया है। शाहनवाज़ आलम ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने बेल नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत का मज़ाक उडाने वाला फैसला देकर न्यायालय पर बढ़ते राजनीतिक दबाव को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपने फैसलों में कह चुका है कि यूएपीए जैसे मामलों में भी बेल नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने उमर खालिद और अन्य छात्रनेताओं को किसी अन्य द्वारा बनाए गए वाट्सएप ग्रुप के ऐसे सदस्य होने जिसने कभी कोई मैसेज भी नहीं किया जैसे सतही आरोपों में बिना बेल के 5 साल से कैद कर रखा है। जबकि दिल्ली दंगे के असली दोषियों दिल्ली पुलिस के अधिकारियों, आरएसएस और भाजपा नेताओं को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न तो ऐसा करने में विफल रहने पर न्यायपालिका ने कोई सख़्ती ही दिखाई। शाहनवाज़ आलम ने कहा कि जब कॉलेजियम वरिष्ठता क्रम में 57 वें नंबर पर रहने वाले सरकार समर्थक जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन देगा तो निचली अदालतों के जजों में न्यायिक के बजाये सरकार को ख़ुश करने वाले राजनीतिक फैसले देने का चलन और दबाव बढेगा। उमर खालिद और अन्य के मामले में आया फैसला ऐसा ही उदाहरण प्रतीत होता है उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देश देख चुका है कि 'गोली मारो सालों को' जैसे हत्या के लिए उकसाने वाले नारे लगाने के बावजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दिल्ली हाईकोर्ट के जज सीडी सिंह ने यह कहते हुए बरी कर दिया था कि ये नारे उन्होंने मुस्कुराते हुए लगाए थे इसलिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

पी.एम आवास दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, एफआईआर दर्ज

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना में जालसाजों ने 18 लोगों से लाखों रुपये ठग लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित आवंटन पत्र लेकर आवास कब्जे की मांग को एलडीए पहुंचे। जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। जन समस्या निवारण संस्थान के चेयरमैन आलोक दुबे द्वारा की गई शिकायत पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जांच कराई। इसमें सामने आया कि अलीनगर, मदेयगंज निवासी मोहम्मद तालिब नामक व्यक्ति ने खुद को एलडीए का प्रशासनिक अधिकारी बताकर आवास दिलाने का झांसा दिया। उसने प्रति व्यक्ति 55,000 रुपये और फिर 1,10,000 रुपये की किश्तें वसूल कर जाली रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और आवंटन पत्र थमा दिए। पीड़ितों के अनुसार तालिब ने यूपीआई के माध्यम से करीब 26 लाख 40 हज़ार रुपये वसूले, लेकिन न तो एग्रीमेंट कराया और न ही किसी को आवास का कब्जा दिलाया। बाद में एलडीए जांच में पाया गया कि तालिब नाम का कोई कर्मचारी प्राधिकरण में कार्यरत ही नहीं है। प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्र और चालान फर्जी पाए गए। उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि डालीबाग में बनाए जा रहे 72 ईडब्ल्यूएस भवनों का पंजीकरण अभी खोला भी नहीं गया है, लेकिन जालसाजों ने इसमें भी फर्जी आवंटन पत्र बना दिए। हजरतगंज स्थित वीआईपी गेस्ट हाउस के पास झुग्गी में रहने वाले राहुल धानुक के नाम से भी जाली दस्तावेज तैयार किए गए। इस संबंध में गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। एलडीए ने आम जनता से अपील की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आवंटन को लेकर किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा न करें। प्राधिकरण भवन में गठित पीएमएवाई सेल ही इस योजना से संबंधित मामलों की जानकारी और प्रक्रिया का प्राधिकृत कार्यालय है। भवनों का आवंटन केवल लॉटरी प्रक्रिया से ही किया जाता है।

योगी सरकार का उच्च शिक्षा में बड़ा कदम

तीन विश्वविद्यालयों में 948 नए पदों को मंजूरी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

- 468 अस्थायी शिक्षणेतर और 480 आउटसोर्सिंग पदों पर भर्ती करेगी योगी सरकार
- शैक्षिक गुणवत्ता में भी होगी वृद्धि और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के तीन नवगठित विश्वविद्यालयों-गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (मुरादाबाद), मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय (मीरजापुर) और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय (बलरामपुर) में कुल 948 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसमें 468 अस्थायी शिक्षणेतर पद और 480 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन पदों के सृजन से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और कार्यात्मक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूपी बढ़ रहा आगे

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा

कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह निर्णय विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने के साथ-साथ प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार स्पष्ट किया है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा और रोजगार दोनों उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विश्वविद्यालयों में नए पदों का सृजन इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जो उच्च शिक्षा को सशक्त और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में 156 अस्थायी शिक्षणेत्तर पद सृजित किए गए हैं, जो 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे और आवश्यकतानुसार समाप्त भी किए जा सकते हैं। इन पदों में फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, अवर अभियंता, आशुलिपिक, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, वैयक्तिक सहायक, लेखाकार, प्रधान सहायक, चिकित्साधिकारी और स्टाफ नर्स जैसे पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया से की जाएगी।

इसके अलावा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में 160 पद वाह्य सेवा प्रदाता (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से पूरे किए जाएंगे, जिससे कुल 480 पद बनते हैं। इनमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छकार, चौकीदार, माली, चपरासी, वाहन चालक और पुस्तकालय परिचर जैसे पद शामिल हैं। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, श्रम विभाग और कार्मिक विभाग की ओर से जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी नियुक्तियों में आरक्षण से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य होगा।

आपसी सद्भाव के साथ मनायें त्योहारः एसडीएम

बैठक में क्षेत्र के कई दर्जन हिन्दू, मुस्लिम धर्मावलंबियों के अलावा तमाम संभ्रांत लोग शामिल हुए

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बिसवां,सीतापुर। आगामी बारावफात एवं दशहरा त्योहारों के मद्देनजर सदरपुर थाना परिसर में मंगलवार को उपजिलाधिकारी महमूदाबाद की अध्यक्षता में एक पीस कमेटी की बैठक आहूत की गई जिसमें क्षेत्र के कई दर्जन हिन्दू, मुस्लिम धर्मावलंबियों के अलावा तमाम संभ्रांत लोग शामिल हुए। इस बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

बैठक में थाना क्षेत्र के उन स्थानों की चर्चा हुई जहां 12 रबी उल अव्वल के कार्यक्रम होते हैं या दशहरा पर्व मनाया जाता है। इन दिनों क्षेत्र में चल रहे गणेश महोत्सवों के स्थानों के बारे में भी जानकारी ली गई। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि त्योहार हमें आपसी सद्भाव बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। खुशी के साथ त्योहार मनायें लेकिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे माहौल खराब हो। उन्होंने कहा मोबाइल के व्हाट्सएप अथवा सोशल मीडिया पर इसी प्रकार की उत्तेजित टिप्पणियां न की जायें। इस बारे में कहीं भी कोई तनाव की स्थिति देखें तो पुलिस को अवगत करायें। क्षेत्र में शांति बनाए रखें। उप जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले आगामी त्यौहारों को आपसी हेलमेल भाईचारे व खुशी के साथ मनायें। कोई भी नई परम्परा न शुरू करें। त्योहार हम सबको खुशी का संदेश देते हैं। त्योहार हम सबको खुशी का संदेश देते हैं। कभी किसी के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। मोबाइल सेटों पर कोई भी व्यक्ति धर्म अथवा राजनीति को लेकर गलत कमेंट्स न करे। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार के अलावा उपनिरीक्षक दिलीप कुमार सिंह व अन्य उपनिरीक्षकों के अतिरिक्त कई आरक्षी व क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान, बीडीसी, अनेक हिन्दू मुस्लिम धर्मावलम्बी एवं संभ्रांत लोग उपस्थिति थे।

सीतापुर में 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान में 76 बाइक सवारों का चालान

सीतापुर। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में ''नो हेलमेट, नो फ्यूल'' अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में, सीतापुर के जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनंद के आदेश पर एक विशेष जांच अभियान में कई विभाग शामिल हुए । इस अभियान के दूसरे दिन, विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों ने शहर के कई पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण किया।इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल न ले सकें। जांच टीमों में जिला पूर्ति अधिकारी, परिवहन विभाग, बांट माप विभाग और यातायात पुलिस के अधिकारी शामिल थे। परिवहन विभाग की टीमों ने एआरटीओ (प्रशासन) सर्वेश चतुर्वेदी और यात्री कर अधिकारी एम.ए. अहमद के नेतृत्व में हेलमेट नहीं पहनने वाले बाइक चालकों पर कड़ी कार्रवाई की।जांच के दौरान, टीमों ने बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए 76 बाइक चालकों को रोककर उनका चालान काटा। एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि यह अभियान अगले 30 दिनों तक जारी रहेगा और इसका मुख्य मकसद लोगों की जान बचाना है।

शिक्षण कार्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित

कैनविज टाइम्स संवाददाता

कमलापुर, सीतापुर। आज दिनांक 2 सितम्बर 2025 दिन मंगलवार को आदरणीय बी0एस0ए0 सर के आदेशानुसार भिन्न भिन्न श्रेणियों में 12 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग में उनके द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का बी0आर0सी0 परिसर में आयोजन किया गया। विकास क्षेत्र कसमंडा से 12/694 बराबर 1.5% शिक्षको को सम्मानित किया गया। मुझे काजल द्विवेदी,प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बलोइया,कसमंडा, सीतापुर यू डायस कोड 09240607701* का चयन करने हेतु सम्मानित खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री अजय गुप्त मौर्य, समस्त ए0आर0पी0, शिक्षक संकुल,विद्यालय के समस्त परिवार तथा अपने शुभचिंतकों और परिवार जनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सम्मानित सभी शिक्षकों ने हृदय से कोटि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

बाघ के ख़ौफ़ से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

दहशत फैला रहा बाघ,वनविभाग पकड़ने में नाकाम, ग्रामीणों में रौष,केवल कॉम्बिंग तक सीमित है वन विभाग

कैनविज टाइम्स संवाददाता

महोली/सीतापुर। जनपद सीतापुर की कोतवाली महोली क्षेत्र के अंतर्गत इन दिनों बाघ का आतंक फैला हुआ है। आमजनमानस ख़ौफ़ में जीने को मजबूर है।स्कूली बच्चे विद्यालय नही जा पा रहे हैं।किसान खेतो में जाने से डर रहे हैं। बीते महीने तहसील महोली के नरनी गांव में एक युवक की मौत बाघ के द्वारा शिकार करने से हो गयी। जिसके बाद बसारा गांव में एक किसान जंगली जानवर का शिकार हो गया।मंगलवार की सुबह कारीपाकर गांव के मजरा मिर्ज़ापुर में गांव के बाहर बंधी गाय पर बाघ ने अपने कुनबा सहित हमला कर दिया जिससे गाय गम्भीर रूप से घायल हो गयी। गाय बांधने गयी महिला ख़ौफ़नाक मंजर देखकर हतप्रभ रह गयी। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गये। जिसके बाद बाघ कुनबे सहित गन्ने में छिप गया। मौके पर वन विभाग की टीम कॉम्बिंग के लिए पहुँची।लगातार हो रही घटनाओं को लेकर क्षेत्र के लोग भयभीत हैं जिसके चलते काँग्रेस प्रवक्ता सुधांशू बाजपेयी ने अपनी टीम के साथ उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौपते हुए जल्द ही क्षेत्र को बाघ से भयमुक्त कराने के लिए कहा।

किराए पर मकान ले चला रहा सेक्स रैकेट, मकान मालिक ने पुलिस से लगाई गुहार

गोरखपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के खड़ेसरी निवासी सुनील सोनकर से होटल चलाने हेतु किराए पर मकान लेकर होटल संचालक अब उसमें सेक्स रैकेट चला रहा है। मना करने पर जान माल की धमकी दे रहा है। पीड़ित मकान मालिक ने पुलिस से गुहार लगाई है।

सोमवार को बड़हलगंज थाने पर दिए तहरीर में पीड़ित मकान मालिक सुनील सोनकर ने लिखा है कि खड़ेसरी एहतमाली में आ नम्बर 761 (ख) में एक मकान उसने बैनामा लिया है जिसमें होटल चलाने के लिए एक व्यक्ति उस मकान को मुझसे किराए पर लिया। अब वह होटल न चला वहां सेक्स रैकेट चला रहा है जिससे मेरी पूरे क्षेत्र में बदनामी हो रही है। खाली करने को कहने पर मुझे जाति सूचक शब्दों से गालियां देता है और जान माल की धमकी दे रहा है। पीड़ित मकान मालिक सुनील सोनकर ने किराएदार के विरुद्ध मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग किया है।

बालाजी हॉस्पिटल में हुई महिला की दर्दनाक मौत

परिजनों की का विरोध देखकर डॉक्टर और संचालक फरार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखीमपुर खीरी। एक बार फिर अवैध अस्पताल की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। रामापुर के बालाजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान नकहा कस्बा की एक महिला की मौत हो गई है। यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था में छुपे गंभीर संकट को उजागर करती है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के कथित डॉक्टर और संचालक घटना के बाद हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हो गए, जिससे हादसे की भयावहता और बढ़ गई है।मृतका के पति ने न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मामले की सुनवाई करने को कहा। डीएम के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। शव को जिलामहिला चिकित्सालय में सुरक्षित रखा गया है।इस गंभीर मामले ने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अवैध अस्पतालों की बढ़ती संख्या और उनमें हो रही लापरवाही मरीजों की जान को ख़तरे में डाल रही है। आम लोगों में अस्पतालों की असलियत को लेकर भारी असंतोष और भय व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार इतनी गंभीर घटना के बाद ही कार्रवाई हो पाती है, जबकि यदि समय रहते इन अवैध अस्पतालों पर नज़र रखी जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे काले धंधों को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए, जिससे मरीज सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो।यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई और उनकी मार्मिक स्थिति की गवाही है, जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या व्यवस्था में सुधार के लिए अब और इंतजार किया जा सकता है? मरीजों की जान की हिफाज़त को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि ऐसे दुखद हादसे पुनः न हों।

खमरिया सीएचसी पर सीडीओ का छापा, मचा हड़कंप

अस्पताल अंधेरे में डूबा, डॉक्टर-स्टाफ गायब, अधीक्षक से जवाब-तलब, वेतन कटेगा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखीमपुर खीरी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मंगलवार को उस समय उजागर हुई जब सीडीओ अभिषेक कुमार ने खमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। पहुंचते ही सीडीओ हैरान रह गए। पूरा परिसर अंधेरे में डूबा था। न लाइट, न जनरेटर। करीब आधे घंटे मशक्कत के बाद जब जनरेटर चला तो मालूम हुआ उसमें ईंधन ही नहीं डाला गया था। साफ हो गया कि बिजली जाने पर अस्पताल कभी जनरेटर पर नहीं चलता।सीडीओ सीधे अधीक्षक के कक्ष में पहुंचे तो पता चला कि वे आवास पर आराम फरमा रहे हैं। इस दौरान 09 चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ भी गायब मिले। सीडीओ ने अधीक्षक का स्पष्टीकरण तलब करते हुए अनुपस्थित कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने और चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार ने पाया कि बीते दो दिनों में हुई डिलीवरी की महिलाएं और नवजात वार्ड में मौजूद ही नहीं थे। जबकि नियम के अनुसार प्रसव के बाद 48 घंटे तक जच्चा-बच्चा को चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाना और भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। और तो और, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली जीरो डोज वैक्सीन तक नहीं लगाई गई थी। सीडीओ ने इसे घोर लापरवाही करार देते हुए सख्त नाराजगी जताई।निरीक्षण में सीडीओ ने पाया कि जांच लैब की छत से पानी टपक रहा था। हालात यह थे कि कीमती जांच मशीनें प्लास्टिक से ढककर रखी गई थीं। इससे मरीजों की जांच की सुविधा प्रभावित हो रही थी। सीडीओ ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और चिकित्सालय भवन की मरम्मत के लिए सीएमओ को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।*गंदगी, जलभराव और बंद शौचालय*अस्पताल परिसर में गंदगी, सीलन और जलभराव ने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत खोल दी। प्रतीक्षालय की जगह दवाओं के बक्से रखे मिले। सीडीओ ने सख्त निर्देश दिए कि दवाओं को स्टोर में रखा जाए और प्रतीक्षालय को मरीज व परिजनों के उपयोग में लाया जाए। तीन शौचालयों में से दो बंद और एक गंदगी से भरा मिला। सीडीओ के औचक निरीक्षण ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी।

नगर पंचायत के द्वारा वसूले जा रहे टैक्स को लेकर जनता में आक्रोश

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सिंगाही खीरी। राज्य सरकार के द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम में जलकर, गृह कर, व्यवसाय कर तथा तमाम प्रकार के अन्य करों में की गई एक से 15 गुना अधिक वृद्धि को लेकर कस्बे के प्रबुद्ध जनों व आम नागरिकों में बड़ी खलबली मच गई है और सोशल मीडिया पर जमकर नगर पंचायत के द्वारा वसूले जा रहे तमाम करो को लेकर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त है। कस्बे के लोगों को कहना है कि करो में की गई 15% की वृद्धि देने में सिंगाही की जनता असमर्थ है। क्योंकि वह अपनी जीविका चलाने के लिए पलायन कर पड़ोस के प्रदेशों में पलायन कर मेहनत मजदूरी करती है। जिससे उनको दो जून की रोटी नसीब होती और करो में की गई वृद्धि का जिम्मेदार नगर पंचायत प्रशासन को मान रहे हैं जबकि नगर पंचायत प्रशासन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के शासनादेश पर करो में वृद्धि कर वसूली की जा रही। सिंगाही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एसडीएम निघासन भी शासनादेश के अनुसार ही नगर पंचायत के करो की वसूली की जाने की बात कह रहे हैं। कस्बे में टैक्स करो में की गई बढ़ोतरी पर आम जनमानस में काफी आक्रोश है और जगह-जगह पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्षमता से अधिक करो की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से यह जनता पर अधिक भार का बोझ है। इस संबंध में सिंगाही ईओ/एसडीएम निघासन राजीव निगम ने बताया की सिंगाही नगर पंचायत के द्वारा शासन से बताई गई गाइडलाइन के आधार पर वसूला जा रहा है और टैक्स में किसी प्रकार से जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओ में टैक्स वृद्धि के लिए शासनादेश जारी किया है और टैक्स वृद्धि से नगर पंचायत बोर्ड का कोई लेना-देना नहीं है न ही कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी नगर पंचायत अध्यक्षों ने बढ़े हुए टैक्स को लेकर नाराजगी व्यक्त करने के लिए यूपी नगर विकास मंत्री से मुलाकात कर टैक्स कम करने की मांग की गई थी लेकिन उन्होंने इसमें कोई जनहित में रहता नहीं दी है।

लखीमपुर में फिर उजागर हुई मौत की दुकान

लखीमपुर खीरी। कोतवाली सदर क्षेत्र के रामापुर के बालाजी हॉस्पिटल में लापरवाह ऑपरेशन से महिला की मौत हो गयी। घटना के बाद हॉस्पिटल संचालक व कथित डॉक्टर हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हो गये। जारनकारी के मुताबिक पीड़िता नकहा कस्बे की रहने वाली थी। वही गमगीन परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से लगाई इंसाफ की गुहार। डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर भेजी गई है। फिलहाल शव जिला महिला चिकित्सालय में रखा गया है। सवाल उठता है कि लखीमपुर में कब तक ऐसे अवैध अस्पताल लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे।

शारदानगर पुलिस की दबिश में वारण्टी अभियुक्त हरिकेशन गिरफ्तार

शारदानगर, खीरी। जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान के तहत आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना शारदानगर पुलिस ने 2 सितंबर 2025 को वारण्टी अभियुक्त हरिकेशन पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम रमनगरी, थाना शारदानगर को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने त्वरित और सराहनीय कदम उठाया।गिरफ्तारी के बाद हरिकेशन को आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु न्यायालय भेज दिया गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक ऋषिराज पांडेय और कांस्टेबल करन कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून का खौफ और अपराधियों में दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि जनपद में अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।

बाढ़ से प्रभावित परिवारों से संवाद कर एडीएम ने दिलाया हरसंभव मदद का भरोसा

पलिया खीरी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नरेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील पलिया के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। वे एसडीएम डॉ. अवनीश कुमार के साथ नाव द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, लंच पैकेट वितरित किए और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।एडीएम ने भानपुर खजुरिया, आजाद नगर, बर्बाद नगर, श्रीनगर मेला घाट और अतरिया गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और राहत कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया।बाढ़ प्रभावित आजाद नगर में एडीएम ने खुद मोटर बोट पर सवार होकर पहुंच कर स्थानीय दिक्कतों को समझा और अधिकारियों को तेज राहत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ चौकियों और चिकित्सा कैंपों का भी निरीक्षण किया और स्वास्थ्य टीमों को प्रभावित परिवारों के द्वार-द्वार जाकर स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण उपलब्ध कराने के आदेश दिए। एडीएम ने कहा कि बाढ़ में संक्रामक बीमारियों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए हर व्यक्ति तक दवाई और टीका पहुंचाना आवश्यक है।प्रशासन की सतत कोशिश है कि किसी भी परिवार को राहत से वंचित न रखा जाए और सभी तक समय पर सहायता पहुंचाई जाए। प्रशासन प्रभावितों के साथ लगातार संपर्क में है और सभी जरूरी कदम उठा रहा है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके।

1143,200 परीक्षार्थी 6-7 सितंबर को देगें पीईटी परीक्षा, प्रशासन ने कसी कमर

लखीमपुर खीरी। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (पीईटी) आगामी 6 और 7 सितंबर को जिले के 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 43,200 परीक्षार्थी भाग लेंगे। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में एडीएम (न्यायिक) अनिल कुमार रस्तोगी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए। एडीएम ने कहा कि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशन में परीक्षा को पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ सम्पन्न कराया जाएगा, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।परीक्षा दो पालियों में होगी–पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक।

महिलाओं ने कबड्डी मैच में निघासन को हराकर ददेरी ने जीता

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सिंगाही खीरी। बावन द्वादशी के मौके पर कस्बे में चल रहे प्रो कबड्डी टूर्नामेंट में बारिश के कारण दो मैच खेले गए।प्रो कबड्डी टूर्नामेंट के तीसरा दिन मंगलवार को सभासद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ कराया। पहला मैच बाला जी नौरंगाबाद व बेलरायां के मध्य खेला गया। इस टूर्नामेंट में बाला जी नौरंगाबाद 63/14 विजयी रही। दूसरा महिला मैच दरेरी वर्सेज निघासन के बीच खेला गया। इस मैच में दोनों टीमो के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। दरेरी की टीम ने मैच को 30/40 पॉइंट से जीत हासिल की। तीसरा पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट खैरीगढ़ एकेडमी और प्रधानपुरवा के बीच खेला गया। खेल पहले हाफ में खैरीगढ़ एकेडमी केवल दो अंक प्राप्त किए। वहीं प्रधानपुरवा की टीम ने चौदह अंक हासिल किए। उसके बाद बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ा। कमेटी के अध्यक्ष साहनी ने बताया कि आज मंगलवार को दस बजे से क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। इस दौरान कमेटी के सदस्य व खेल प्रेमी मौजूद रहे।

घास लेने गये युवक की संदिग्ध अवस्था मे कटी गर्दन

गर्दन कटने पर युवक की हालत हुई गंभीर,जिला अस्पताल रेफर

कैनविज टाइम्स संवाददाता

निघासन खीरी। घर से खेत में घास लेने गए एक किशोर की संदिग्ध हालत गर्दन में गर्दन कट गई, खेत में बच्चे को तड़फता देख स्थानीय लोगों ने उसे आनन फानन में नजदीकी हॉस्पिटल सीएचसी निघासन पहुंचाया, जहां के डाक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल से एंबुलेंस तक ले जाने के लिए किशोर को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, पुलिस वाले उसे लादकर एंबुलेंस तक ले गए।किशोर की पहचान विक्रम पुत्र रामगोपाल निवासी चखरा थाना कोतवाली निघासन के रूप में हुई है। चखरा गांव के रहने वाले बाल गोविंद शर्मा ने बताया कि हम लोग पास के ही खेत में काम कर रहे थे, तभी गन्ने के खेत से चिल्लाने की आवाज आई तो हम लोग अंदर पहुंचे वहां देखा तो इस लड़के की गर्दन कटी थी।लोगों ने कहा कि बाघ ने हमला किया है पर वहां पर जानवर के पद चिन्ह नहीं थे, बल्कि इंसानों के पदचिन्ह थे। लड़के के पिता बच्चे की हालत देखकर बेहोश हो गए, किशोर के पिता रामगोपाल राजवंशी ने बताया कि वह बीमार रहते हैं उनका बेटा ही घास लेने जाता है, आज सुबह घर से 9:00 बजे वह गांव के पास ही एक गन्ने के खेत में घास लेने गया था, दोपहर बाद उनको सूचना मिली कि उनके बेटे की गर्दन कट गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाघ का हमला है लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता उनके बेटे की गर्दन कैसे कटी है।डॉ अरविंद पटेल ने बताया कि कुछ ग्रामीण एक किशोर को अस्पताल में लेकर आए थे जिसकी गर्दन कटी हुई थी, उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र ने बताया कि गन्ने के खेत में घसीटने के निशान मिले हैं प्रथम दृष्टया जानवर का हमला लगता है जांच की जा रही है।

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में निर्यातकों की बैठक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बैठक में निर्यातकों द्वारा अपने-अपने जनपदों से देश-विदेश में हो रहे निर्यात को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव मण्डलायुक्त मुरादाबाद के साथ साझा किए गए।

निर्यातकों ने बताया कि अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ से हस्तशिल्प इकाईयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे निर्यातकों के अत्याधिक आर्डर होल्ड पर हैं तथा नए ऑर्डर मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

मुरादाबाद । मण्डलायुक्त श्री आञ्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मण्डल के सभी जनपदों के प्रमुख निर्यातकों के साथ आयोजित बैठक के दौरान विदेश में निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में सुझाव एवं विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निर्यातकों द्वारा अपने-अपने जनपदों से देश-विदेश में हो रहे निर्यात को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव मण्डलायुक्त मुरादाबाद के साथ साझा किए गए।

जनपद मुरादाबाद के निर्यातकों ने बताया कि अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ से हस्तशिल्प इकाईयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे निर्यातकों के अत्याधिक आर्डर होल्ड पर हैं तथा नए ऑर्डर मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इससे जनपद में रोजगार पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसके साथ ही निर्यातकों द्वारा इनकम टैक्स सब्सिडी, कच्चा माल खरीदने में 10 प्रतिशत सब्सिडी और फ़ेयर सब्सिडी में बढ़ोत्तरी कराए जाने का आग्रह भी किया गया। निर्यातकों ने बताया कि अन्य विभागों से अधिकारी फैक्ट्रियों का सर्वे करने आते हैं जिनसे इकाईयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है साथ ही उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि डीआईसी को सिंगल विंडो के माध्यम से एवं डीआईसी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सर्वे आदि कराया जाना उचित होगा। इसके साथ ही जनपद बिजनौर के डिवीजनल चैयरमैन आईआईए द्वारा प्रदेश में विगत कई वर्षों से कार्यरत सैकड़ों गुड़ एवं खंडसारी औद्योगिक इकाईयों के हित में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2023 का प्रभावी क्रियान्वयन कराकर इन इकाईयों को मण्डी शुल्क एवं विकास शुल्क की देयता से मुक्त रखने हेतु एवं उद्योग को मण्डी शुल्क के बोझ से राहत देने हेतु पैराई सत्र 2023-24 व 2024-25 की लंबित समाधान योजना को लागू कराने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही बिजनौर में लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय से अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पर्यटन इकाईयों की स्थापना में नीति सीमा क्षेत्र को लेकर उत्पन्न हो रहे अवरोध को दूर करने का भी आग्रह किया गया।रामपुर के निर्यातकों ने मैंथॉल पर 50 प्रतिशत टेरिफ को लेकर कहा कि इससे जनपद के रोजगार में कमी आयी है तथा जनपद का निर्यात घटा है तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निर्यातकों ने कहा कि फ़ेट एण्ड लॉजिस्टक सब्सिडी को बढ़ाया जाये।मण्डलायुक्त द्वारा सभी निर्यातकों की समस्याएं और सुझावों को सुनने के बाद उसका समाधान कराने का आश्वासन दिया गया तथा मण्डलायुक्त ने निर्यातकों को अमेरिका के साथ-साथ अन्य देशों के साथ भी निर्यात बढ़ाने तथा हस्तशिल्प के डिजाइनों में न्यू इनोवेसन पर ध्यान देने के लिए कहा। इसके साथ ही निर्यातकों द्वारा जल भराव की समस्या एवं 100 बेड ईएसआई हॉस्पिटल तथा बिजली से सम्बन्धित समस्याओं के विषय में भी मण्डलायुक्त को अवगत कराया गया।बैठक का संचालन श्री योगेश कुमार संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा किया गया तथा मण्डल के उपायुक्त उद्योग भी बठक में मौजूद रहे। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री योगेश कुमार के सतह ही श्री रचित अग्रवाल मै. गिफ्ट इन्टरनेशनल मुरादाबाद, श्री आशीष सिंह गिफ्ट इंटरनेशनल मुरादाबाद, श्री मौहम्मद अजमल मै. मार्क इम्पैक्स मुरादाबाद, श्री राजीव बंसल मै. सेन्सस लाइफ स्टाइल्स मुरादाबाद, श्री संचित गुप्ता आईआईए चैयरमैन रामपुर, श्री अमित कपूर रामपुर, श्री अरविन्द नन्दा डायरेक्टर मै. मेन्था एण्ड एलाइड प्रोडेक्ट रामपुर, श्री अरविन्द अरौरा मै. अरोरा एरोमेटिक्स सम्भल, श्री कमल कौशल वार्ष्णेय मै. नील कंठ एन्टरप्राइजेज सम्भल, श्री आशुतोष रस्तोगी मै. एनएस मिन्ट प्रोडक्टस प्रा. लि. सम्भल, श्री विकास कुमार अग्रवाल डिविजनल चैयरमैन आईआईए बिजनौर, श्री अवनीश कुमार अग्रवाल चैप्टर चैयरमैन आईआईए बिजनौर, श्री विनय भार्गव अमरोहा, श्री पंकज विश्नाई अमरोहा आदि निर्यातक उपस्थित रहे।

भाकियू द्वारा जिलापूर्ति कार्यालय का घेराव, डीएम को ज्ञापन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

भकियू ने राशन वितरण विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि राशन में घटतौली और शिकायतों का निस्तारण न होना अधिकारियों की आदत बन गयी है

बदायूं। भारतीय किसान यूनियन असली गैर राजनीतिक ने भ्रष्टाचार को लेकर जिला पूर्ति कार्यालय पर जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल जिसका संचालन जसवीर सिंह यादव वकील साहब ने किया। अध्यक्षता स्वयं जिला अध्यक्ष केपीएस राठौर ने की । जिला सचिव सूरजपाल सिंह ने कहा कि जनपद की सभी तहसीलों पर पूर्ति इंस्पेक्टर और राशन कोटेदारों की मिली भगत से जनता का हक छीना जा रहा है। और राशन का आवंटन सही तरीके से नहीं किया जाता पूरे जनपद में घटतौली हो रही है। पूरा राशन नहीं दिया जाता है। जिसकी आगे में प्रति कोटेदार से प्रसिद्ध दुकान तीन हजार रुपये इंस्पेक्टर द्वारा दिए जाते हैं। पैसा प्राइवेट आदमी के द्वारा लिया जाता है। जॉन वाइस पैसा इकट्ठा किया जाता है। जिला उपाध्यक्ष हरीश पटेल ने कहा विभाग शासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। शासनादेश के मुताबिक राशन डीलर वितरण प्रमाण पत्र जो सचिव द्वारा प्रमाणित होता है। जिससे पता लगता है कि कितना राशन बात और कितना शेष गोदाम में रहा किन-किन लोगों को राशन बांटा गया। वह हर बार हर महा जाम होता है। लेकिन कोई दुकानदार जमा नहीं करता इसी में के लोग मनमानी खेल खेलते हैं। शेष राशन भेज दिया जाता है।

अधिकारी वितरण प्रमाण पत्र के बारे में नहीं पूछते वह पूछते हैं। कितना राशन बच्चा और बचा या नहीं अभी तक पैसा नहीं आया। उन्होंने कहा नगर पंचायत ककराला सखानू असिस वरखिन सिकरोड़ी, रमजानपुर लबरी कठुलिया जोड़ी नगला गंगी नगला काना नगला एवं शिवायः हामिदपुर आदि दुकानों पर प्रीत यूनिट एक किलो राशन कम और अंत्योदय कार्डों पर पैतीस किलो से तीस किलो प्रीत यूनिट कम दिया जाता है। जिससे बदले में इंस्पेक्टर को मोटी कमाई आती है। जसवीर यादव वकील साहब तहसील अध्यक्ष उन्होंने धरने की कार्रवाई को आगे बढ़ते हुए कहा जब तक वितरण वाली मशीन महीने के अंत तक बंद नहीं हो जाती तब तक राशन का वितरण होना चाहिए। कोटेदारों का एक कंाटा मशीन से जो कनेक्ट होता है। जिससे पर्ची निकलती है किसी भी व्यक्ति का अंगूठा लगाकर उसे मशीन के ऊपर एट पत्थरों का वजन रखते हैं उसके बाद पर्ची लगती है। और फिर स्टोर में जहां राशन मिलता है। दूसरा कंाटा रखा है उसे पर्ची के हिसाब से वह कंाता सेट किया हुआ है। वजन करके उसे राशन दे दिए जाता है जो निर्धारित मात्रा से कम राशन होता है। सूर्य प्रताप यादव ने कहा की गोदाम से ट्रांसपोर्टर ठेकेदार राशन को डोर टू डोर पहुंचने का पैसा एवं पल्लेदारी का पैसा सरकार से लेते हैं ठेकेदार खुद ना जाकर अपने प्राइवेट लड़कों को भेजता है जो रास्ते में गाड़ियां खड़ी करते हैं और वहीं से राशन का वितरण शुरू कर देते हैं

जिलाधिकारी ने सीएम युवा योजना की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक

बैंकों को नियमानुसार ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश

कैनविज टाइम्स संवाददाता

मुरादाबाद । जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मुख्यमंत्री युवा योजना की प्रगति को लेकर विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री योगेश कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों को 3377 आवेदन पत्र भेजे गए थे जिसके सापेक्ष अब तक कुल 759 लाभार्थियों को ही ऋण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में योजना के अंतर्गत मात्र दो माह में बैंकों द्वारा 665 आवेदन पत्रों का निस्तारण हुआ था जिसके सापेक्ष वर्ष 2025-26 में 5 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अब तक तुलनात्मक रूप प्रगति में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं ऋण वितरण में बैंकों की प्रगति अत्यंत धीमी है।जिलाधिकारी ने इस संबंध में सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं बैठक में मौजूद बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन 5 से 6 ऋण आवेदन स्वीकृत करके वितरण करें। जिन बैंकों में अत्यधिक संख्या में आवेदन निरस्त किए गए हैं, वे निरस्त आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए सूची उद्योग विभाग को उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रगति को लेकर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी तथा लंबित प्रकरणों और निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की स्थिति की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करने के संबंध में भी उन्होंने संयुक्त आयुक्त उद्योग को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

कोषागार बिल्डिंग का होगा जीर्णोद्धार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

कोषागार कार्यालय अस्थाई रूप से तहसील सदर में होगा शिफ्ट

तहसील सदर में कक्ष संख्या-15, 17, 18 और दो अन्य कक्षों का कोषागार के शासकीय कार्यों के लिए जिलाधिकारी ने किया आवंटन

मुरादाबाद । कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित कोषागार कार्यालय को अस्थाई तौर पर तहसील सदर परिसर में स्थानांतरित करने के संबंध में जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं।जिलाधिकारी ने बताया कि कोषागार कार्यालय मुरादाबाद की बिल्डिंग में पुनर्निर्माण/मरम्मत से संबंधित कार्य कराए जाने हैं। पुनर्निर्माण एवं मरम्मत अवधि के दौरान कोषागार कार्यालय स्तर से संपादित होने वाले कार्यों को निर्बाध रूप से संपादित कराने के उद्देश्य से कोषागार कार्यालय को तहसील सदर मुरादाबाद के प्रथम तल पर कक्ष संख्या-15, कक्ष संख्या-17, कक्ष संख्या-18 और दो अन्य कक्षों को कोषागार के शासकीय कार्यों के लिए आवंटित कर दिया गया है। मुख्य कोषाधिकारी रेनू बौद्ध ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कोषागार बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने तक कोषागार कार्यालय तहसील सदर परिसर में संचालित होगा। तहसील सदर में कार्यालय शिफ्ट करने का कार्य करीब 20 सितंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के उपरांत कोषागार कार्यालय को पुनः विभागीय बिल्डिंग में स्थानांतरित किया जाएगा।

प्रत्येक संस्थान में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य : जिलाधिकारी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम हेतु डीएम ने उठाया कदम

बदायूँ। जिलाधिकारी अवनीश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘‘महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एंव प्रतितोष) अधिनियम-2013 अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में जनपद स्तर के एसे प्रत्येक शासकीय, अर्द्धशासकीय एंव अशासकीय (निजी) विभाग, सगंठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, शाखा अथवा यूनिट में जहाँ कार्मिको की सख्या 10 या 10 से अधिक है, ऐसे सभी कार्यालयों के नियोजको द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की जाँच हेतु आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना है। यदि किसी नियोजक द्वारा अपने कार्यस्थल में नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समिति का गठन नही किया गया है तो नियोजक पर रु0 50,000/-पचास हजार रू0 तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है और यह दण्ड नियोजक पर दूसरी बार अधिरोपित दण्ड से दुगने दण्ड का दो गुणा हो जायेगा।उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्यवाही शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से सम्बन्धित सभी सांविधिक निकायो यथा-डॉक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टड एकाउन्टेन्ट, आय-व्यय, लेखक, इन्जीन्यर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञ को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजो प्रशिक्षण केन्द्रो और शैक्षणिक सस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों व नसिंग होम्स आदि के द्वारा भी की जाए।उन्होंने कहा कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एंव प्रतितोष अधिनियम-2013 अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में जनपद स्तर के सभी समस्त शासकीय, अर्द्वशासकीय एवं निजी कार्यालयों, संस्थाओं, निकायों, उपक्रमों, परिषदों एवं बोर्ड इत्यादि मे आन्तरिक परिवाद समिति का गठन जनपद के कार्यालयों में कराते हुए सभी आन्तरिक परिवाद समिति का गठन जिसमें महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4(2) के अन्तर्गत कार्यालय में तैनात पीठासीन अधिकारी-कार्यस्थल/अन्य व्यवस्थापक इकाइयों/कार्यालयों/संगठनों से वरिष्ठ महिला कर्मचारी। कार्यालय में कम से कम 02 सदस्य महिलाओं के लिये कार्य करने मे प्रतिबद्ध/समाज कार्य में अनुभव/कानूनी ज्ञान, बाहरी 01 सदस्य महिलाओं के लिये कार्य करने मे प्रतिबद्ध/समाज कार्य में अनुभव/कानूनी ज्ञान। उपरोक्त संरचना में आधी सदस्य महिलायें होगी।उन्होने निर्देश दिए कि ऐसे प्रत्येक शासकीय, अर्द्धशासकीय एव अशासकीय (निजी) विभाग, सगंठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, शाखा अथवा यूनिट में जहाँ कार्मिको की सख्या 10 या 10 से अधिक है।

बीज के लिये नि:शुल्क मिनी किट का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक

मुरादाबाद। जिला कृषि अधिकारी डा0 राजेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित ल्लराज्य सहायतित निःशुल्क चना, मटर एवं मसूर बीज मिनीकिट वितरण प्रदर्शन एवं प्रचार कार्यक्रम 2025-26 योजना के अंतर्गतल्ल दलहनी फसल, जिसमें चना 16 किग्रा, मटर 20 किग्रा एवं मसूर 8 किग्रा मात्रा के बीज की मिनीकिट निःशुल्क प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल थद्दन्द्धदथन्पद्धथद्ध.पक्.द्दधफ.द्धद्ध पर पंजीकृत कृषक 25 सितम्बर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन करने वाले कृषकों को चना, मटर एवं मसूर बीज मिनी किट आवेदन अवधि में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। एक कृषक को केवल एक मिनीकिट प्राप्त हो सकेगी। चयनित कृषकों को ई पॉस मशीन के माध्यम से संबंधित विकास खण्ड के राजकीय कृषि निवेश बीज भण्डार से चना, मटर एवं मसूर बीज की मिनी किट वितरित की जाएगी। इच्छुक कृषक निःशुल्क चना, मटर एवं मसूर बीज मिनी किट प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल https://gridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन 25 सितम्बर 2025 तक कर सकते हैं।

नशीला पदार्थ खिलाकर धोखे से बैनामा कराने का आरोप, एसएसपी से शिकायत

अनूपशहर। गांव राजौर में दबंग ने ग्रामीण को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर धोखे से 3 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया। ग्रामीण की पत्नी ने दबंग के विरुद्ध एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। क्षेत्र के गांव राजौर निवासी दबंग मनजीत पुत्र गिरिराज ने गांव के ही योगेश को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर धोखे से उसकी डेढ बीघा कृषि भूमि का 19 जुलाई को धोखे से अपनी बहन निधि पत्नी अरविंद निवासी गांव डबका थाना अहमदगढ़ के नाम बैनामा करा दिया। इसी प्रकार 13 अगस्त को निधि के नाम दोबारा डेढ बीघा भूमि का बैनामा करा दिया। बैनामा के बदले में आरोपी मनजीत ने एक्सिस बैंक का ?6 लाख का चेक दिया। उपरोक्त चेक को उसके पति को बैंक ले जाकर समस्त धनराशि निकाल कर अपने साथ ले गया। इस संदर्भ में रिंकी पत्नी योगेश निवासी गांव राजौर ने एसएसपी बुलंदशहर को पत्र देकर अवगत कराया है, कि उसका एक बेटा दिव्यांग तथा दूसरा भी बेरोजगार है। वह इस कृषि भूमि के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। जमीन को दबंगों द्वारा धोखाधड़ी करके कब्जा लिए जाने के बाद उसके सामने पेट भरने की समस्या पैदा हो रही है। प्रार्थना पत्र में रिंकी ने यह भी अवगत कराया है, कि इस संदर्भ में मनजीत से बात करने पर उसने किसी से जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी है। मनजीत जिला बदल होने के साथ अपराधी मानसिकता का है। रिंकी के प्रार्थना पत्र पर अनूपशहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायती पत्र में प्रशांत पुत्र रतन लाल निवासी मोहल्ला मदारगेट को भी दोषी बताया गया है। इस संदर्भ में योगेश के भाई भारतीय किसान यूनियन के नेता वीरेंद्र सिंह चोपड़ा ने उचित कार्रवाई न होने पर पलायन की चेतावनी भी दी है।

महिला अस्पताल के लॉन्ड्री हाउस पर संविदा कर्मियों का अवैध कब्जा

बदायूं। शहर का जिला महिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है इस बार मामला लॉन्ड्री हाउस पर दो संविदा कर्मियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे का है। बताते चलें की दो संविदा कर्मियों (इनमें से एक हेल्प डेस्क पर कार्यरत है) द्वारा लॉन्ड्री हाउस पर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा किया जा हुआ है। इतना ही नहीं उन्होंने वहां पर अवैध निर्माण कार्य भी कराया है। दोनों संविदा कर्मचारी राजनीतिक सरपरस्ती के चलते उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि नवागत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने दूरभाष पर हुई वार्ता में कैनविज के सम्वाददाता को बताया कि उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से सात दिन के अंदर उक्त परिसर को खाली करने का निर्देश जारी किया था जिसमें अन्यथा की स्थिति में वेतन कटौती सहित अनुशासनिक कार्यवाही अमल मेँ लाए जाने का निर्देश भी दिया था लेकिन समाचार लिखे जाने तक दोनों मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए लॉन्ड्री हाउस पर काबिज थे।

युवा दिवस पर सघन एड्स जागरुकता अभियान का आगाज

बदायूं। राजकीय डिग्री महिला महाविद्यालय घंटाघर बदायूं में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सघन एड्स जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु एक गोष्ठी का आयोजन प्राचार्या डॉ0 वंदना की अध्यक्षता में किया गया। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी (एड्स) डॉ विनेश कुमार द्वारा जनपद में एच आई वी/ एड्स होने के चार कारण असुरक्षित यौन सम्बन्ध,एच आई वी ग्रस्त महिला से होने वाले उसके बच्चे, एच आई वी ग्रस्त व्यक्ति का ब्लड दूसरे को चढ़ाने, एच आई वी से संक्रमित व्यक्ति की सिरिंज से दूसरे को इंजेक्शन लगाने से फैलता है इसी प्रकार बच्चों को जागरूक किया गया कार्यक्रम मेँ उपस्थित काउंसलर श्रीमती सुषमा सिंह ने पीपीटीसीटी द्वारा बताया गया कि अगर कोई एचआईवी संक्रमित महिला है तो उसका प्रसव डॉक्टर की देख रेख में ही होनी चाहिए इसी तरह एसटीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए सभी को जागरूक किया गया एवं। लोक स्मृति सेवा संस्थान बदायूं के प्रोग्राम मैनेजर शनि दुवे द्वारा बताया गया कि सही जानकारी ही सही बचाव है। एवं उनकी संस्था द्वारा चल रहे प्रोग्राम जैसे एफ एस डब्लू, एम एस एम, ड्रग यूजर्स जैसे उच्च जोखिम समूहों पे एचआईवी/एआईडीएस विषय पर जागरूक कर रोक थाम एवं, जाँच, बचाव, इलाज के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया द्य कार्यक्रम का संचालन रोहित सक्सेना प्रोग्राम मैनेजर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में में अर्चना पांडे, डॉ सतीश कुमार, डॉ बृजेश कुमार, डॉ भावना सिंह, एवं सरिता गौतम इत्यादि शिक्षक उपस्थित रहे।

विद्यालय में किया गया अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन

बदायूं। महर्षि महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों की पी.ए. द्वितीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को उनके अभिभावकों के समक्ष दर्शाया गया एवं बच्चों के प्रदर्शन व्यवहार और शिक्षा के बारे में चर्चा की गई। जिसमें अभिभावकों द्वारा भी पूर्ण सहभागिता निभाई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य के. के. वर्मा जी के द्वारा अभिभावकों की समस्याओं का निवारण किया गया। विद्यालय में महर्षि भावातीत ध्यान योग शिविर का भी आयोजन हुआ। जिसमें ध्यान एवं सिद्धि शिक्षक कुशल कांत राठौर एवं वंदना पाण्डे द्वारा सभी अभिभावकों को योग का महत्व बताते हुए योग, ध्यान के लिए प्रेरित किया गया तथा अभिभावकों को बताया गया कि बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों को भी ध्यान एवं योग करना आवश्यक है। इस प्रकार यह संगोष्ठी अभिभावकगण तथा अध्यापकगण के मध्य बच्चों की प्रगति को लेकर मार्गदर्शन करने में सहायक रही। इस अवसर पर संपूर्ण विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।

नगर पंचायत अध्यक्ष, ईओ, नोटरी व स्टांप वेंडर के खिलाफ मुकदमा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बदायूं। वजीरगंज नगर पंचायत में फर्जीवाड़े के आरोपों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन ईओ, नोटरी अधिवक्ता और स्टांप वेंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर पंचायत वार्ड नौ के सभासद सुमित वार्ष्णेय ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा करवाया है सभासद सुमित वार्ष्णेय का आरोप है कि उन्होंने 15 फरवरी 2025 को नगर पंचायत अध्यक्ष नूरसबा बेगम और तत्कालीन ईओ अखिलेश दीक्षित पर वित्तीय घोटालों की शिकायत जिलाधिकारी को दी थी। शिकायत की जानकारी होते ही आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर उनके नाम से फर्जी शपथपत्र तैयार करा लिया। इसमें उनके हस्ताक्षर भी कूटरचित तरीके से किए गए और नोटरी से प्रमाणित कराकर डीएम को प्रस्तुत किया गया, ताकि उनकी शिकायत को निरस्त कराया जा सके। सुमित वार्ष्णेय का कहना है कि डीएम कार्यालय से प्राप्त पत्र के जरिए उन्हें इस फर्जीवाड़े का पता चला। जब उन्होंने इस मामले में थाने और एसएसपी से शिकायत की तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसलिए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मोहम्मद तौसीफ रज़ा ने इसे गंभीर मानते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन ईओ, नोटरी अधिवक्ता और स्टांप वेंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। नगर पंचायत अध्यक्ष बोली, आरोप निराधारनगर पंचायत अध्यक्ष नूरसबा बेगम का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। कहा कि पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उनकी छवि को धूमिल करने और राजनीतिक साजिश के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।

पनीर की सब्जी में मिला था चूहा, जांच करने पहुंची टीम तो ढाबा संचालक भागा

बदायूँ। पनीर की सब्जी में चूहा मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को टीम जांच करने पहुंची तो ढाबा बंद मिला। इसलिए वह टीम खाद्य पदार्थों का सैंपल भी नहीं ले सकी है। यह मामला कुछ दिन पुराना है।बिल्सी नगर के बिसौली-कासगंज बाईपास मार्ग पर गल्ला मंडी के पास स्थित मुस्कान ढाबा पर कुछ दिन पहले नगर निवासी व्यापारी निशांत माहेश्वरी अपने दोस्त के साथ खाना खाने गए थे। खाने के अंतिम चरण में उसकी पनीर की प्लेट में चूहा निकलने पर हड़कंप मच गया। व्यापारी ने वीडियो बना लिया और ढाबा पर शोर मचाने लगा। बाद में इसकी कोतवाली से पुलिस से शिकायत भी की। कुछ लोगों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा लिया। जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन में सक्रिय हो गया। सोमवार को सहायक आयुक्त खाद्य सीएल यादव के नेतृत्व में वहां टीम पहुंची लेकिन ढाबा बंद कर भाग गया।

बारिश में भी निकला मोहर्रम का आख़िरी जुलूस

सम्भल/असमोली। विकासखंड के ग्राम बुकनाला सादात में सोमवार को आठ रबी उल अव्वल के अवसर पर तेज़ बारिश के बीच मोहर्रम का तारीखी व आख़िरी जुलूस निकाला गया। भारी बारिश के बावजूद अकीदमंदों की बड़ी संख्या इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुई। जुलूस की शुरुआत इमामबाड़ा साहेबुज़मान से हुई, जो मजहरे कर्बला से होता हुआ इमामबाड़ा बनी हाशिम पहुंचकर सम्पन्न हुआ। इस दौरान इमामबाड़ों व घरों से काले अलम हटाए गए।इमामबाड़ा मजहरे कर्बला पर आख़िरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ? का ताबूत शबीह के रूप में सजाया गया। अकीदमंदों ने गुलाब के फूल चढ़ाकर पुरसा दिया और दुआएँ मांगीं। जुलूस में अलम, शबीहे ताबूत, ऊंट की अमरिया व झूला भी बरामद किए गए। विभिन्न अंजुमनों ने नौहा-ख़्वानी और मातम कर इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों को ख़िराजे अकीदत पेश किया। इस धार्मिक जुलूस में सभी समुदायों के लोगों ने शिरकत कर भाईचारे का संदेश दिया।

डीएम ने निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के लिये राजनैतिक दलों के साथ की बैठक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों से अपील की कि आगामी पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाने हेतु प्रत्येक मतदेय स्थल पर बी.एल.ए. (बूथ लेवल एजेन्ट) की नियुक्ति सुनिश्चित करें तथा बी.एल.ए. की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराए

बदायूँ। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के संबंध में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि आयोग द्वारा मतदाताओं को सहज, सरल एवं सुलभ मतदान अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मतदेय स्थलों का सम्भाजन कराया जाता है। इस वर्ष भी आयोग ने निर्देशित किया है कि मतदेय स्थलों के निर्धारण में किसी परिवार का विभाजन न हो, एक ही भवन अथवा गली में रहने वाले मतदाता एक ही अनुभाग में सम्मिलित हों तथा किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े और न ही किसी प्राकृतिक बाधा को पार करना पड़े। उन्होंने राजनैतिक दलों से अपील की कि आगामी पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाने हेतु प्रत्येक मतदेय स्थल पर बी.एल.ए. (बूथ लेवल एजेन्ट) की नियुक्ति सुनिश्चित करें तथा बी.एल.ए. की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके नाम फार्म-6 भरवाकर निर्वाचक नामावली में जोड़े जाएँ। इसी प्रकार 24 वर्ष या उससे अधिक आयु के अर्ह मतदाताओं के नाम भी सुनिश्चित रूप से सम्मिलित कराए जाएँ।बैठक में यह भी अनुरोध किया गया कि निर्वाचक नामावली में छूटे हुए योग्य मतदाताओं विशेषकर युवा एवं महिला मतदाताओं को जोड़ने, तथा मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटवाने हेतु फार्म-7 भरवाने में सभी दल सक्रिय भूमिका निभाएँ। अन्त में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार में सहयोग प्रदान करने हेतु सभी राजनैतिक दलों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 वैभव शर्मा सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश,समय से कार्यालय न आने पर होगी कार्रवाई

मण्डलायुक्त द्वारा विभिन्न कार्यालयों केनिरीक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण किया गया। इस दौरान लापरवाही उजागर हुई और कुल 17 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोंडा। देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील के द्वारा पूर्वान्ह 10:30 बजे के करीब विद्युत विभाग, गोंडा के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण किया गया। इस दौरान लापरवाही उजागर हुई और कुल 17 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।आयुक्त के निरीक्षण में कार्यालय मुख्य अभिय न्ता (वितरण) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए।इसी प्रकार कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,विद्युत वितरण में दो कर्मचारी, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम में सात कर्मचारी तथा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय में दो कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिले।कुल मिलाकर एक अधिकारी और 16 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के बाद सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अनुपस्थित पाए गए स भी अधिकारी-कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह सख्त कदम विभागीय अनुशासन और का र्य संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपू र्ण माना जा रहा है।आयुक्त ने सभी अधिकारि यों और कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुं चने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि शा सन स्तर से भी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थि ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।इसके बावजूद यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सम य से उपस्थित नहीं होता है,तो उसका स्पष्टीकर ण मांगा जाएगा और आवश्यकतानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त ने साफ कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सरकारी कार्यों में देरी से जनता को असुविधा होती है, इसलिए सभी कर्मचारियों को समयपालन को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है।उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को भी निर्देशित किया है कि उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अनुपस्थित या देर से आने वाले कार्मिकों के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।इससे प्रशासनिक का र्यकुशलता और जनता को मिलने वाली सेवा ओं में सुधार होगा।

गौतमबुद्ध नगर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा

गौतमबुद्ध नगर । यमुना नदी मे लगातार बढ़ रहे जलस्तर से गौतमबुद्ध नगर के तटीय इलाकों में बने फार्म हाउस में पानी घुस गया है। मंगलवार को दोपहर बाद जिलाधिकारी मेधा रूपम ने भारी पुलिस बल के साथ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए कैंप में जाकर उनसे उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर जिला प्रशासन लगातार स्थितियों पर नजर रखे हुए है। लोगों को चेतावनी जारी किया है कि वे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से निकलकर, बाढ़ पीड़ितों के रहने के लिए बनाए गए केंद्र में पहुंच जाएं। जिलाधिकारी ने अपने मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए कैंप में बिजली, पानी और खाने पीने की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से जाकर उनका हाल-चाल भी पूछा।आज शाम तक यमुना का जलस्तर बढ़कर पुस्ता तक पहुंच गया है। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों को डूब क्षेत्र से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाने को कहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि डूब क्षेत्र में स्थित जिन गांवों और फार्म हाउस में पानी भर गया है, वहां रहने वाले लोगों को और मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है।

जंगलों के बीच सफलता की कहानी लिख रहीं हैं समूह की दीदियां

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बहराइच । यह कहानी है बहराइच जनपद मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर विकासखण्ड मिहीपुरवा के भारत-नेपाल सीमा एवं कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार के बीच बसे थारू जनजाति बाहुल्य गांव फकीरपुरी के प्रतिमा स्वयं सहायता समूह की दीदियों की। स्वयं सहायता समूह का गठन सितम्बर, 2018 में बिहार आजीविका मिशन से आई दीदियों ने किया था। इस स्वयं सहायता समूह में कुल 11 दीदियां जुडी जिसमें कुछ अलग करने की लगन थी। समूह में जुडने के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से इनकों रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रू. 15000 एवं सामुदायिक निवेश निधि के रूप में रू. 1,50,000 दिये गये।समूह की दीदियों से जब रोजगार एवं प्रशिक्षण के विषय में बात की गई तो इन लोगो ने अपने परम्परागत उत्पादों को बनाने एवं उसको अलग पहचान दिलाने में रूचि दिखाई। इसी कड़ी में वर्ष 2023 में विश्व प्रकृति निधि (डब्लूडब्लूएफ) के माध्यम

से 15 दिवस एवं वर्ष 2024 में 10 दिवस का परम्परागत उत्पाद जैसे डलिया जूट बैग, कैप, ह ै ड ब ै ग, टोकरी, रोटी बॉक्स एवं फूलदान बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त समूह की सभी दीदीयां जूट एवं जल कुम्भी से उपरोक्त सभी उत्पाद बना रही है। यह पर्यावरण के अनूकूल भी है। आज इस समूह की दीदियां स्वयं तो आत्मनिर्भर है। साथ ही अपने आस-पास के अन्य समूहों की दीदियों को भी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रहीं हैं। इस समूह की दीदियों द्वारा आज अपने उत्पाद की बिक्री कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार आने वाले पर्यटकों के अलावा अन्य स्थानों पर भी की जा रही है। सम्पूर्णता अभियान अन्तर्गत आडिटोरियम परिसर में भी समूह की दीदियों द्वारा स्टाल लगाकर अपने उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

जनपद में अब हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोण्डा। परिवहन आयुक्त,उत्तर प्रदेश एवं डीएम गोण्डा के निर्देशानुसार जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु एक विशेष अभियान ''नो हेलमेट, नो पेट्रोल'' प्रारंभ किया गया है।इस अभियान के अंतर्गत जिले के सभी पेट्रोल पम्प स्वामियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी दो पहिया वाहन चाल क या उसका सहयात्री बिना हेलमेट के पेट्रोल पम्प पर आता है,तो ऐसे वाहनों में किसी भी स्थिति में ईंधन की आपूर्ति न की जाए।शासन द्वारा यह भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जनपद एक सितंबर, से तीस सितंबर, तक नो हेलमेट न पेट्रोल अभियान चलाया है,ताकि लोगों में जागरूकता फैले।साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि जिले के समस्त पेट्रोल पम्प स्वामी अपने-अपने पेट्रोल पम्प प्रांगण में बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाकर इसके संबंध में लोगों को जागरूक करें।यह निर्णय प्रदेश में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं की संख्या एवं दो पहिया वाहन चा लकों की सुरक्षा को

दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।हेलमेट न केवल वाहन चालक की सुर क्षा सुनिश्चित करता है,बल्कि गंभीर चोट से भी बचाव करता है।अतः यह अनिवार्य है कि दो पहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठा सहयात्री दोनों हेलमेट धारण करें।

जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पम्प स्वामियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।साथ ही, परिवहन विभाग एवं पुलिस वि भाग की संयुक्त टीम द्वारा समय-समय पर पे ट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया जाएगा,तथा नि यमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पम्प के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए गी।जिला प्रशासन आम नागरिकों से अपील करता है कि वे स्वयं की सुरक्षा हेतु सदैव हेल मेट का प्रयोग करें एवं दूसरों को भी इसके लि ए प्रेरित करें।यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्व पूर्ण प्रयास है।परिवहन विभाग के द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प स्वामियों को इस अभि यान के संबंध में कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।आपकी सुरक्षा, आपका अधिकार है हेलमेट पहनिए, जीवन बचाइए।

प्राथमिकता के आधार पर हो समस्याओं का निस्तारण : वीरू साहनी

कन्नौज । उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के सभापति वीरू साहनी ने सर्किट हाउस सभागार में विभागीय अधिकारियों एवं समिति सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की।सभापति ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलों का भ्रमण कर यह देखा जा रहा है कि समितियाँ किस प्रकार कार्य कर रही हैं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सही ढंग से हितग्राहियों तक पहुँच रहा है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए और समिति की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एवं मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सभापति ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 60 प्रतिशत तथा पुरुषों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत इस वित्तीय 2024-25 में खोले गए पोर्टल पर प्राप्त 90 आवेदनों में से 65 पात्र पाए गए हैं।

17 को मनाया जाएगा भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिवस

तैयारी पूर्ण, आयोजक बोले, सनातन परम्परा के अनुसार होगी पूजा-अर्चना

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बहराइच। शहर के कठौवां दोनक्का स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर भगवान विश्वकर्मा के भक्तों की बैठक आगामी विश्वकर्मा जन्मोत्सव की तैयारी हेतु आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता मंदिर के संरक्षक एडवोकेट धर्मराज विश्वकर्मा ने की जबकि संचालन विपिन विश्वकर्मा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोकी विश्वकर्मा ने कहा कि आगामी 17 सितंबर को सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव सनातन परंपरा के अनुसार वैदिक रीति से पूजन अर्चन हवन एवं प्रसाद भंडारे के साथ होना सुनिश्चित हुआ। इस आयोजन को लेकर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। पूरे जनपद में

विश्वकर्मा भगवान का यह एकमात्र मंदिर है जिसमें विश्वकर्मा वंश के पांच पुत्रों के वंशजों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है क्योंकि यह स्थान ब्रह्मा जी की नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है एवं गंधर्व वन के रूप में वेदों में इसका वर्णन मिलता है ।बैठक का संचालन करते हुए विपिन विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा ने सनातन धर्मियों को समरसता का जो संदेश देने का कार्य किया है उससे समाज के सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति हीन भावना का दृष्टिकोण त्यागना चाहिए यही सनातन धर्म हमें सिखाता है। उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर को सृष्टि के रचयिता विराट विश्वकर्मा का जन्म उत्सव वैदिक रीति से संपन्न होगा। बताया कि भोर में सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का षोडशोपचार पूजन ,नवग्रह मंडल पूजन उपरांत विश्वकर्मा भगवान का दुग्ध,मधु,जल से अभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात फल फूल नैवेद्य एवं विभिन्न प्रकार के भोग भगवान विश्वकर्मा को अर्पित किए जाएंगे,एवं भगवान विश्वकर्मा के भक्तों एवं विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी मंदिर परिसर में किया जाएगा। इस अवसर पर बैठक में केसरी प्रसाद ,दयानंद शर्मा, नोखे लाल विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा,संत राम विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

विश्व हिंदू रक्षा परिषद का सदस्यता कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बहराइच समेत प्रदेश व देश में घट रही हिन्दुओं की संख्या पर चिंता जताई

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नानपारा, बहराइच। विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा नगर के बंधन मैरिज हॉल में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि बहराइच सहित देश और प्रदेश में घटती हिंदू जनसंख्या गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इंडो-नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में बाहरी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। राय ने जोर देकर कहा कि सरकार और समाज को इस दिशा में सतर्कता बरतनी चाहिए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मिथिलेश मिश्रा, महामंत्री राजेश तिवारी, उपाध्यक्ष दिनेश वर्मा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष दीपा शर्मा, विमल लक्ष्मी देवी सहित तहसील और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को संगठन से जोड़ा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता जिले के विभिन्न इलाकों की जनसंख्या रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे ताकि ठोस रणनीति बनाई जा सके।इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश आर्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए सतत कार्य करने का संकल्प लिया।

कालपी बस स्टैंड पर हुई हिंसा का मास्टरमाइंड माजिद गिरफ्तार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

उरई। उत्तर प्रदेश के जनपद उरई में बीती 29 अगस्त को कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर हुई आगजनी और हिंसा की वारदात के मास्टरमाइंड माजिद को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से फरार चल रहा माजिद लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था।पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने बताया कि 29 अगस्त को कालपी बस स्टैंड पर माजिद और उसके साथियों का एक ट्रैवलर एजेंसी के संचालक से विवाद हो गया। इस विवाद ने काफी हिंसक रूप ले लिया और माजिद के गुट ने एजेंसी संचालक की पिटाई कर दी। इसके बाद घटना स्थल पर खड़ी मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घटना का मास्टर माइंड माजिद फरार चल रहा था। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जे वाले एक फार्म हाउस सहित कई अवैध निर्माणों और ठिकानों पर प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया।

बारिश में मकान गिरने से परेशान परिवार, जाँच को पहुंचे अधिकारी

पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद का भरोसा व नुकसान का आकलन कर आर्थिक व आवास की सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया

कैनविज टाइम्स संवाददाता

महराजगंज, रायबरेली। विकास खंड महराजगंज के अंतर्गत टूक गांव में सोमवार रात हुई बारिश के कारण मुनव्वर अली का कच्चा मकान धराशायी हो गया। इस हादसे से परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वे अस्थायी स्थिति में रहने को मजबूर हैं।

सूचना मिलने पर मंगलवार को खंड विकास अधिकारी वर्षा सिंह सहित प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और मौके का जायजा कर। पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद का भरोसा व नुकसान का आकलन कर आर्थिक व आवास की सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। खण्ड विकास अधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि तहसीलदार से वार्ता की गई है पीड़ित परिवार को शासन द्वारा आपदा राहत कोष से मिलने वाली सहायता राशि यथाशीघ्र दिलाने की कार्यवाही शुरू करते हुए। गांव के दो पीड़ित परिवारों को भरण पोषण के लिए गौशाला से दो-दो गायें भी दी जाएंगी। इसके अलावा कोटेदार से पीड़ित परिवार को अतिरिक्त रासन भी दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सुनील मौर्य, व कई स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

भारत-नेपाल सीमा पर 10 ग्राम स्मैक के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार

नानपारा, बहराइच । भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक नेपाली तस्कर को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। यह अभियान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने के उद्देश्य से चलाया गया। 59वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट कैलाश चंद रमोला के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में ई समवाय बलाईगांव के पार्टी कमांडर उप-निरीक्षक अनामिका मेहरा एवं उनकी टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बॉर्डर पिलर संख्या 665 के पास नेपाल निवासी चानस ग्यावल (29), पुत्र राम बहादुर ग्यावल, ग्राम मधुबन, दुर्गापुर, जिला बर्दिया, नेपाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी भारत में तस्करी करने का प्रयास कर रहा था। गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मादक पदार्थ को थाना मोतीपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई से स्पष्ट है कि सीमा पर सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है। एजेंसियों ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा बलों को दें, ताकि अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके और समाज को सुरक्षित रखा जा सके।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे कोई बच्चा : चंद्रभूषण पाण्डेय

बीआरसी घुघली में शिक्षक संकुल बैठक संपन्न, निपुण ऐप, यू डायस और ड्राप आउट के संदर्भ में हुई चर्चा

खण्ड शिक्षा अधिकारी चंद्र भूषण पाण्डेय ने छात्र उपस्थिति बढ़ाने पर दिया जोर

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोरखपुर। बीआरसी घुघली के सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी चन्द्र भूषण पाण्डेय की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय शिक्षक संकुल की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में निपुण ऐप के माध्यम से छात्रों के आकलन पर विशेष ध्यान देकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने का निर्देश बीईओ ने देते हुए कहा कि शिक्षकों को प्रिंट रिच मटेरियल और टीएलएम का अधिक से अधिक उपयोग कर ब्लाक के प्रत्येक विद्यालय को शत प्रतिशत निपुण बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही मिशन लाइफ, स्पोर्ट्स क्लब, वॉच क्लब और रीडिंग क्लब की गतिविधियों पर भी चर्चा की गई।शिक्षकों ने विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ाने और अधिक से अधिक बच्चों का पंजीकरण कराने का संकल्प लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।बैठक में एआरपी बालमुकुंद सिंह, एआरपी अंग्रेजी उपेन्द्र मिश्र, शिक्षक नेता राजू सिंह, पवन पटेल, रिजवानुल्लाह खान, वीरेन्द्र यादव, अशोक सिंह, मनोज वर्मा, श्रीमती अंजना श्रीवास्तव, डॉ धनंजय मणि त्रिपाठी, जाकिर सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

परियोजनाओं के चिन्हित भूमि पर उपलब्ध परिसम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत करें विभाग : डीएम

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बहराइच । जनपद की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान खलीलाबाद बहराइच नई रेल लाइन निर्माण, जनपद बहराइच में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 के किमी 36.5 से किमी 101.540 तक चैड़ीकरणध्पेव्ड शोल्डर सहित 2/4 लेन निर्माण, सशस्त्र सीमा बल, 42वी वाहिनी की सीमा चैकी रूपईडीहा की स्थापना, जनपद बहराइच में लखनऊ-बहराइच मार्ग से बहराइच-गोण्डा मार्ग बाईपास का निर्माण तथा जनपद बहराइच में भारत-नेपाल राष्ट्र की सीमा के निकट बहुउद्देशीय हब के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिया कि अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर स्थापित परिसम्पत्तियों का वितरण एक सप्ताह में भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बहराइच को उपलब्ध करा दिया जाय। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद, अधिशाषी अभियन्ता लो.नि.वि. प्रा.ख. प्रदीप कुमार व निर्माण खण्ड-1 के अमर सिंह, जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चैधरी, एनएचएआई के प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

आरती के दौरान मांस फेंकने वाला आरोपी गया जेल

संकट मोचन हनुमान मंदिर पिपराइच में सोमवार रात आरती के दौरान मांस का टुकड़ा फेंकने का मामला प्रकाश में आया था

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोरखपुर। रेलवे फाटक के निकट स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पिपराइच में सोमवार रात आरती के दौरान मांस का टुकड़ा फेंकने वाले के विरुद्ध मंदिर के पुजारी दीनानाथ गुप्ता के तहरीर पर पुलिस ने बी. एन एस की धारा 196,300, 302,299,353इ द तथा अपराधिक धारा 7 सीएलए एक्ट के तहत केस दर्ज कर मंगलवार को आरोपी को जेल भेज दिया। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी नार्थ जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी उमेश यादव कुशीनगर के कप्तान गंज थाना क्षेत्र के ग्राम अगया नंबर एक गोसाईं टोला का निवासी है। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने सोमवार सायं हनुमान मंदिर में आरती के दौरान मंदिर के अंदर घुस कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, सम्प्रदाय विशेष के विरुद्ध अभद्र व अशोभनीय टिप्पणी करने तथा पालिथीन में रखे मांस के टूटने फेंकने का अपराध कबूल किया है। इसके इस कृत्य से मंदिर तथा तिराहे पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया था। थानाध्यक्ष पुरूषोत्तम आनंद सिंह,एसआई उमेश यादव के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आरोपी को पकड़ना तथा पूरे मामले का त्वरित खुलासा किया है।इस दौरान श्रेयांस राय , सुनील कुमार, धर्मेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे ।

कंपोजिट विद्यालय में पानी भर गया

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पीलीभीत। जनपद में भारी बारिश के कारण विकास खंड मरौरी क्षेत्र के ग्राम चंदोई स्थित कंपोजिट विद्यालय में पानी भर गया है। इस तरह की घटनाएं जिले में आम हो गई हैं।

क्योंकि पीलीभीत में तराई क्षेत्र बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहा है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं।भारी बारिश के चलते पीलीभीत में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।लगातार हो रही बारिश ने तराई क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कई इलाकों में जलभराव हो गया है,जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।पीलीभीत जिले में शारदा एवं देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास कर रहा है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एसडीएम ने किया निरीक्षण

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पूरनपुर। तहसील क्षेत्र के गांव शास्त्रीनगर,रामनगर,सिद्ध नगर सहित अन्य गांवों में उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव से पहुंचकर निरीक्षण किया साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों को फूड पैकेट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए है।

उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित लोगों को फूड पैकेट वितरित किए, जिसमें खाने के सामान और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल थी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी मदद के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित

क्षेत्रों में प्रशासनिक सहायता प्रदान की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह की इस पहल से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिली और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिली। उनकी इस पहल की सराहना की जा रही है और बाढ़ प्रभावित लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए।उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह की इस पहल से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिली और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिली हैं।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा हर सम्भव मदद का भरोसा दिया

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पूरनपुर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान ने प्रभावित लोगों से मिलकर उनसे संवेदना व्यक्त कि पहाड़ों एवं मैदानी भागों में हो रही मूलाधार बारिश से दर्जनों गांव व घरों में बाढ़ का पानी भर जाने से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में ट्रांस शारदा एवं नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में भयंकर बाढ से हाहाकार मचा हुआ है बताया कि एक सप्ताह से नेपाल उत्तराखंड और पीलीभीत में अतिवृष्टि के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।

जिससे यहां बाढ की बड़ी समस्या खड़ी हुई है अभी तक 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में बाढ़ देखने को मिलती थी इस बाढ से पीलीभीत सहित प्रदेश के कई जनपद प्रभावित हुए है कहा कि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया। बाढ़ बचाव के सभी उपाय समय पर पूरे हो, उस पर कार्य भी किया गया है उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया था, कि क्षेत्र में तत्काल राहत एवं बचाव कर प्रारंभ की जाए सबसे पहले प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए और हर समस्याओं के समाधान के लिए जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं खड़ा रहूंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों केबंदरबोझ,बूंदीभूड,14 नंबर कालोनी कके प्रभावित लोगों को राहत सामग्री , पका भोजन व त्रिपाल वितरित कर उनका हाल जाना व हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया. इस अवसर पर मण्डल उपाध्यक्ष असीम मृधा,सुभाष सिकदार,ग्राम प्रधान विवेकानंद सरकार,ग्राम प्रधान अजय वैध, उपजिलाधिकारी कलीनगर महिपाल सिंह, तहसीलदार वीरेन्द्र कुमार,नायब तहसीलदार अक्षय, लेखपाल सहित सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे।

भाजपा जिलाध्यक्ष और पालिका चेयरमैन ने एक साथ किया निचले इलाकों का निरीक्षण

फावड़ा पंजी से चेक की नालों की रुकावट, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने को कहा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पीलीभीत। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ आस्था अग्रवाल ने मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कुछ स्थानों पर कर्मचारियों को बुलाकर जल निकासी दुरुस्त कराई गई। गोदावरी स्टेट कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष डॉ आस्था अग्रवाल ने कई क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जल भराव वाले क्षेत्रों में निरीक्षण किया। गोदावरी स्टेट के बाहर भाजपा जिला अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष डॉ आस्था अग्रवाल ने पालिका कर्मियों से पंजी लेकर खुद नाले में रुकावट को परखा। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि नल खुले हुए हैं लेकिन क्योंकि खाखरा और देव नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है इसलिए बारिश का पानी आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है जैसे ही नदी का लेबिल नीचे होगा तो पानी क्रॉस हो जाएगा।

इसके बाद पालिका अध्यक्ष और भाजपा जिला अध्यक्ष ने तहसील सदर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए जा रहे भोजन की व्यवस्था को देखा और उप जिलाधिकारी व तहसीलदार से जानकारी भी ली।पालिका अध्यक्ष डॉ आस्था अग्रवाल ने नदी किनारे के निचले इलाके गोदावरी स्टेट कॉलोनी, जोशी टोला, सुभाष नगर, विनायक विहार, अवध नगर आदि क्षेत्रों में जल भराव का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को निर्देश दिए की वह स्थिति पर नजर बनाए रखें और सभी का सहयोग करें।इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, सभासद साकेत सक्सेना, वतनदीप मिश्रा, विपिन राजू फौजी, जगन्नाथ प्यारे, नंदकिशोर कश्यप , अमन बाबू, देव प्रकाश, विपिन मिश्रा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे साथ में नगर पालिका के सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

नगर पालिका में बैठक हुई सपन्न

पूरनपुर। नगर पालिका परिषद पूरनपुर एवं सोशियोवाइटल नेटवर्क फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर-घर कूड़ा संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।यह कार्यक्रम नगर के कुल 10 वार्डों में संचालित किया जाएगा, जिसमें सोशियोवाइटल नेटवर्क फाउंडेशन द्वारा जन-जागरूकता गतिविधियाँ एवं एम.आर.एफ. प्लांट का संचालन भी किया जाएगा।कार्यक्रम के दौरान पूरनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शैलेन्द्र गुप्ता, समाजसेवी हर्ष गुप्ता, वार्ड सभासदगण, अधिशासी अधिकारी एजाज अहमद, मण्डल कार्यक्रम प्रबंधक अंकित सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अंशुल गुप्ता तथा सोशियोवाइटल नेटवर्क फाउंडेशन के निदेशक रजत तिवारी की विशेष उपस्थिति रही।कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष शैलेन्द्र गुप्ता एवं अधिशासी अधिकारी एजाज अहमद द्वारा हरी झण्डी दिखाकर कूड़ा गाड़ियों का संचालन प्रारम्भ किया गया हैं।

पंजाब आई बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर संगत ने की बैठक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पूरनपुर। ब्लॉक रोड पर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मंगलवार दोपहर 2 बजे संगत की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता करना रहा। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने संगत से अपील की कि हर कोई अपनी क्षमता अनुसार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसे कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना मानव धर्म है। संगत ने निर्णय लिया कि आर्थिक सहायता राशि एकत्र कर जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा कपड़े, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान भेजने पर भी विचार किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन ने लोगों से अधिक से अधिक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि छोटी सी मदद भी किसी जरूरतमंद के जीवन में बड़ा सहारा बन सकती है। बैठक में क्षेत्र के अनेक लोग सामिल हुए और क्षेत्रीय लोगों से मदद की अपील की है। इस दौरान ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मस्जिद अल खजरा की तरफ से 25 हजार रुपए का चेक बाढ़ पीड़ितों को देने को कहा गया है।

पूरनपुर देहांत में आईं बाढ़ प्रधान प्रतिनिधि ।ने परिवारों को बांटा भोजन

पूरनपुर।क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कई घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, जिससे लोगों को भोजन की भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में प्रधान पति फैयाज हुसैन के नेतृत्व में प्रधान प्रतिनिधि दानिश हुसैन ने जरूरतमंद परिवारों की मदद की। मंगलवार दोपहर लगभग तीन बजे मोहल्ला अहमदनगर अमरूदपुर वाली गोटिया में भोजन वितरण किया गया। इसमें बाढ़ व जलभराव से प्रभावित परिवारों को पके हुए खाने के पैकेट बांटे गए। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

नगर में गणपति विसर्जन की भव्य शोभायात्रा सम्पन्न

पूरनपुर। नगर में आज गणपति विसर्जन की शोभायात्रा बड़े ही धूमधाम, श्रद्धा और उत्साह के साथ सम्पन्न हुई। पूरे नगर में भक्ति और उल्लास का वातावरण छाया रहा। शोभायात्रा में नगर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और गणपति बप्पा के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता के साथ सम्मानित साथीगण संजय गुप्ता, आशीष रस्तोगी, पुनीत पाण्डेय, अमोल मराठा, सुशील वर्मा, मयंक वर्मा, मुदित पाण्डेय, विवेक तिवारी, सुमित वर्मा सहित सर्राफा संघ एवं महाराष्ट्र मंडल के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे।नगरवासियों ने शोभायात्रा को सफल और भव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्रा के दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं ने फूल वर्षा और प्रसाद वितरण किया।कार्यक्रम के समापन पर सभी ने विघ्नहर्ता गणपति से नगर की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की।

नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

कादीपुर/सुलतानपुर। थानाक्षेत्र के मलिकपुर नोनरा जगरिया गांव में मंगलवार सुबह एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। सुबह अवधेश विश्वकर्मा की पत्नी गायत्री (26) का शव उनके घर में बंद कमरे के भीतर बिस्तर पर मिला। परिजनों के अनुसार कमरे का दरवाजा बाहर से कुंडी लगा था, जिसे तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। शव देखते ही परिजनों व ग्रामीणों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गायत्री की शादी बीते वर्ष 20 अप्रैल 2023 को हुई थी और वह चार माह की बच्ची की मां थी। मृतका का मायका दोस्तपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर रोहितावा गांव में है। मृतका के पिता लालजी विश्वकर्मा ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कादीपुर थाने के इंस्पेक्टर श्याम सुंदर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं, मायके वालों की तरफ से अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संकुल का एकदिवसीय संगीत प्रशिक्षण वर्ग सकुशल संपन्न

कादीपुर/सुलतानपुर। विद्या भारती काशी प्रांत के अंतर्गत सुल्तानपुर संकुल का एकदिवसीय संगीत प्रशिक्षण वर्ग आज सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, सिरवारा मार्ग, सुल्तानपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण वर्ग में काशी प्रान्त के संगीत प्रभारी भरत सिंह, काशी प्रान्त के संयोजक दीनबंधु सिंह तथा सुलतानपुर संकुल संयोजक ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने प्रतिभागियों को संगीत के विविध आयामों का प्रशिक्षण प्रदान किया। वर्ग में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए लगभग 14 संगीत शिक्षकों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया और प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुख्य रूप से रोली श्रीवास्तव, मांडवी द्विवेदी, प्रियंका पान्डेय, नीतू श्रीवास्तव, निहारिका श्रीवास्तव, लक्ष्मी शर्मा, दयाशंकर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश सिंह ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में संगीत के महत्व को बताते हुए सभी आचार्यों एवं प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।

पेट्रोल पंपों पर अचानक छापेमारी

सुल्तानपुर। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला पूर्ति विभाग और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने पेट्रोल पंपों पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी जीवेश मौर्य और आरटीओ विभाग के पीटीओ सुरेंद्र तिवारी ने विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पेट्रोल पंप मालिकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी बाइक सवार को बिना हेलमेट पेट्रोल दिया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संयुक्त छापेमारी की इस कार्रवाई से जिले के पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मच गया है।

प्राइवेट वाहनों पर पुलिस लोगो हटाने का अभियान शुरू

सुल्तानपुर। जिले में पुलिस ने प्राइवेट वाहनों पर अवैध रूप से पुलिस का लोगो और नाम लिखकर चलने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को रोका और कार्रवाई की।अखंडनगर से लखनऊ जाने वाली आशीष ट्रैवल्स की प्राइवेट बस पर पुलिस लिखा मिला। यातायात निरीक्षक राम निरंजन ने बस स्टेशन पर वाहन को रोककर बस से पुलिस सिंबल को मौके पर ही खुर्चवाया और वाहन स्वामी पर ?2000 का जुर्माना लगाया।टीएसआई राम निरंजन ने बताया कि इस तरह से अवैध तरीके से पुलिस का लोगो या नाम लिखकर चलना अपराध है। ऐसे वाहनों को न केवल जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर वाहन सीज भी किया जाएगा।पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि हाइवे पर फर्राटे भरने वाले प्राइवेट वाहन चालक इस तरह की हरकत से बाज आएं, वरना सख्त कार्रवाई होगी।

नई तकनीक से गन्ना किसानों को होगी पानी की बचत

सुल्तानपुर। किसान सहकारी चीनी मिल ने गन्ना की खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाया है। मिल ने यूपी माइक्रो इरीगेशन पोर्टल पर पंजीकृत गुजरात की टू वैल्यू इरीगेशन कंपनी के माध्यम से 3 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम स्थापित किया है। कंपनी ने गन्ने के खेत में उच्च तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया है।

चोरी की तीन बाइकों के साथ एक शातिर गिरफ्तार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ सुल्तानपुर के साथ ही रस्तामऊ मस्जिद के पास से चुराई गई थी बाइकें

अमेठी। थाना मोहनगंज पुलिस ने चोरी की तीन अदद मोटरसाइकिल के साथ एक अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर थाना मोहनगंज के प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह मय हमराह द्वारा तलाश वांछित देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा हिकमतअमली से पकड़कर नाम पता पूछा गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने अपना नाम ऐश मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शकील निवासी ग्राम मनी मनोहर थाना मोहनगंज बताया।मोटरसाइकिल के कागजात मांगने पर दिखा न सका एवं पूछताछ में बताया कि उसने यह हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल नंबर यूपी 33 जेड 7130 कुछ दिन पहले रस्तामऊ मस्जिद के पास से चुराई थी। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये युवक की निशानदेही पर भदमर मार्ग के पास खण्डहर से चोरी की दो अन्य मोटरसाइकिल एक होण्डा शाइन यूपी 32 जेके 8195 एवं 2.एचएफ डीलक्स बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल बरामद हुई।बरामद मोटरसाइकिलों के बारे में उसने बताया कि उसने मोटरसाइकिल होण्डा शाइन यूपी 32 जेके 8195 को जनपद लखनऊ से चुराया था एवं बिना नंबर प्लेट हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल को उसके साथी राहुल सिंह पुत्र गंगा बक्श सिंह निवासी हरपालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ने हलियापुर जनपद सुलतानपुर से चोरी कर बेचने के लिये दिया था। इस सम्बंध में कोतवाली प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने मुकदमा दर्जकर आरोपी युवक को जेल भेज दिया है।

खेलकूद सामग्री खरीद में बड़े पैमाने पर हुई धांधली

कैनविज टाइम्स संवाददाता

अमेठी। शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चों के लिये खेलकूद सामग्री की धनराशि जारी की गई है। जनपद के अधिकांश विकास क्षेत्रों के विद्यालयों में कागजी घोड़ा दौड़ाकर धनराशि खेवनहारों द्वारा ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है जिसमें सामग्री की गुणवत्ता को नजरअंदाज कर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं व धांधली की गई है जिससे ब्लाक से लेकर जनपद तक के आला अधिकारी भलीभांति वाकिफ हैं लेकिन फिर भी किसी ने स्थलीय निरीक्षण और भौतिक सत्यापन करना मुनासिब नही समझा है।प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद सामग्री क्रय के लिये पांच हजार रुपये व उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों के लिये दस दस हजार रुपये प्रबंध समिति के खाते में भेजा गया था। इस धनराशि से खेलकूद सामग्री खरीदने का निर्देश जारी किया गया है लेकिन जनपद के विकास क्षेत्र तिलोई,सिंहपुर, बहादुरपुर, शुकुल बाजार, जगदीशपुर के साथ ही अन्य कई विकास क्षेत्रों के विद्यालयों में खेवनहारों द्वारा कागजी घोड़ा दौड़ाकर धनराशि को ठिकाने लगा दिया गया है और खेलकूद सामग्री आज तक विद्यालय नही पहुंच सकी है और जिन विद्यालयों में खेलकूद सामग्री खरीदी भी गई है उसकी गुणवत्ता बेहद घटिया किस्म की बताई जा रही है।सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि दर्जनों विद्यालयों में खेलकूद सामग्री बक्सा में रखी हुई है जिसका उपयोग नौनिहाल कर ही नही पा रहे हैं और कई विद्यालयों के प्रबंध समिति अध्यक्ष इस वर्ष क्रय की गई खेलकूद सामग्री से अनभिज्ञ है उन्हें यह तक नही पता कि किस फर्म से और कब सामग्री खरीदी गई है। अब देखना यह है कि खेलकूद सामग्री के नाम पर धनराशि के बंदरबांट तक बेसिक शिक्षा विभाग कब पहुंचता है यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इस सम्बंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को खेलकूद सामग्री के भौतिक सत्यापन की जांच पड़ताल किये जाने का निर्देश दिया गया है और जांचोपरांत कार्यवाही की जायेगी।

एसपी ने पुलिस बूथ पर लगे कैमरों का लिया जायजा

अमेठी। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने थाना जगदीशपुर पुलिस बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन किया गया।पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा थाना जगदीशपुर के पुलिस बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया एवं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत त्यौहार रजिस्टर में प्रविष्टियों का अवलोकन कर सम्बंधित अधिकारी कर्मचारीगण को आवश्यक निर्देश दिया।

लोकतत्व के मर्मज्ञ साहित्यकार हैं मथुरा प्रसाद सिंह जटायु : अंजनी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सुलतानपुर। साहित्य, समाज और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में मथुरा प्रसाद सिंह जटायु ने अमिट छाप छोड़ी है। भाषा,छंद और शैली पर उनकी पकड़ मजबूत है। लोकतत्व के मर्मज्ञ साहित्यकार जटायु की रचनाओं का सही मूल्यांकन अभी बाकी है। यह बातें चर्चित स्तम्भकार अंजनी कुमार सिंह ने कहीं।

वह वरिष्ठ साहित्यकार मथुरा प्रसाद सिंह जटायु के 74 वें जन्मदिन पर रेलवे यूनियन सभागार में कौंडिन्य साहित्य सेवा समिति व उद्गार मंच द्वारा आयोजित साहित्य दिवस समारोह को बतौर मुख्य वक्ता सम्बोधित कर रहे थे। अध्यक्षता करते हुए डॉ आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप ने कहा कि कवि जटायु स्वयं में एक साहित्यिक संस्थान है । उनकी रचनाएं हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। प्रोफ़ेसर रामजी तिवारी ने कहा कि जटायु का साहित्य बहुत ज्यादा मूल्यवान है। जटायु भारत के महान सांस्कृतिक मूल्य के प्रतीक हैं। डॉ ए.के.सिंह ने कहा कि कवि जटायु की कविताएं समाज को प्रेरित करती हैं। उनके खंड काव्य अहिल्या ने अहिल्या के बारे में मेरी पूरी धारणा ही बदल दी है। सरस्वती वंदना राजबहादुर राना, स्वागत राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह रवि, आभार ज्ञापन पवन कुमार सिंह व संचालन नरेन्द्र शुक्ल ने किया।

समारोह में अंगवस्त्र, सम्मान पत्र, पुष्पगुच्छ आदि देकर चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु चर्चित चिकित्सक डॉ ए.के.सिंह को आचार्य सुश्रुत स्मृति सम्मान, हिंदी संवर्धन हेतु दयाराम अटल को त्रिलोचन शास्त्री स्मृति सम्मान, हरिनाथ शुक्ल को मान बहादुर सिंह स्मृति सम्मान, शिक्षा क्षेत्र में डॉ.रवींद्र प्रकाश सिंह को अम्बिका प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान, केशव प्रसाद सिंह को कृष्ण प्रसाद यादव स्मृति सम्मान, समाजसेवा क्षेत्र हेतु इंद्रमणि मिश्र को काशी प्रसाद पाण्डेय स्मृति सम्मान व विपिन यादव को राम चरित्र मिश्र स्मृति सम्मान देकर सम्मानित किया गया। साथ ही डॉ डी एस मिश्र व मंचस्थ अतिथियों को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ व अभिनंदन पत्र समर्पित किया गया।

डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर लगाई फटकार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

जयसिंहपुर/सुल्तानपुर। जयसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को डीएम कुमार हर्ष ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 32 कर्मचारियों में से 9 अनुपस्थित मिले। हालांकि, ड्यूटी रजिस्टर में केवल एक कर्मचारी को अनुपस्थित दिखाया गया था। डीएम ने एक्स-रे कक्ष का निरीक्षण किया। रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि दिन में 12 एक्स-रे किए गए।

ओपीडी में मरीज मीना कुमारी ने बताया कि कुछ दवाएं अस्पताल से मिलीं और कुछ बाहर से खरीदनी पड़ीं। स्वास्थ्य केंद्र में कई कमियां मिलीं। ड्रेसिंग रूम में साफ-सफाई नहीं थी। औषधि वितरण कक्ष में वॉशबेसिन गंदा था। रेफ्रिजरेटर का तापमान मानक के अनुरूप नहीं था। स्टॉक रूम में हेपेरॉन और ओबीडॉन दवाओं का स्टॉक रजिस्टर से मेल नही खाता है। डेंगू वार्ड में जनरल वार्ड के मरीजों को भर्ती पाया गया। भर्ती मरीजों को नाश्ते में खिचड़ी दी गई थी। डॉक्टरों को मरीजों के भोजन का मेन्यू तक नहीं पता था। लेबर रूम का अटेंडेंट रामसरण भी अनुपस्थित मिला। डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में पाई गई कमियों के लिए संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए।

जीवन रक्षक पहल

कैसी विडंबना है कि जो हेलमेट दुर्घटना में हमारे जीवन की रक्षा करता है, उसे पहनाने के लिये सरकार को सख्ती करनी पड़ रही है। जब तमाम दिशा-निर्देशों की अवहेलना तथा जुर्माने की अनदेखी करके लोग बिना हेलमेट का सफर करने की जिद दिखाते हैं तो निश्चय ही सरकारों को सख्ती करनी पड़ती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' मुहिम कितनी प्रभावी साबित होती है। हम यह जानते हैं कि दोपहिया वाहन पर चलना जितना सुविधाजनक है, उतना ही दुर्घटना की दृष्टि से बेहद संवेदनशील भी। कोई गिरता है तो चोट लगना निश्चित है। खतरा ये होता है कि हमारे गिरने पर पीछे से आ रहा तेज वाहन चाहकर भी गिरने वाले को बचा नहीं पाता। देश में हर साल लाखों दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, कुछ दुर्भाग्यशाली बच नहीं पाते। लेकिन यदि हेलमेट लगा हो तो जीवित बचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस हकीकत को जानते हुए भी कि देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में तीस फीसदी शिकार दोपहिया वाहन चालक ही होते हैं, इस दिशा में लोग गंभीरता नहीं दिखाते। विडंबना यह भी है कि बहुत से लोग हेलमेट लगाते भी हैं तो सस्ते, और उसे भी टशन में लगाने से बचते हैं। विश्वास किया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीवन रक्षा की यह मुहिम रंग लाएगी। उम्मीद करें कि एक सितंबर से शुरू होने वाले इस अभियान को दोपहिया वाहन चालकों का सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा। निस्संदेह, दोपहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत की वजह हेलमेट न लगाना या फिर अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट ठीक से न पहनना होता है। कई लोग चालान से बचने के लिये औपचारिकता के लिए सस्ता हेलमेट पहन लेते हैं, जो पहनने के बावजूद बचाव नहीं कर पाता। या फिर गिरने की स्थिति में खुलकर अन्यत्र गिर जाता है। सवाल उठता है कि यातायात नियमों के अनुसार अनिवार्य होने के बावजूद लोग हेलमेट को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? ऐसी लापरवाही जिसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ सकती है। कुछ लोग जीवनपर्यंत विकलांगता के शिकार भी हो जाते हैं। फिर भी ऐसी लापरवाही समझ से परे है। एक हकीकत यह भी है कि यातायात पुलिस भी शुरू से ही ऐसी सख्ती नहीं दिखाती कि कोई बिना हेलमेट के वाहन न चला सके। एक संकट यह भी है कि पिछली सीट पर बैठी महिलाएं हेलमेट नहीं पहनती हैं। जबकि हादसे होने की स्थिति में वे भी शिकार बनती हैं। कुछ को अपने बालों के खराब होने की चिंता होती है। क्या जीवन से बड़ी कोई चीज हो सकती है? लेकिन विडंबना यह कि तमाम प्रयासों के बावजूद हम हेलमेट पहनने को लेकर जिम्मेदारी का भाव जगाने में कामयाब नहीं हो पाते। एक आंकड़े के अनुसार, बीते साल तीस हजार लोगों की मौत हेलमेट न पहनने के कारण हुई। फिर भी हम हकीकत को नजरअंदाज करते हैं। उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम रंग लाएगी।

ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' मुहिम कितनी प्रभावी साबित होती है। हम यह जानते हैं कि दोपहिया वाहन पर चलना जितना सुविधाजनक है, उतना ही दुर्घटना की दृष्टि से बेहद संवेदनशील भी। कोई गिरता है तो चोट लगना निश्चित है। खतरा ये होता है कि हमारे गिरने पर पीछे से आ रहा तेज वाहन चाहकर भी गिरने वाले को बचा नहीं पाता। देश में हर साल लाखों दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, कुछ दुर्भाग्यशाली बच नहीं पाते।

एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहने का आदेश स्वागत योग्य

वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली में विपक्षी नेताओं ने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई इस प्रक्रिया के औचित्य को लेकर वे अभी आश्वस्त नहीं हैं। वैसे इस तरह की संवैधानिक प्रक्रियाओं को भी राजनीतिक रंग देना, विडम्बनापूर्ण है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्षी नेताओं द्वारा कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग को आरोपों के दायरे में शामिल रखा जाना। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी नेता चुनाव आयोग और सरकार को घेरते हुए यह मुद्दा बार-बार उठाते रहेंगे। विपक्षी दल इस विषय में जिस तरह की नकारात्मकता दर्शा रहे हैं, वह भी प्रश्नों के घेरों में एवं अतिश्योक्तिपूर्ण है। क्योंकि यह अत्यंत सामयिक और संवेदनशील है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया, एक ओर मतदाता सूची को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 'वोटर अधिकार यात्रा' निकालना और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करना, लोकतंत्र की सेहत और स्थायित्व को धुंधलाता है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का जहां तक सवाल है तो वहां भी विपक्षी दल और चुनाव आयोग एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाते नजर आए। जहां विपक्षी दलों के वकील इस प्रक्रिया की खामियों की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाते रहे, वहीं चुनाव आयोग के वकील ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या इस प्रक्रिया में नहीं, बल्कि उस मानसिक सोच में है, जो आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह से ग्रस्त है। उनके मुताबिक दूसरे पक्ष की मानसिकता ही खोट निकालने की हो गई है। इसमें दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को यथासंभव उपयुक्त ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह देखना बाकी है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में सभी पक्षों का विश्वास जीतने और सभी योग्य मतदाताओं की आशंकाएं दूर करने में किस हद तक कामयाब हो पाता है। निश्चित ही पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अभी तक के अनुभव मिले-जुले रहे हैं।

बिहार में चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया लगातार चर्चा में है। जहां एक तरफ इसे लेकर शुरू की गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में विपक्षी नेताओं की रैली के साथ समाप्त हुई, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर नए आदेश जारी करते हुए मतदाता सूची सुधार का कार्य आगे भी जारी रहने का निर्देश जारी किये हैं, यह निर्देश स्वागतयोग्य है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह पूरा प्रकरण आखिरकार कैसा मोड़ लेगा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर किस तरह का असर डालेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि बिहार के मतदाता 1 सितंबर के बाद भी दावा या आपत्ति कर सकेंगे। यह निर्देश बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी राजनीतिक दलों की शिकायतें दूर नहीं हुई हैं। ज्यादातर आम लोगों की शिकायतों का निवारण कर दिया गया है, पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए एसआईआर की खामी एक बड़ा मुद्दा है। महागठबंधन में शामिल दल इस मुद्दे में विवाद खड़े करने में ही अपने चुनावी हित देख रहे हैं। हालांकि, न्यायालय ने उचित ही बताया है कि मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर असमंजस की स्थिति काफी हद तक 'विश्वास का मामला' है। इसका मतलब, जो राजनीतिक अविश्वास है, उसे दूर करने के लिए स्वयं दलों को सक्रिय होना पड़ेगा। न्यायालय की इस सलाह पर राजनीतिक दलों को गौर करना चाहिए और इस प्रक्रिया को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि चुनाव सुधार एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर सभी राजनीतिक दल यह ठान लें, तो चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सकता है। वास्तव में, मतदाता पुनरीक्षण का काम राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर लगातार जारी रखना चाहिए, इससे लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित होगी एवं चुनाव की खामियों को सुधारा जा सकेगा। वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली में विपक्षी नेताओं ने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई इस प्रक्रिया के औचित्य को लेकर वे अभी आश्वस्त नहीं हैं। वैसे इस तरह की संवैधानिक प्रक्रियाओं को भी राजनीतिक रंग देना, विडम्बनापूर्ण है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्षी नेताओं द्वारा कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग को आरोपों के दायरे में शामिल रखा जाना। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी नेता चुनाव आयोग और सरकार को घेरते हुए यह मुद्दा बार-बार उठाते रहेंगे। विपक्षी दल इस विषय में जिस तरह की नकारात्मकता दर्शा रहे हैं, वह भी प्रश्नों के घेरों में एवं अतिश्योक्तिपूर्ण है। क्योंकि यह अत्यंत सामयिक और संवेदनशील है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया, एक ओर मतदाता सूची को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 'वोटर अधिकार यात्रा' निकालना और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करना, लोकतंत्र की सेहत और स्थायित्व को धुंधलाता है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का जहां तक सवाल है तो वहां भी विपक्षी दल और चुनाव आयोग एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाते नजर आए। जहां विपक्षी दलों के वकील इस प्रक्रिया की खामियों की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाते रहे, वहीं चुनाव आयोग के वकील ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या इस प्रक्रिया में नहीं, बल्कि उस मानसिक सोच में है, जो आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह से ग्रस्त है। उनके मुताबिक दूसरे पक्ष की मानसिकता ही खोट निकालने की हो गई है। इसमें दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को यथासंभव उपयुक्त ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह देखना बाकी है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में सभी पक्षों का विश्वास जीतने और सभी योग्य मतदाताओं की आशंकाएं दूर करने में किस हद तक कामयाब हो पाता है। निश्चित ही पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अभी तक के अनुभव मिले-जुले रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि राजनीतिक दल सूची में मतदाताओं को शामिल करने के दावों के बजाय उन्हें हटाने की मांग करते हुए आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने ज्यादा नाम काटे होते, तो नाम जोड़ने के लिए ज्यादा दावे होते। कांग्रेस को शायद अभी भी शिकायत है कि उसके एजेंटों के दावे पर गौर नहीं किया गया है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने कहा है कि दावे यथोचित प्रारूप में नहीं किए गए हैं। ऐसे में, चुनाव आयोग को कुछ उदारता बरतते हुए अपनी सूची का हकीकत से मिलान करना चाहिए। बिहार में ही बड़ी पार्टियों के तमाम बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) सक्रिय हो जाएं, तो मतदाता सूची को दोषरहित बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भी यही मंशा है। मतदाता सूची को लेकर विवादों में पड़े रहना हर प्रकार से अफसोसजनक होगा, इससे हमारे लोकतंत्र की गरिमा घटेगी। गौर करने की बात है कि शीर्ष अदालत के निर्देश पर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और पैरा लीगल स्वयंसेवकों को पुनरीक्षण में लगाया जाएगा। वास्तव में, पुनरीक्षण जल्दी संपन्न होना चाहिए, ताकि बिहार चुनाव में देरी न होने पाए। चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। इसका दायित्व केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। मतदाता सूची में गड़बड़ी, डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम, या फर्जी पंजीकरण जैसी समस्याएं अक्सर चुनावी निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती रही हैं। ऐसे में एसआईआर जैसी प्रक्रिया को चुनाव आयोग द्वारा लागू करना आवश्यक कदम माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले पर्याप्त राजनीतिक परामर्श, जनजागरूकता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई थी? यदि ऐसा नहीं हुआ, तो राजनीतिक दलों का असंतोष स्वाभाविक है। इसमें कोई शक नहीं कि पुनरीक्षण के मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। बिहार आज निर्णायक मोड़ पर है। विशेष रूप से जन सुराज पार्टी के जो तेवर हैं, उससे बिहारी राजनीति के पूरे कलेवर पर असर पड़ सकता है। बिहार का विकासोन्मुख होना जरूरी है। इस जरूरत को बिहार में नया और पुराना विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष भी नए सिरे से समझ रहा है। लोगों के लिए तो यही सबसे अच्छी बात होगी कि सभी राजनीतिक दल अपने मुद्दों में विकास और रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा को सबसे ज्यादा तरजीह दें। अब बड़ा प्रश्न है कि यदि सुप्रीम कोर्ट आयोग के पक्ष में निर्णय देती है, तो विपक्ष को अपने आंदोलन का औचित्य सिद्ध करना कठिन होगा। वहीं यदि अदालत को प्रक्रिया में खामियां मिलती हैं, तो आयोग की कार्यप्रणाली पर गहरे प्रश्न उठेंगे। विपक्ष की ओर से इसे सीधे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताना भी अतिशयोक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि मतदाता सूची को शुद्ध करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। यदि ऐसे हर संवैधानिक कदम को राजनीतिक रंग देकर विवादित बना दिया जाए, तो लोकतंत्र में संस्थाओं की मजबूती के बजाय कमजोरी ही बढ़ेगी। एसआईआर जैसी पहल की केवल बिहार ही नहीं, समूचे देश में जरूरत है ताकि चुनाव प्रक्रिया भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों से मुक्त हो सके। लेकिन इसकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब यह निष्पक्ष, पारदर्शी और सर्वसम्मत तरीके से लागू हो। चुनाव आयोग को न केवल अपने कदमों की संवैधानिकता, बल्कि उसकी जनस्वीकार्यता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। विपक्ष को भी इस प्रक्रिया को मात्र राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय रचनात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशना चाहिए। लोकतंत्र केवल मतदाताओं की भागीदारी से नहीं, बल्कि संस्थाओं पर विश्वास से भी जीवित रहता है। इसलिए संस्थाओं की गरिमा और पारदर्शिता दोनों की रक्षा अनिवार्य है। **–ललित गर्ग**

मनुष्य के दखल से पृथ्वी की बदहाली

संजीव ठाकुर

महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन है, किंतु मानव की लालच को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान और जल की थी किन्तु मनुष्य की लालसा के कारण हमें उद्योग धंधों का विकास तीव्र गति से करना पड़ा, मशीनें जितनी बड़ी से बड़ी होती गई आदमी उतना ही बौना होता गया।जब हम अपने विकास का इतिहास देखते हैं तो ब्रिटिश सत्ता के दौरान हमारे संसाधनों का प्रकृति का अंधाधुंध दोहन होता रहा है। कृषि में नई नई तकनीक ट्रैक्टर, रसायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि बंजर होकर कराहाने लगी। विकास का सही मायने माननीय शक्तियों के साथ ऊर्जा और उसकी शक्ति तथा सामर्थ्य का सही उपयोग ही होगा। जब से हमने विकास के पथ पर उड़ान भरी है उद्योगों की चिमनी यों को ऊपर उठाया मोबाइल क्रांति का बटन दबाया ई-मेल पर सवार होकर विश्व संदेश को सुना तब से हमारे झरनों का कल कल स्वर और संगीत बंद हो गया, पक्षियों का कलरव बंद हो गया पक्षी अब चीत्कार कर रहे हैं। नदी नाले सूखकर मृतप्राय हो गए हैं। समुद्र की लहरों की झंकार विलुप्त हो गई है और पानी खारा और खारा हो गया है। अब हमें यह सोचना है कि विकास के नाम पर हमें ग्रीन इंडिया चाहिए या इंटरनेट की सवारी कर डिजिटल इंडिया चाहिए। बच्चों की झोली में इंटरनेट को डालकर डिजिटल जेनरेशन का सपना देखना चाहिए या प्रकृति की गोद में सुगंधित वायु की लहरों में खो जाना चाहिए। झरनों में बैठकर नौका विहार का आनंद लेना चाहिए या कंप्यूटर में बैठकर नेट खोल कर नन्हे मुन्ने की आंखों पर जोर डालकर उन्हें चश्मा वाला बनाना चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान यानी कि ग्रीन इंडिया और डिजिटल इंडिया का सपना नदी के दो कभी ना मिलने वाले किनारे हैं। विकास के नाम पर असीमित उद्योग धंधों की बाढ़ आ गई है। भूमि समाप्त हो रही है साथ ही हमारी वायु विषैली हो गई है। रात में शहरी मकानों मैं बिजली के झालरों के सामने आकाश में रात्रि के तारों की चमक फीकी पड़ गई है। जंगलों को हम ऐसे साफ करते गए जैसे सड़क पर रोड रोलर चला रहे हैं। नगर बने ,महानगर बने ,मकान बने किंतु अब घर गायब होते गए, हमें तब सुध आई जब चिड़िया चुग गई खेत, हमें विकास के नाम पर मानव सभ्यता से जुड़ी जमीन पानी, हरियाली,पक्षी जानवर सब चाहिए केवल अंधाधुन्ध कंक्रीट का विकास या इंटरनेट की रफ्तार नहीं चाहिए। इसके लिए हमें संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश लगाना होगा। संसाधनों का इस्तेमाल अतिरेक में नहीं होना चाहिए। हम प्राकृतिक परियोजना तथा परिस्थितिकी की परियोजनाओं का स्वागत करना होगा सम्मान करना होगा। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सौर, पवन, बायोगैस, ज्वार तरंग लहरों को ऊर्जा का आधार बनाना होगा। भारत में परिस्थितियां बड़ी विषम है एक तरफ सोडियम लाइट से नहाती दिल्ली ,मुंबई ,बेंगलुरु की रंगीन सड़कें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तेज गति की मेट्रो है,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लुफ्त उठाते हुए युवक युवतियां है, दूसरी तरफ पसीने से भीगा हुआ किसान हैं। कैरोसिन की चिमनी में बच्चों को कहानी सुनाती माताएं हैं। यानी कि इतनी डिजिटल विषम बताएं भारत के अलावा विश्व के किसी भी कोने में नहीं है। भारत में विकास के नाम पर डिजिटलाइजेशन करने की आवश्यकता जरूर है पर गांव जंगलों नदियों और प्राकृतिक संसाधनों के निरस्तीकरण और विनाश की कीमत पर नहीं। हमें यह साबित करना होगा कि भारत के विकास की हरित क्रांति के साथ-साथ डिजिटल इंडिया भी विकास की गति को बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत कि हरित क्रांति का विकास ही डिजिटल इंडिया का स्वप्न को भी पूरा करेगा। इसके लिए स्वच्छ साफ-सुथरे संसाधन जैसे जल, खनिज, यूरेनियम ,थोरियम नहीं होगा तब तक नाभिकीय रिएक्टर की भट्टीयां कैसे चलेंगी। किसी कवि ने कहा है, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, पंछी सारे उपवन के चहचहा उठेंगे। विकास का जो भी रास्ता या नक्शा हम तैयार करेंगे निश्चित तौर पर वह मार्ग हरित क्रांति या हरित विकास से होकर गुजरेगा, जिससे हम अपनी 141 करोड़ जनसंख्या को स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे और एक नए भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे।

सेहत मंत्र

कई बीमारियों को दूर करता है लौंग

भारतीय रसोई में लौंग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल खाने का स्वाद बढ़ाया जा सकता है, बल्कि अपनी सेहत को भी सेहतमंद बनाया जा सकता है। हालांकि सदियों से इसे आयुर्वेदिक औषधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लौंग की मदद से कई बीमारियों से आराम पाया जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार छोटी-छोटी समस्या होने पर दवा का सेवन करना ठीक नहीं होता है। रोजमर्रा में होने वाली आम समस्याओं से राहत पाने के लिए हमारी रसोई में ही कुछ चीजे मौजूद होती हैं। इन्हीं में से एक लौंग हैं। सर्दी और जुकाम जैसी समस्या से राहत पाने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अपने मुंह में कुछ देर के लिए एक लौंग रख लें। इससे आपको गले में होने वाले दर्द और सर्दी-जुकाम से राहत मिलेगी। गलत खान-पान के कारण अक्सर गैस की समस्या होती है, तो ऐसे में आप हर बार दवाओं का सेवन करना भी हानिकारक हो सकता है। इसके लिए आपके रसोई में मौजूद लौंग सबसे लाभकारी औषधि है। अगर आप गैस और कब्ज जैसी समस्या से परेशान हैं, तो इससे राहत पाने के लिए सुबह खाली पेट लौंग तेल की कुछ बूंदो को एक गिलास पानी में डालकर सेवन करें। मुंह से बदबू आने पर कोई हमसे बात करना तो दूर बैठना पसंद भी नहीं करता है। ऐसे में हम अपनी इस समस्या से आराम पाने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दांतों का दर्द भी हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको रोजाना करीब 45 दिनों तक 1 से 2 साबुत लौंग का सेवन करना पड़ेगा। लौंग की मदद से आप अपनी सुंदरता को भी बढ़ा सकते हैं। चेहरे पर होने वाले दाग-धब्बे या डार्क सर्कल जैसी समस्या को लौंग की मदद से सही किया जा सकता है। इसके लिए पीसे हुए लौंग को किसी फ़ेसपैक या बेसन में मिलाकर लगाएं। ध्यान रहे अपने चेहरे पर सीधे तौर पर लौंग का उपयोग न करें। ये काफी गर्म होता है और ऐसा करने पर इससे जलन हो सकती है। बाल झड़ने और बालों के रुखेपन की समस्या से ज्यादातर लोग परेशान हैं। ऐसे में लौंग सबसे लाभकारी उपाय है। इसके लिए एक भगोने पानी में 4 से 5 लौंग को उबाल लें। इसके बाद हल्का ठंडा होने पर इस पानी से अपने बालों को धोएं। इससे आपके बाल मजबूत और चमकदार बनेंगे।

धर्म मंत्र

भगवान गणेश को पसंद है 'दूर्वा'

मोदक और लड्डू का भोग तो भगवान गणेश जी को अति प्रिय है ही इसके अलावा गणेश जी को 'दूर्वा' चढ़ाने का भी काफी महत्व है। कहा जाता है कि गणेश पूजन में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्त को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि 'दूर्वा' एक प्रकार की घास है जिसे 'दूब' भी कहा जाता है, संस्कृत में इसे दूर्वा, अमृता, अनंता, गौरी, महौषधि, शतपर्वा, भार्गवी आदि नामों से जाना जाता है। 'दूर्वा' कई महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त है। इसका वैज्ञानिक नाम साइनोडान डेक्टीलान है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत-कलश निकला तो देवताओं से इसे पाने के लिए दैत्यों ने खूब छीना-झपटी की जिससे अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी पर भी गिर गई थी जिससे ही इस विशेष घास 'दूर्वा' की उत्पत्ति हुई। गणेश जी को दूर्वा अत्याधिक प्रिय क्यों है इसके संबंध में पुराणों में एक कथा कही गई है जिसके अनुसार अनादि काल में अनलासुर नाम का एक विशाल दैत्य हुआ करता था जिसके कोप से धरती सहित स्वर्ग लोक में भी त्राही-त्राही मची हुई थे। समस्त देवता, ऋषि-मुनि, मानव इस दैत्य के आतंक से त्रस्त थे। यह दैत्य धरती पर मानवों को जिंदा ही निगल जाता था। इस विशालकाय दैत्य से तंग आकर एक बार देवराज इंद्र सहित समस्त देवता और ऋषि-मुनि महादेव शिवजी की शरण में पहुंचे और प्रार्थना की कि हमें इस दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाएं। महादेव ने कहा कि यह काम तो विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं, आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। महादेव का आदेश पाकर सभी देवता और प्रमुख ऋषि-मुनि भगवान गणेश जी के पास पहुंचे और अनलासुर के कोप से मुक्ति दिलाने की विनती गणपति बप्पा से की।

पर्यटन

इंदौर शहर की हर अदा निराली

देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात इंदौर शहर की हर अदा निराली है। हालाँकि कोरोना काल में इंदौर पर भारी आपदा आई और यह सर्वाधिक संक्रमण वाला शहर भी बना लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। इंदौर शहर सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि कारोबार करने और खाने-पीने का शौक रखने वालों के लिए भी बेहतरीन जगह है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर होने के बावजूद साफ-सफाई के प्रति यहाँ जैसी जागरूकता है वैसी देश के अन्य महानगरों में देखने को नहीं मिलती है। यही कारण रहा है कि इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित इंदौर शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 190 किमी पश्चिम में स्थित है। इंदौर को उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर एक व्यापार बाजार के रूप में स्थापित किया गया था, वहीं इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ से ही पहले इंदूर और बाद में इस शहर को इंदौर नाम प्राप्त हुआ। मराठा काल में बाजीराव पेशवा ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर, अपने सेनानायक मल्हारराव होलकर को यहां का जमींदार बना दिया, जिन्होंने होलकर राजवंश की नींव डाली। होलकर वंश का शासनकाल भारत के स्वतंत्र होने तक रहा। यह मध्य प्रदेश में शामिल होने से पहले ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी और मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी था। खान (कान्ह) नदी के तट पर बनी कृष्णापुरा छत्रियाँ, होलकर शासकों को समर्पित हैं। ब्रिटिश काल से ही इंदौर एक औद्योगिक शहर के रूप में विख्यात रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में छोटे-बडे उद्योग हैं। उद्योगों में बड़ी संख्या में स्थानीय और कई एमएनसी भी हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग व्यावसायिक वाहन बनाने वाले व उनसे सम्बन्धित उद्योग हैं, इसे ''भारत का डेट्राइट'' भी कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में ही स्थित है। औद्योगिक शहर के साथ-साथ इंदौर शिक्षा का भी केन्द्र है। यह भारत का एकमात्र शहर है, जहाँ भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम इंदौर) व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी इंदौर) दोनों स्थापित हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में जिन 100 भारतीय शहरों को चयनित किया गया है जिनमें इंदौर भी है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से बिगड़े हालात

आक्रोशित एबीवीपी ने किया हंगामा, लाठी चार्ज की हर तरफ आलोचना, डीएसपी हटाए गए, कोतवाल लाइन हाजिर

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बाराबंकी। रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, माती में चल रहे एलएलबी पाठ्यक्रम को लेकर मचे घमासान का असर मंगलवार को पूरे जिले में देखा गया । बिना मान्यता कोर्स संचालित करने और छात्रों से मोटी फीस वसूलने के आरोपों के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों व एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है । पुलिसिया बर्बरता का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन विरोधी नारेबाजी के साथ शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया।छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से एलएलबी की मान्यता नवीनीकरण में ढिलाई बरतता आ रहा है। इस कारण छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में फंस गया है। जबकि दूसरी ओर विश्वविद्यालय लगातार दाखिले लेकर फीस वसूल रहा है। यह न केवल शिक्षा के साथ खिलवाड़ है बल्कि सीधा-सीधा धोखाधड़ी का मामला हैघटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। सीओ को हटाया गया, कोतवाल राना को लाइन हाजिर कर दिया गया और चौकी स्टाफ पर गाज गिरी। अयोध्या मंडलायुक्त व पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।छात्रों के पक्ष में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन उतर आए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर अधिवक्ता संघ तक ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर समर्थन जताया। जिला अस्पताल में भाजपा पदाधिकारियों का जमावड़ा रहा और कलेक्ट्रेट में प्रशासन विरोधी नारे लगातार गूंजते रहे।एबीवीपी अवध प्रांत सचिव पुष्पेंद्र बाजपेयी ने स्पष्ट कहा, ल्लजब तक कुलपति खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करते और निष्कासित छात्रों की बहाली नहीं होती, तब तक आंदोलन थमेगा नहीं। छात्र हितों के खिलाफ कोई भी अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।ङ्कविश्वविद्यालय परिसर और शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन परिसर में तनाव अभी भी बना हुआ है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे हुआ संघर्ष ?

बाराबंकी : एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार सुबह विश्वविद्यालय गेट पर धरना शुरू किया। दोपहर तक छात्र–छात्राओं की संख्या बढ़ी और कालेज प्रशासन के खिलाफ नारे गूंजने लगे। स्थिति तब बिगड़ी जब कॉलेज का गेट बंद कर देने से अंदर सैकड़ों छात्र फंस गए। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने गेट खुलवाने का प्रयास किया तो हाथापाई शुरू हो गई।सूत्र बताते हैं कि विद्यालय प्रशासन के कुछ लोगों ने एबीवीपी के छात्रों को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे। इसी बीच पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिस पर छात्र उग्र हो गए और पुलिस चौकी पर पथराव की घटना हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भीड़ को तितर–बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री अभिषेक बाजपेयी, जिला संयोजक अनुराग मिश्र सहित करीब 25 छात्र–छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सफ़ेदाबाद स्थित मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। देर रात एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएम आवास के बाहर पुतला दहन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मान्यता के मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि ल्लरिन्यूअल प्रक्रिया लंबित है।ङ्क मगर बड़ा सवाल यह है कि जब तक मान्यता पूरी नहीं हुई, तब तक प्रवेश क्यों लिए गए और फीस क्यों वसूली गई? कालेज प्रशासन इस गंभीर सवाल पर चुप है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए छात्रों को ही दोषी ठहराना विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी कायरता मानी जा रही है। इधर, छात्र संगठनों ने मांग की है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर विद्यालय प्रशासन के लोगों द्वारा हाथापाई क्यों की गई, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो ?

भाकपा ने छात्रों के आंदोलन को दिया समर्थन, दोषियों पर कार्रवाई की माँग

बाराबंकी। राम स्वरूप विश्वविद्यालय में विधि के छात्रों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कथित बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सामने आ गई है। पार्टी ने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए दोषी पुलिसकर्मियों व विश्वविद्यालय प्रशासन के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। भाकपा राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण को लेकर संगठन ने जिलाधिकारी आवास पर पुतला दहन किया, जो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह घटना घटी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई है।

कल्याणी नदी तट पर श्रद्धालुओं की भीड़, गणेश प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन

शांति व्यवस्था के बीच धूमधाम से सम्पन्न हुआ गणेश विसर्जन महोत्सव

कैनविज टाइम्स संवाददाता

मसौली बाराबंकी। गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को ग्राम पंचायत नेवला करसंडा, मुजफ्फरपुर व करन्द में शोभायात्रा निकालकर गाजे-बाजे एवं ''गणपति बप्पा मोरिया'' के जयघोष के बीच भगवान श्रीगणेश की प्रतिमाओं का कल्याणी नदी घाट पर विधिवत विसर्जन किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

अबीर-गुलाल उड़ाते हुए श्रद्धालुओं ने ''अगले बरस तू जल्दी आना'' के नारों के साथ भावभीनी विदाई दी। विसर्जन क्रम कल्याणी नदी तट के पड़रिया घाट पर संपन्न हुआ, जहां देर शाम तक भीड़ उमड़ी रही।शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवागत प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक विपिन सिंह व शिवकुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा।विसर्जन समारोह में अध्यक्ष संदीप कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष राजकमल, उपाध्यक्ष आशीष कुमार वर्मा, वीरेंद्र कुमार रावत, अध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष अतुल कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष संजय वर्मा, अभिषेक कुमार वर्मा (करन्द), अध्यक्ष मनीष पुजारी, उपाध्यक्ष अनुज कुमार, कोषाध्यक्ष ऋतिक कुमार, श्याम बाबू, विकास बाबू व अमर बाबू सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पोर्टल पर पंजीयन करके मिल जाएगी बीज की किट

कैनविज टाइम्स संवाददाता

निंदूरा बाराबंकी। विकास खंड निंदूरा अंचल के किसान अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर बीज मिनी किट निः शुल्क प्राप्त कर सकेंगे। सहायक विकास अधिकारी कृषि हरि प्रकाश चौधरी ने बताया कि रबी 2025-26 में राज्य सहायतित योजना के तहत किसानों को चना 16 किग्रा, मटर 20 किग्रा, मसूर 8 किग्रा और राई/सरसों दो किग्रा का मिनीकिट उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मिनीकिट के लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। इच्छुक किसान एक सितम्बर से 25 सितम्बर तक कृषि दर्शन-दो पोर्टल (द्धण्ध्प://थद्दन्द्धदथन्पद्धथद्ध.फ्ण्.द्दधफ.द्धद्ध) पर आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ केवल कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। प्रत्येक किसान को केवल एक ही दलहनी फसल का मिनीकिट प्रदान किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा।

एडीओ कृषि ने क्षेत्र के सभी किसानों से समय से आवेदन कर योजना का लाभ लेने की अपील की है।

सड़क हादसे में विवाहिता की मौत, पति घायल

रामनगर बाराबंकी केसरीपुर- महादेवा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक विवाहिता की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम रहटा निवासी शिव बरन अपनी पत्नी पिंकी मिश्रा को मोटरसाइकिल से लेकर रामनगर से घर लौट रहे थे। मोहनिया नाला के पास उनकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिससे पिंकी नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही मौत हो गई। घायल शिव बरन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महादेवा चौकी प्रभारी संतोष त्रिपाठी ने बताया कि असंतुलित होकर मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकराई थी। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है।

सिंचाई विभाग ने शीशम वृक्ष कटवाकर बेचा, वन विभाग ने की बरामद

निंदूरा बाराबंकी। घुंघटेर थाना क्षेत्र के ग्राम महोलिया में सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी ने राजकीय शीशम वृक्ष बिना अनुमति कटवाकर अमानीगंज (थाना बीकेटी, लखनऊ) की लकड़ी ठेकी पर बेच दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने छापा मारकर समस्त शीशम बोटा, प्रकाष्ठ तथा अपंजीकृत ट्रैक्टर-ट्राली (आयशर 333) बरामद की। अभियुक्त मनोज कुमार यादव, अवर अभियंता सिंचाई विभाग सीतापुर और आसिफ निवासी अमानीगंज के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 में रेंज केस दर्ज किया गया है।

सर्प दंश से छात्रा की मौत

रामनगर बाराबंकी। सांप के काटने से एक छात्रा की मृत्यु पर शोकाकुल परिवार और कॉलेज परिसर में गम का माहौल हो गया। समाचार के अनुसार ग्राम बिठौरा निवासी साहबदीन की 16 वर्षीय पुत्री मोहिनी (कक्षा 11, भगवान देवी पाटन शाह बालिका इंटर कॉलेज, रामनगर) की नींद में ही सांप के डसने से मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार को कॉलेज की प्रधानाचार्या की अगुवाई में सभी शिक्षक और छात्राओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

अध्यापिका से नाराजगी, बच्चों ने छोड़ा विद्यालय

बाराबंकी। प्राथमिक विद्यालय निम्बहा में सहायक अध्यापिका ऐश्वर्या सिंह के खिलाफ अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार राय को लिखित शिकायत दी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अध्यापिका का व्यवहार बच्चों और अभिभावकों के प्रति ठीक नहीं है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज अभिभावकों ने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना बंद कर दिया। विद्यालय में कुल 36 बच्चों में से सोमवार को केवल 4 और मंगलवार को 12 बच्चे ही उपस्थित हुए। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संबंधित अध्यापिका को मूल विद्यालय जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जेल में ग्राम प्रधान, पंचायत में विकास कार्य ठप, समिति गठन की मांग

50 दिनों से विकास कार्य ठप्प, ग्रामीण समस्याओं की आगोश में

कैनविज टाइम्स संवाददाता

रामसनेहीघाट बाराबंकी। विकासखंड बनीकोडर की ग्राम पंचायत लकड़िया में ग्राम प्रधान रामरूप करीब पचास दिन से जेल में बंद हैं। प्रधान के निरुद्ध होने से पंचायत के विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाकियू अंबावत किसान नेता दिनेश कुमार ने स्थिति पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी से समिति गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंचायत में विभिन्न मदों के खातों से धन निकासी न होने के कारण विकास कार्य रुक गए हैं, जिससे रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत में कुल 11 सदस्य हैं, लेकिन प्रधान के जेल जाने के बाद अब तक समिति का गठन न होना प्रशासनिक लापरवाही दर्शाता है। किसान नेता दिनेश कुमार ने बताया कि डीएम को लिखित प्रार्थना पत्र व शपथपत्र देकर पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के तहत समिति गठित करने की मांग की गई है। इस दौरान भाकियू अंबावत जिला अध्यक्ष लवकुश यादव भी मौजूद रहे।लकड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान रामरूप पुत्र रामनारायण वर्ष 2021 में निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष जुलाई माह की 10 तारीख को घटित एक आपराधिक मामले में सुबेहा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वे जिला कारागार में निरुद्ध हैं।पंचायती राज एक्ट की धारा 12 के अनुसार, प्रधान का पद रिक्त होने पर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य नामित कर दायित्वों का निर्वहन करता है। किंतु लकड़िया पंचायत में अब तक यह प्रक्रिया पूरी न होने से गांव के विकास कार्य ठप पड़े हैं।प्रधान के जेल में होने की सजा सीधे जनता को भुगतनी पड़ रही है। सचिव चाहकर भी अकेले कोई कार्य नहीं करा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को शीघ्र समिति गठित कर पंचायत कार्य सुचारु रूप से शुरू कराना चाहिए।

दलित महिला की पुकार अनसुनी, प्रधान पति पर लकड़ी हड़पने का आरोप

कैनविज टाइम्स संवाददाता

रामनगर बाराबंकी। योगी आदित्यनाथ सरकार दलित उत्पीड़न रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। थाना रामनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत जुरौंडा की दलित महिला शांति देवी और उनके पति राजकुमार वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मगर आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। मामला उनके ससुर बुलाकी गौतम के इलाज के लिए पुश्तैनी भूमि पर लगे यूं के लिफ्ट्स के पेड़ कटवाने और उससे निकली तीन टालियों लकड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि ग्राम प्रधान पति अवधेन्दु प्रताप सिंह ने हल्का लेखपाल और दो सिपाहियों की मदद से दबाव बनाते हुए यह कहते हुए लकड़ी कब्जे में ले ली कि पेड़ परती की जमीन में लगे थे और उन्हें पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया। यही नहीं, शांति देवी के खेत में पड़ी दो टालियां लकड़ी भी प्रधान पति उठा ले गए। सालों बीत जाने के बावजूद न तो लकड़ी की नीलामी कराई गई और न ही कोई कार्रवाई की गई, उल्टा पंचायत भवन से लकड़ी गायब कर दी गई।पीड़िता शांति देवी का कहना है कि चकबंदी के दौरान उक्त भूमि पर उसके ससुर का कब्जा सिद्ध है और यह उनकी पुश्तैनी भूमि है। ऐसे में लकड़ी छीन लेना, गाली-गलौज करना और दुर्व्यवहार करना सरासर अन्याय है। इस मामले में शांति देवी ने 7 जुलाई 2025 को उपजिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर न्याय की मांग की, साथ ही मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान पति की कथित मिलीभगत के चलते अब तक कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। पीड़िता का साफ कहना है कि अगर प्रशासन ने न्याय नहीं दिया तो वह माननीय न्यायालय की शरण लेगी।यह मामला सरकार के उन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है जिनमें दलितों को न्याय और सुरक्षा दिलाने की बातें की जाती हैं, जबकि हकीकत यह है कि वर्षों से एक दलित महिला अपने हक के लिए दर-दर भटक रही है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है।

नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान तेज, 18 वाहनों का चालान, डग्गामार बस सीज

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बाराबंकी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों को रोड सेफ्टी नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग ने नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान को और सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है।

मंगलवार को जनपद के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण के दौरान बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचे 18 दोपहिया वाहन चालकों के चालान किए गए, वहीं लखनऊ-बाराबंकी हाईवे पर चल रही डग्गामार बस (यूपी 43 टी 6374) को खामियां पाए जाने पर सीज कर थाने में निरुद्ध किया गया। इस अभियान की जानकारी देते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन अंकिता शुक्ला ने बताया कि यात्री/मालकर अधिकारी रवि चन्द्र त्यागी की टीम ने आलापुर स्थित पेट्रोल पंप पर जांच के दौरान यह कार्रवाई की और पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना हेलमेट पेट्रोल खरीदने वाले चालकों को किसी भी हाल में ईंधन न दिया जाए।बिना हेलमेट चलने वाले चालक न केवल कानून तोड़ते हैं बल्कि अपनी और अपनों की जिंदगी से भी खिलवाड़ करते हैं। हर साल हजारों लोग इस लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। इसलिए हेलमेट पहनना केवल नियम का पालन ही नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है।

शीतल नाथ भगवान की पूजा, भाव विभोर हुए श्रावक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बाराबंकी। पर्युषण पर्व क्रम में आज उत्तम संयम धर्म के साथ ही धूपदशमी की पूजा श्रावकों द्वारा भक्ति भाव से की गई।सर्व प्रथम सरावगी स्थित श्री १००८ चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान का पंचामृत अभिषेक व शांति धारा हुई।संयम आत्मा को स्वस्थ करने का साधन है। संयम के बिना जीवन व्यर्थ हैं। राग, मोह, द्वेष को त्यागना एवं संसार के यम को जो मार दे वही संयम है। सब जगत में पूर्ण शांति रहे कोई भी दुखी न रहे इसके लिए मंत्रोचार के साथ भगवान की आराधना की गयी। आज छठवे दिन विशेष रूप से श्री शीतलनाथ भगवान की पूजा सभी भक्तों ने किया। प्रभु के समक्ष धुप खेकर ये प्रार्थना की कि हमारे भीतर जितनी भी कषाय , राग द्वेष है वह सभी नष्ट हो जाए जिससे हमे परम शांति कि प्राप्ति हो।अनुशाशन में रहकर इंद्रियों को नियंत्रण कर मनुष्य महान बन सकता है।

सांयकालीन सभा में श्रावकों ने सामूहिक रूप से प्रभु कि आरती की। सब भाव विभोर थे, कोई नृत्य कर रहा था तो कोई झूम रहा था कोई प्रभु को निहार रहा था तो कोई आनंदित होकर भगवान कि भक्ति कर रहा था। सभी भक्त भक्ति में लीं थे। सुनीता जैन छाबड़ा, कल्पना छाबड़ा, अनिल जैन छाबड़ा, श्रुति जैन एवं दीपाली जैन ने भव्य प्रस्तुतीकरण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तम्बोला दीपाली जैन , श्रुति जैन ने पाटनी परिवार ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, धरसेनाचार्य पाठशाला के बच्चों ने नाटिका, छाबड़ा परिवार ने झंडा ऊँचा रहे हमारा व हाथों कि कसरत में और बाकलीवाल परिवार ने धर्म कि संगीत मयी यात्रा का धार्मिक आयोजन किया। इसके अंतर्गत बम्पर प्राइज सभी प्रतियोगियों को गिफ्ट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन बिंदु, उपाध्यक्ष पंकज जैन धनावत, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, मंत्री सुभाष जैन गंगवाल, भंडारी सचिन जैन , दीप चंद गंगवाल, राजेश कुमार जैन, अंकुर जैन चीकू, विशाल जैन, पद्म छाबड़ा, अशोक पाटनी, पवन जैन गुरुपरिवार, हरीश जैन, कमलेश जैन सहित कई सैकड़ा श्रावक उपस्थित रहे।

आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारत को सुपर 4 में कोरिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की जरूरत

एजेंसी

राजगीर। पूल चरण में अपराजेय रहने के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय हॉकी टीम को एशिया कप सुपर 4 चरण के मुकाबले में बुधवार को पांच बार की चैम्पियन और पिछली विजेता कोरिया के खिलाफ अपने खेल में सुधार करना होगा। भारतीय टीम पूल ए में सारे मैच जीतकर सुपर 4 में पहुंची है। उसने चीन को 4-3 से, जापान को 3-2 और कजाखस्तान को 15-0 से हराया। जीत के बावजूद भारत का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। चीन और जापान के खिलाफ औसत प्रदर्शन के बाद उसने टूर्नामेंट में दूसरी ही बार खेल रही कजाखस्तान टीम पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। दूसरी ओर कोरियाई टीम भी अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है। वह पूल बी में मलेशिया के बाद दूसरे स्थान पर रही और मलेशिया ने उसे 4-1 से हरा दिया था। तेज गर्मी और भारी उमस के बीच टीमें संघर्ष करती नजर

आई लेकिन सुपर 4 के मैच शाम को होंगे जिससे प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। भारतीय टीम ने सोमवार को हर क्षेत्र में बेहतर खेल दिखाया चाहे गोलकीपिंग हो, डिफेंस , मिडफील्ड या आक्रमण। फॉरवर्ड पंक्ति का प्रदर्शन तारीफ के काबिल रहा जिसमें अभिषेक ने चार गोल दागे। सुखजीत सिंह ने भी हैट्रिक लगाई और फ्लैंक से उनकी ड्रिबलिंग और 'डी' के भीतर शांतचित्त रवैया जबर्दस्त था। भारत की फॉरवर्ड पंक्ति में एकमात्र कमजोर कड़ी दिलप्रीत सिंह रहे जिन्होंने गोल तो किया लेकिन एक आसान मौका गंवाया भी। अभी तक टूर्नामेंट में वह जूझते ही नजर आये हैं और अब उन्हें प्रदर्शन में सुधार करना होगा। भारत के कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा ,'' सुपर 4 चरण से पहले स्ट्राइकर्स का लय में रहना जरूरी है। मनप्रीत सिंह की अगुवाई में मिडफील्ड का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने डिफेंस की कमान बखूबी संभाल रखी है।पहले दो मैचों में औसत प्रदर्शन के बाद गोलकीपर कृशन बहादुर पाठक के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। कोच फुल्टोन ने हालांकि कहा कि असल टूर्नामेंट अब शुरू हुआ है जिसमें पिछले नतीजे मायने नहीं रखते। उन्होंने कहा ,'' हमारी टीम आत्मविश्वास से भरी है। खिलाड़ी लय में है और हम यही चाहते हैं। कजाखस्तान के खिलाफ हरमनप्रीत, जुगराज सिंह , संजय और अमित रोहिदास चारों ने पेनल्टी कॉर्नर तब्दील किये। जुगराज ने हैट्रिक लगाई। सुपर 4 चरण हालांकि सभी टीमों (भारत, कोरिया, चीन और मलेशिया) के लिये नयी शुरूआत होगी। सभी टीमें एक दूसरे से खेलेंगी और शीर्ष दो रविवार को फाइनल में जगह बनायेंगी।

विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने से ओलंपिक की भरपाई कर दी: चिराग

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन टीम के सदस्य चिराग शेट्टी ने कहा कि हाल में पेरिस में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने से एक साल पहले इसी शहर में ओलंपिक खेलों में पोडियम तक नहीं पहुंच पाने की काफी हद तक भरपाई कर दी। चिराग और लंबे समय से उनके साथी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी ने पिछले सप्ताह विश्व चैंपियनशिप में पुरुष युगल का कांस्य पदक जीता। दुनिया की नौवें नंबर की इस जोड़ी ने क्वार्टर फ़ाइनल में मलेशिया के दो बार के ओलंपिक पदक विजेता आरोन चिया और सोह वूई यिक को हराकर विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा पदक हासिल किया। भारत की इस जोड़ी का पहली बार विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना सेमीफाइनल में चीन की 11वीं वरीयता प्राप्त चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी से हार के साथ टूट गया। चिराग ने कहा, ''मुझे लगता है कि आरोन और सोह के खिलाफ जीत

निश्चित रूप से बहुत खास है। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि अगर हम सही रणनीति के साथ खेलें तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। हाल ही में उनके खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा था। विशेष कर ओलंपिक खेलों में जहां हमें उनके हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, ''इसलिए उन्हें लगातार गेम में हराने से निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ा और यह पिछले साल के ओलंपिक खेलों की एक तरह से भरपाई भी थी। हम ओलंपिक में उसी कोर्ट पर उनसे हार गए थे। इसलिए उनके खिलाफ जीत वास्तव में खास थी। एक साल पहले सात्विक और चिराग को ओलंपिक में पदक से चूकने का दर्द सहना पड़ा था, जब मलेशियाई जोड़ी ने उनका अभियान बीच में ही रोक दिया था। कांस्य पदक जीतने के साथ ही सात्विक और चिराग विश्व चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए हैं। साइना नेहवाल ने विश्व चैंपियनशिप में दो जबकि पीवी सिंधू ने पांच पदक जीते हैं। चिराग ने कहा कि यह जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि साइना और सिंधू के साथ हम भी विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं।

संक्षिप्त समाचार

राशिद खान ने रचा इतिहास, अफगानिस्तान की यूएई पर आसान जीत

शारजाह। अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को सोमवार रात 38 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज़ में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस मैच में स्टार स्पिनर राशिद खान ने बड़ा कीर्तिमान रचते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए। 26 वर्षीय राशिद ने 3 विकेट लेकर अपना आंकड़ा 165 पर पहुँचा दिया और न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ टिम साउदी (164 विकेट) को पीछे छोड़ दिया। राशिद ने ईथन डिसूज़ा (12), आसिफ खान (1) और ध्रुव पाराशर (1) को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले अफगानिस्तान ने बल्लेबाज़ी करते हुए 4 विकेट पर 188 रन बनाए। इब्राहिम जादरान (63 रन, 40 गेंद, 4 छक्के, 3 चौके) और सेदिकुल्लाह अतल (54 रन, 40 गेंद, 3 छक्के, 4 चौके) ने दूसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की। अतल का यह पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक था। अंत में करीम जनत (23*, 10 गेंद, 2 चौके, 2 छक्के) और अजमतुल्लाह उमरज़ई (20*, 12 गेंद, 2 छक्के) ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर स्कोर को मज़बूती दी। यूएई के मुहम्मद रोहिद और सगीर खान ने 2-2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई ने कप्तान मुहम्मद वसीम (67 रन, 37 गेंद, 6 छक्के, 4 चौके) की आतिशी पारी से धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने 23वां टी20ऋअर्धशतक जमाया, लेकिन उनके आउट होते ही टीम की लय बिगड़ गई और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। इस जीत के बाद अफगानिस्तान ने सीरीज़ में वापसी की। पाकिस्तान पहले ही दोनों मैच जीत चुका है और अब मंगलवार को अफगानिस्तान से भिड़ेगा। तीनों टीमों को दो-दो मैच खेलने हैं, जबकि शीर्ष दो टीमें 7 सितंबर को फाइनल में आमने-सामने होंगी।

आसिफ अली ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मध्य क्रम बल्लेबाज आसिफ़ अली ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 2021 टी 20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ रोचक मुकाबले में उनकी 7 गेंदों पर 25 रनों की पारी उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की सबसे यादगार पारी है। आसिफ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अपने जीवन का एक गर्व करने योग्य अध्याय करार देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। आसिफ ने कहा, ''आज मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। अलहमदुलिल्लाह, पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरव की बात रही है। मेरे प्रशंसकों, साथियों और कोचों, हर उतार-चढ़ाव में आपके प्यार, विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार और दोस्तों, जो खुशी के पलों में और मुश्किल हालातों में, जिसमें विश्व कप के दौरान मेरी प्यारी बेटी का निधन भी शामिल है, मेरे साथ खड़े रहे, आपकी ताकत ने मुझे आगे बढ़ाया। हालांकि आसिफ़ ने कहा कि वह घरेलू क्रिकेट और दुनिया भर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। आसिफ ने पाकिस्तान के लिए 58 टी20 और 21 वनडे खेले। टी20 में आसिफ़ ने 15.18 की औसत से 577 रन बनाए वहीं वनडे में उन्होंने 25.46 की औसत से 382 रन बनाए जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने आख़िरी वनडे अप्रैल 2022 में लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ खेला था जबकि अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने अगस्त 2023 में एशियन गेम्स में बांग्लादेश के ख़िलाफ टी20 प्रारूप में खेला। आसिफ़ को 2018 में वेस्टइंडीज के ख़िलाफ डेब्यू का मौक़ा मिला था, डेब्यू से पहले उन्होंने उस साल पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को ख़िताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके दो महीने बाद ही उन्हें वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला लेकिन प्रदर्शन की निरंतरता की कमी के चलते वह टीम में स्थाई जगह हासिल नहीं कर पाए। आसिफ हाल ही में पाकिस्तान चैंपियंस के लिए भी खेलते नजर आए थे। साउथ अफ़्रीका चैंपियंस के ख़िलाफ फाइनल में उन्होंने 28 रनों की पारी खेली थी।

मिचेल स्टार्क ने टी20 क्रिकेट को अलविदा कहा

ब्रिसबेन। आस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और टी20 प्रारूप में अपने कैरियर को विस्तार देने के लिये टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की श्रृंखला के लिये मंगलवार को घोषित आस्ट्रेलियाई टी20 टीम में स्टार्क और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के नाम नहीं हैं। पैतीस वर्ष के स्टार्क ने 65 टी20 मैचों में 79 विकेट लिये हैं। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनकी प्राथमिकता है और अगले दो साल के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये उन्हें तैयार रहना है। कमिंस को पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बाद से आराम दिया गया है। उनकी कमर में भी दर्द है इसलिये नवंबर में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला की तैयारी के मद्देनजर उन्हें आराम दिया है। स्टार्क एशेज, भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला और 2027 वनडे विश्व कप के लिये पूरी तरह फिट रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा ,'' मैने आस्ट्रेलिया के लिये हर टी20 मैच के हर मिनट का मजा लिया है। खासकर 2021 विश्व कप क्योंकि जीत के साथ हमने पूरे सफर का आनंद लिया। स्टार्क ने कहा ,'' टी20 विश्व कप से संन्यास लेने का कारण तरोताजा और फिट बने रहना है। इससे गेंदबाजी समूह को टी20 विश्व कप की तैयारी के लिये भी समय मिल जायेगा। आस्ट्रेलियाई चयन समिति के प्रमुख जॉर्ज बेली ने कहा ,'' मिचेल को अपने टी20 कैरियर पर गर्व होना चाहिये। वह विश्व कप 2021 विजेता टीम का प्रमुख सदस्य था। अच्छी बात यह है कि वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलता रहेगा।

पटरी पर लौट रहे हैं भारत-चीन संबंध : गोयल

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सीमा मुद्दे सुलझते जाएंगे तनाव कम होता जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई बैठक में भारत-चीन सीमा मुद्दे के '' निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य'' समाधान की दिशा में काम करने पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को मान्यता देते हुए व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने सऊदी टूरिज्म कैंपेन का चेहरा

एजेंसी

रियाद। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी (एसटीए) के उपभोक्ता ब्रांड सऊदी, वेलकम टू अरेबिया ने अपना नया वैश्विक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें दुनिया के फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो नज़र आ रहे हैं। इस कैंपेन का नाम आई कम फॉर फुटबॉल, आई स्टेड फॉर मोर रखा गया है, जो यह संदेश देता है कि सऊदी अरब सिर्फ खेलों का नहीं बल्कि मनोरंजन, संस्कृति और फैशन का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। फिल्मी अंदाज़ में तैयार किए गए इस कैंपेन में रोनाल्डो को सऊदी अरब के अलग-अलग इवेंट्स का अनुभव करते दिखाया गया है। शुरुआत में वे स्टेडियम में बैठे अपने खेल से अन्य खेलों की तुलना करते दिखते हैं और फिर रंगीन दृश्यों के बीच दर्शकों के जुनून और जोश को महसूस करते हैं। यह दिखाता है कि सऊदी अब वैश्विक खेल और सांस्कृतिक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा

रहा है। यह कैंपेन सऊदी के सालभर चलने वाले विविध खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों पर रोशनी डालता है, जो रियाद, जेद्दाह और अलउला में आयोजित होते हैं। इनमें फीफा वर्ल्ड कप 2034, एएफसी एशियन कप 2027, ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक्स 2027 और एशियन विंटर गेम्स 2029 जैसे बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं। साथ ही फॉर्मूला-1, ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, गोल्फ, टेनिस और सऊदी प्रो लीग जैसे नियमित आयोजनों से यह देश खेलों का वैश्विक केंद्र बन रहा है। सऊदी न केवल खेलों में बल्कि कला, फैशन और मनोरंजन में भी तेजी से उभर रहा है। रियाद फैशन वीक, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फ़ेस्टिवल, आर्ट्स बिएनाले और सीजन फ़ेस्टिवल्स इसके कैलेंडर का अहम हिस्सा हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय कलाकार मंच साझा करते हैं। सऊदी के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा, सऊदी आज सांस्कृतिक असलियत, गर्मजोशी भरी मेहमाननवाज़ी और विश्वस्तरीय आयोजनों का अनोखा संगम बन चुका है। हम पर्यटकों को यादगार अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के सीईओ फहद हमीदअद्दीन ने बताया कि 2018 से अब तक सऊदी 100 से अधिक बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स की मेज़बानी कर चुका है और 2030 तक 150 मिलियन पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी सऊदी के इस सफर को खास बताते हुए कहा, यहां खेलों का भविष्य लिखा जा रहा है। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि सऊदी अपनी जड़ों को सम्मान देते हुए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रेगिस्तान से स्टेडियम तक – यहां हर युवा खिलाड़ी बड़ा सपना देख सकता है। सऊदी अरब ने पर्यटन क्षेत्र में 800 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 22.4 अरब डॉलर का बाजार मूल्य और 16.5 अरब डॉलर का जीडीपी योगदान हासिल करना है। खेल और मनोरंजन के बड़े आयोजनों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नौकरियां, बुनियादी ढांचा और युवाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी।

न्यूज़ीलैंड टी20 सीरीज के लिए, मार्कस स्टॉइनिस की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें ऑलराउंडर मार्कस स्टॉइनिस की वापसी हुई है। उनके साथ मिच ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट और जेवियर बार्टलेट की भी टीम में वापसी हुई है, जिससे अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्टॉइनिस की दावेदारी मज़बूत हो गई है। 36 वर्षीय स्टॉइनिस पिछले एक साल से न तो सेंट्रल और न ही स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी बार नवंबर 2024 में खेला था। इस साल फरवरी में उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन टी20 लीग्स में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स और द हंड्रेड में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए अहम भूमिकाएं निभाईं और दोनों टीमों को फाइनल तक पहुँचाने में योगदान दिया।

महानआर्यमन सिंधिया ने एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर संभाली कमान

एजेंसी

इंदौर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया ने मंगलवार को मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। एमपीसीए चुनावों में अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और पूरी कार्यकारिणी सर्वसम्मति से चुनी गई है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित एमपीसीए की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी पर अंतिम मुहर लग गई। महान आर्यमन (29) ने वर्ष 1957 में स्थापित एमपीसीए के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इस संगठन की बागडोर संभाली है। एमपीसीए अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद महान आर्यमन ने संवाददाताओं से कहा,''यह मेरे लिए बेहद भावुक पल है क्योंकि मेरे दिवंगत दादा माधवराव सिंधिया और मेरे पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एमपीसीए अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। मैं खुश हूं कि एमपीसीए परिवार ने मुझ पर भी इस जिम्मेदारी के लिए भरोसा जताया है। एमपीसीए चुनावों में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बारे में पूछे जाने पर ग्वालियर के पूर्व राजघराने के 29 वर्षीय वंशज ने कहा,''यह एक उदाहरण है कि एमपीसीए ऐसा परिवार है जो सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। एमपीसीए देश का इकलौता राज्य क्रिकेट संघ है जहां पारिवारिक माहौल में चुनाव होते हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि वह सूबे में क्रिकेट को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देंगे। एमपीसीए की एजीएम में शामिल होने से पहले, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महान आर्यमन के साथ शहर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचे और गणेशोत्सव के दौरान दर्शन किए। एमपीसीए के नये अध्यक्ष महान आर्यमन की सक्रियता क्रिकेट के गलियारों में गुजरे तीन सालों में लगातार बढ़ती देखी गई है। वह 2022 में जीडीसीए के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्हें 2022 में ही एमपीसीए का आजीवन सदस्य बनाया गया था। महान आर्यमन सूबे की टी20 क्रिकेट लीग मध्यप्रदेश लीग (एमपीएल) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2024 में अपने गृहनगर ग्वालियर से एमपीएल की शुरुआत की थी। सिंधिया परिवार लम्बे वक्त से सूबे के क्रिकेट प्रशासन में है और एमपीसीए पर इस परिवार का पिछले कई दशकों से वर्चस्व बरकरार है। मध्यप्रदेश सरकार के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एमपीसीए में सिंधिया परिवार के वर्चस्व को 15 साल पहले चुनौती दी थी।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को खुला एवं पारदर्शी बनाएंगे: सीतारमण

चेन्नई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खुला एवं पारदर्शी बनाएंगे। इससे अनुपालन बोझ में और कमी आएगी एवं छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। तमिलनाडु स्थित सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका स्पष्ट उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, अनुपालन लागत कम करना तथा स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों और उद्यमियों के लिए एक अधिक अनुकूल परिवेश का निर्माण करना है। सीतारमण ने कहा, '' इसके अतिरिक्त, अगले दो दिन होने वाली परिषद की बैठक के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की योजनाबद्ध शुरुआत से आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली एवं पारदर्शी हो जाएगी। अनुपालन बोझ में और कमी आएगी जिससे छोटे व्यवसायों के लिए फलने-फूलना आसान हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़े सुधारों की घोषणा की थी और नागरिकों के लिए दिवाली पर उपहारों का वादा किया था। सीतारमण ने कहा कि देश के अपने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए बैंकों से न केवल ऋण का विस्तार करने बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास को गति प्रदान करने, एमएसएमई के लिए समय पर और आवश्यकता-आधारित वित्तपोषण सुनिश्चित करने, बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने व विविध आवश्यकताओं को पूरा करने का आह्वान किया जाता है। इस लक्ष्य के लिए बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सेमीकॉन के पहले दिन बना इंडिया डीपटेक अलायंस, डीपटेक इकोसिस्टम को देगा बढ़ावा

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत में डीपटेक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2025 के पहले दिन वेंचर कैपिटल कंपनियों के एक समूह ने इंडिया डीपटेक अलायंस (आईडीटीए) के गठन की घोषणा करते हुये कहा कि संस्थापक सदस्यों ने एक अरब डॉलर पूंजी की प्रतिबद्धता जतायी है। वेंचर कैपिटल कंपनी सेलेस्टा कैपिटल के संस्थापक प्रबंधक साझेदार श्रीराम विश्वनाथन ने यहां द्वारका स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, ''आज अग्रणी वैश्विक और भारतीय निवेशकों के गठबंधन की तरफ से मुझे इंडिया डीपटेक अलायंस के गठन की घोषणा करने का सौभाग्य मिला है, उद्योग का गठबंधन जो भारत में जीवंत डीपटेक इकोसिस्टम बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम करने की इच्छा रखता है। श्री विश्वनाथन ने कहा कि आईडीटीए का उद्देश्य भारत में नयी परिभाषाएं गढ़ने वाली डीपटेक कंपनियों के निर्माण के लिए निजी पूंजी और विशेषज्ञता मुहैया कराना है ताकि वे दुनिया को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें, और अमेरिका-भारत गलियारे को मजबूत किया जा सके। उन्होंने बताया कि संस्थापक सदस्यों ने कुल एक अरब डॉलर की पूंजी प्रतिबद्धता जाहिर की है और आने वाले दिनों में सदस्यता बढ़ने के साथ इस आंकड़े में काफी बढ़ोतरी की उम्मीद है। संस्थापक सदस्यों में सेलेस्टा कैपिटल के अलावा एक्सेल, प्रेमजी इनवेस्ट, ब्लूम वीसी, गाजा कैपिटल, आईबीएस, ड्रीम वेंचर्स और टेनेसिटी वेंचर्स शामिल हैं। उन्होंने भारत के लंबे समय तक जारी रहने वाले प्रौद्योगिकी विकास में विश्वास रखने वाली और कंपनियों से आईडीटीए से जुड़ने की अपील की।

सर्राफा बाजार में जोरदार तेजी, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे सोना और चांदी

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज जबरदस्त तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं ने आज सर्राफा बाजार में तेजी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कीमत में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज प्रति 10 ग्राम 1,0,090 रुपये से लेकर 1,06,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना आज 97,250 रुपये से लेकर 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोने की तरह ही चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,26,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,06,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर

कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,06,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,06,140 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 97,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,06,090 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 97,250 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,06,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,06,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 97,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,06,240 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में तेजी का रुख नजर आ रहा है।

स्टार्ट-अप से लेकर स्मार्ट शहरों तक बैंक हो सकते हैं मददगार : मुर्मु

एजेंसी

चेन्नई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि स्टार्ट-अप से लेकर स्मार्ट शहरों तक भारतीय बैंक अच्छे मददगार हो सकते हैं।

सुश्री मुर्मु ने आज यहां सिटी यूनियन बैंक (सीयूबी) के 120वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहाः ''स्टार्ट-अप से लेकर स्मार्ट शहरों तक, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें बैंक मदद कर सकते हैं। बैंक एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं।'' उन्होंने जोर दिया कि कि डिजिटल और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता में बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बैंकिंग उद्योग इसकी विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज बैंकों की भूमिका वित्तीय लेनदेन से आगे बढ़ गई है और बैंक केवल धन के संरक्षक नहीं हैं बल्कि वे विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये समावेशी और सतत विकास में भी सहायक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक वित्तीय समावेशन है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सिटी यूनियन बैंक जैसे बैंक बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहती है जहाँ औपचारिक बैंकिंग तक सीमित पहुँच है। बैंक और फिनटेक कंपनियाँ वंचित समुदायों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप, सूक्ष्म-ऋण और बीमा उत्पाद प्रदान कर रही हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि सिटी यूनियन बैंक ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सुश्री मुर्मु ने आगे कहा कि भुगतान बैंक, डिजिटल वॉलेट और बैंकिंग संवाददाताओं ने वित्तीय सेवाओं को दूर-दराज के गाँवों तक पहुँचाया है। इस क्षेत्र में प्रगति के बावजूद, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट पहुँच और वित्तीय जागरूकता के संदर्भ में अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से लोगों को प्रौद्योगिकी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सकता है। सुश्री मुर्मु ने कहा , ञ्च किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण हमारे बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। समय पर किफायती ऋण और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के साथ ही कृषि-तकनीकी पहलों का समर्थन करके, बैंक कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं। बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विकास के इंजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, ''हमारे बैंकों को वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों की मदद के लिए भी कदम उठाने चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को बैंकिंग सेवाओं के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे-जैसे हमारी डिजिटल और ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता जा रहा है।

चुनाव आयोग ने दो जगह वोटर सूची में नाम होने पर पवन खेड़ा से मांगा जवाब

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने दो जगह वोटर सूची में नाम होने के आरोप में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को नोटिस भेजा है और आठ सितम्बर तक जवाब देने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि श्री खेड़ा के नाम दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 40 के काका नगर के पते पर है और दूसरी जगह उनका नाम दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 41 के डी ब्लॉक जंगपुरा के पते का है। श्री खेड़ा को भेजे नोटिस में चुनाव अधिकारी ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एक व्यक्ति के दो जगह से वोटर लिस्ट में नाम होना दंडनीय अपराध है। चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि इस नियम के तहत उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और इसका जवाब निर्वाचन अधिकारी को आठ सितम्बर सुबह 11 बजे तक मिलना चाहिए। इससे पहले भाजपा नेता अमित मालवीय ने श्री खेड़ा पर दिल्ली में दो मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इस मामले की जाँच करने का आग्रह किया था। उनका आरोप था कि श्री खेड़ा का जंगपुरा और नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों के दो जगह से वोटर लिस्ट में नाम है।

पवन खेड़ा को पार्टी से निकालें राहुल गांधीः सचदेवा

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दो 'ईपीआईसी नंबर' के मुद्दे पर निशाना साधते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। श्री सचदेवा ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि श्री खेड़ा के दो ईपीआईसी नंबर' और वोट का मामला सामने आने से दिल्ली की जनता हतप्रभ है। उन्होंने कहा कि एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में ''वोट चोरी'' के नाम पर भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सबसे करीबी पार्टी प्रवक्ता खेड़ा के दो 'ईपीआईसी नंबर' तथा वोट सामने आए हैं। इससे श्री गांधी के दोहरे मानदंड उजागर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन श्री गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जवाब देना चाहिए कि वे श्री खेड़ा के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने श्री गांधी से श्री खेड़ा को पार्टी से निकालने की मांग की है।

भ्रष्टाचार से जुड़े 23 मामलों में विभिन्न विभागों ने हमारी सलाह नहीं मानीः केंद्रीय सतर्कता आयोग

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि 23 ऐसे मामले हैं जहां सरकारी विभागों ने भ्रष्टाचार के सिलसिले में उसकी सलाह की काफी हद तक अनदेखी की।

उसने कहा कि इनमें से सबसे अधिक पांच मामले रेल मंत्रालय तथा दो-दो मामले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) से संबद्ध हैं। आयोग का कहना है कि एक-एक मामला दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (डीपीए), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण (एएआई), आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और इंडियन ओवरसीज बैंक से संबंधित था।

आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), 'कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई)', 'मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)', 'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)', सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), प्रसार भारती और जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा उसकी सलाह नहीं मानने के एक-एक मामले का भी हवाला दिया। प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करने वाली इस संस्था (सीवीसी) की हाल में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग की सलाह नहीं मानने से सतर्कता प्रक्रिया दूषित होती है और सतर्कता प्रशासन की निष्पक्षता कमजोर होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) केंद्र सरकार, उसके निगमों, कंपनियों और सोसाइटियों आदि के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण करता है तथा सतर्कता मामलों पर सलाह देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग द्वारा यह सलाह किसी विशेष मामले से संबंधित सभी तथ्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों के तर्कसंगत मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है, जो संबंधित संगठन उसके संज्ञान में लाता है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''अधिकतर मामलों में अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा आयोग की तर्कसंगत सलाह को स्वीकार करना, आयोग की सलाह की वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता का संकेत है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के कुछ मामलों में, या तो आयोग के साथ निर्धारित परामर्श तंत्र का पालन नहीं किया गया।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर, दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना

एजेंसी

नयी दिल्ली। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार शाम यहां पहुंच रहे हैं और इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जिसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की भी संभावना है।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री का यहां भारतीय उद्योग तथा व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। अमेरिका की अनेक देशों पर आयात शुल्क लगाये जाने की घोषणा के बाद दुनिया भर में व्यापारिक मोर्चे पर चल रही खींचतान के बीच उनकी भारत यात्रा को इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर आ रहे श्री वोंग के साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही इस यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों तथा साझेदारी को प्रगाढ बनाने के लिए भी अहम माना जा रहा है। वह बुधवार को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कौशल विकास , डिजिटल सहयोग , विमानन , अंतरिक्ष और जहाजरानी क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है। श्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच भविष्य की भागीदारी को लेकर संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया जा सकता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री मोदी और श्री वोंग के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय चर्चा होगी जिसके बाद प्रधानमंत्री उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के वित्त मंत्री के नाते वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी मुलाकात करेंगे। उनका विदेश मंत्री डा.एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझीदार और उसकी 'एक्ट ईस्ट' में शामिल प्रमुख देश है। श्री मोदी की सितंबर 2024 की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। दोनों प्रधानमंत्री मुलाकात के दौरान दोनों देशों के मज़बूत और बहुआयामी सहयोग की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य में सहयोग के रोड़मैप पर भी चर्चा करेंगे। वे परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री वोंग की यात्रा से संबंधों को विशेष साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने, विनिर्माण और कनेक्टिविटी जैसे मौजूदा सहयोग के क्षेत्रों को और मज़बूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा डेटा प्रवाह और बिजली व्यापार जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग और कौशल प्रशिक्षण के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम की संभावनाओं पर भी बात होगी। पिछले महीने यहां हुए तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने स्थिरता, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा, उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी से संबंधित संभावित सहयोगों पर चर्चा की थी।

सेना के एनसीसी शिविर में डेढ़ हजार कैडेट दो सप्ताह तक लेंगे गहन प्रशिक्षण

नयी दिल्ली। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) निदेशालयों के 1546 कैडेट यहां करियप्पा परेड ग्राउंड में करीब दो सप्ताह तक चलने वाले सेना के गहन प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले कैडेटों में 867 लड़के और 679 लड़कियां है। अतिरिक्त महानिदेशक (ए) एयर वाइस मार्शल पी वी एस नारायण ने मंगलवार को यहां शिविर का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट अवरोध प्रशिक्षण, मानचित्र पठन और अन्य संस्थागत प्रशिक्षण जैसी विविध गतिविधियों में अपना कौशल निखारेंगे। शिविर में शारीरिक गतिविधियों , मानसिक तीक्ष्णता और टीम वर्क पर जोर दिया जाएगा। थल सेना शिविर का उद्देश्य कैडेटों को सेना प्रशिक्षण के प्रमुख पहलुओं से अवगत कराना, उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना और अनुशासन, नेतृत्व एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। यह शिविर सेना विंग के कैडेटों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर के शिविर के रूप में व्यापक प्रशिक्षण एवं चरित्र विकास पर केंद्रित है। अपर महानिदेशक ने कहा कि एनसीसी युवाओं को ऐसे अनूठे अवसर उपलब्ध कराती है जो उनके रोमांच, अनुशासन और सम्मान से भरा जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी सभी कैडेटों में नेतृत्व और सौहार्द की भावना पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए तैयार करती है।

मोदी वैश्विक समुद्री सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित : सोनोवाल

नयी दिल्ली। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले 'भारत समुद्री सप्ताह' में भाग लेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम में मुख्य भाषण देंगे।
श्री सोनोवाल ने गुवाहाटी में-वाटर वॉयेज नॉर्थईस्ट 2025- सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन से दुनिया को अपनी समुद्री ताकत दिखाने का भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों के एक लाख से अधिक हितधारकों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्हेंने कहा कि समुद्री क्षेत्र इस समय अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। ऐसी स्थिति में भारत में यह सम्मेलन आयोजित होना और इसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की पुष्टि करेगा। श्री सोनोवाल ने कहा, ''भारत समुद्री सप्ताह न केवल विचारों का संगम होगा, बल्कि विश्वास का भी संगम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से हमारे समुद्री दृष्टिकोण का मार्गदर्शन किया है, उससे दुनिया अब भारत को एक विश्वसनीय साझेदार और एक उभरती हुई समुद्री शक्ति के रूप में देख रही है। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फ़ोरम में श्री मोदी की उपस्थिति वैश्विक उद्योग जगत की हस्तियों को भारत की विकास गाथा में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी।

पेज एक का शेष

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स ...

(जीसीसी) मॉडल पर हैं। इस योजना के अंतर्गत लखनऊ और कानपुर नगर समेत आस-पास के कस्बों में 10-10 रूटों पर 9 मीटर लंबी एसी ई-बसें चलाई जाएंगी। प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें अनिवार्य होंगी। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष की होगी। अनुमान है कि प्रत्येक रूट पर करीब 10.30 करोड़ का व्यय आएगा, जिसमें से ?9.50 करोड़ बसों की खरीद पर और ?0.80 करोड़ चार्जिंग उपकरणों व अन्य आवश्यक साधनों पर खर्च होंगे। प्रावधान के तहत, बसों का डिजाइन, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, आपूर्ति और अनुरक्षण की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर निभाएंगे। उन्हें 90 दिनों के भीतर प्रोटोटाइप ई-बस उपलब्ध करानी होगी और एक वर्ष के भीतर बस संचालन शुरू करना होगा। सभी किराया एवं गैर-किराया राजस्व का संग्रह निजी ऑपरेटर करेंगे। टैरिफ निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा। साथ ही सरकार परिवहन विभाग और आरटीओ/आरटीए से आवश्यक लाइसेंस और परमिट जारी करेगी। ई-बसों के संचालन के लिए सरकार बिहाइंड-द-मीटर विद्युत अवसंरचना और अपॉर्चुनिटी चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। सरकार का मानना है कि इस मॉडल से सरकारी वित्तीय बोझ में कमी आएगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर निर्यात हब बनाने की दिशा में योगी कैबिनेट ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दे दी है। नई नीति में 2020-25 की निर्यात नीति में सुधार करते हुए डिजिटल तकनीकी, अवसंरचना विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण और बीमा, बाजार विस्तार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि करना और सभी जनपदों को निर्यात गतिविधियों से जोड़कर क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश का निर्यात न केवल गुणात्मक रूप से बढ़ेगा बल्कि उत्तर प्रदेश को एक सशक्त ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। योगी कैबिनेट ने शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट की शैक्षणिक इकाइयों को उच्चीकृत किया जाएगा। वर्तमान में ट्रस्ट के अंतर्गत 5 संस्थान संचालित हैं–स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज, स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय, श्री दैवी सम्पद ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय, श्री धर्मानन्द सरस्वती इंटर कॉलेज और श्री शंकर मुमुक्ष विद्यापीठ। विश्वविद्यालय बनने के बाद इनका संचालन विश्वविद्यालय करेगा। जिलाधिकारी शाहजहांपुर की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के पास कुल 21.01 एकड़ भूमि है, जिसमें से लगभग 20 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय को मिलेगी। पहले चरण में उच्च शिक्षा विभाग और मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के बीच एमओयू होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत औपचारिक कार्यवाही पूरी की जाएगी।

मेडिकल कॉलेजों में...

के समक्ष राज्य सरकार की अपील पर सुनवायी हुयी। खंडपीठ ने अपीलकर्ता राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर को स्पष्ट करने को कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों व आरक्षण सम्बंधी प्रावधानों पर विचार के बाद पारित एकल पीठ के 25 अगस्त के फैसले में क्या कमी है।

दरअसल, एकल पीठ ने यह पाते हुए कि शासनादेशों दिनांक 20 जनवरी 2010, 21 फरवरी 2011, 13 जुलाई 2011, 19 जुलाई 2012, 17 जुलाई 2013 व 13 जून 2015 के जरिए आरक्षित वर्ग के लिए 79 प्रतिशत से अधिक सीटें सुरक्षित की गई हैं, इन शासनादेशों को निरस्त कर दिया था। साथ ही चारों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण अधिनियम, 2006 का सख्ती से अनुपालन करते हुए, नये सिरे से सीटें भरने का आदेश दिया था। याची के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि उक्त मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार के कोटे की कुल 85-85 सीटें हैं जबकि सिर्फ 7-7 सीटें अनारक्षित श्रेणी के लिए रखी गई हैं। वहीं, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण की ओर से दलील दी गई थी कि इंदिरा साहनी मामले में शीर्ष अदालत यह स्पष्ट कर चुकी है कि 50 प्रतिशत की सीमा अंतिम नहीं है, इससे अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि, एकल पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुयी थी और कहा था कि यह सीमा सिर्फ नियमों का पालन करते हुए ही, बढ़ाई जा सकती है।

एकेटीयू दीक्षांत समारोह...

प्रस्तावों के लिए बजट तय किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के घटक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ को 54 करोड़ का बजट को अनुमोदित किया गया। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में धरोहर (ए रिपोसिटरी फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम आइकेएस सेंटर) बनाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके लिए 50 लाख रूपये का बजट तय किया गया है। साथ ही आईकेएस में माइनर कोर्स चलाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। बैठक में विश्वविद्यालय एवं घटक संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के कल्याण के लिए भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें कर्मचारी कल्याण कोष के तहत किसी भी कर्मचारी के मृत्यु पर 15 लाख रूपये, एनपीएस कर्मियों को राज्य सरकार के शासनादेश को अंगीकृत करते हुए मृत्यु पर पुरानी सुविधाओं का लाभ, महिला कर्मियों को शिशु देखभाल अवकाश, प्रसूति अवकाश, विभिन्न बीमा कंपनियों के जरिये कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए 10 लाख रूपये का निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्यकीय सुविधा, ब्याज रहित अग्रिम भुगतान सात लाख एवं दस लाख रूपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में विजिटिंग, डिजिनस्टिगुइस एवं एमिरिट्स प्रोफ़ेसर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार शुरू किये गये बीटेक पाठ्यक्रम के लिए भी बजट तय किया गया। सामाजिक कार्यों के तहत गोंद लिये गये गांवों में कार्य कराने आदि के लिए एक करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया।

सबसे अधिक राजस्व...

जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 के सापेक्ष 612 मामलों का निस्तारण किया है। इसका रेश्यो 244.80 प्रतिशत है। जनपदीय न्यायायल में राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि 379 मामलों का निस्तारण कर दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी और 400 मामले निस्तारित कर तीसरे स्थान पर आजमगढ़ है। इसी तरह अगस्त में मऊ के जिलाधिकारी न्यायालय ने 91 मामलों का निस्तारण कर 303.33 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की, जो प्रदेश भर में सबसे अधिक है और मऊ प्रदेश भर में पहले स्थान पर है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 79 मामले निस्तारित किए गए। वहीं जौनपुर के जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 68 मामले निस्तारित किए गए। इसी तरह जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा निस्तारित किये गये मामलों में बुलंदशहर दूसरे और जौनपुर तीसरे स्थान पर है। भू राजस्व संबंधित मामलों के निस्तारण में भी जौनपुर अव्वल इसी प्रकार अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व जौनपुर निर्धारित मानक 50 के सापेक्ष कुल 208 वादों का निस्तारण कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं। वहीं अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व गाजीपुर कुल 30 वादों का निस्तारण कर दूसरे स्थान पर हैं तथा अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व मीरजापुर कुल 24 वादों का निस्तारण कर तीसरे स्थान पर हैं। इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने 50 के मानक के मुकाबले 211 मामलों का निस्तारण कर 422 प्रतिशत हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि 105 मामले निस्तारित कर आजमगढ़ दूसरे और 80 मामले निस्तारित कर झांसी तीसरे स्थान पर है।

राष्ट्रपति के मामले ...

पहली शर्त पूरी न हो। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि विधानसभा से पास बिल पर वह या तो मंजूरी दें, मंजूरी रोक लें, पुनर्विचार के लिए वापस भेजें या राष्ट्रपति के पास आरक्षित करें। पहली शर्त यह है कि अगर विधानसभा दोबारा विचार के बाद विधेयक वापस भेज दे, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि अगर राज्यपाल अनिश्चित समय तक बिल रोक कर रखते हैं, तो 'जल्दी' शब्द का महत्व खत्म हो जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि राज्य सरकारें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकतीं, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते।

कांग्रेस-आरजेडी ने मेरी...

हमारा संसार होती है... मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में जो कुछ हुआ...उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं और मेरी माँ के साथ करोड़ो महिलाओं का अपमान किया गया। श्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोग उस जंगल राज को नही भूले हैं जब शाम के समय हर मां गुंडों और माफिया के खौफ से सलामत लौटने की दुआ करती थी। ऐसे संस्कार वाले लोग अगर दुबारा आ गए तो महिलाओं की स्थिति पहले की तरह बदतर हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने आपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बिहार के लोगो से कहा 'आप सबको भी, बिहार की हर माँ को ये देख-सुनकर कितना बुरा लगा है! मैं जानता हूँ, इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है।' आखिर में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि बिहार के लोग ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में जरूर सबक सिखायेंगे। गौर तलब है कि पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समय दरभंगा में एक मंच से उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी और उनके मां को गली दी थी जिसका विडियो सामने आया था।

भारत की सबसे छोटी चिप...

जा रही है। इसका उद्देश्य इस सेक्टर में भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विकसित विकसित करना है। सेमीकंडक्टर चिप को डिजिटल डायमंड बताते हुये उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में दुनिया का भाग्य तेल के कुंओं से तय होता था। इक्कीसवीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी हैं, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। उन्होंने कहा कि आज सेमीकंडक्टर्स का वैश्विक बाजार 60 हजार करोड़ डॉलर का है जो अगले कुछ वर्षों में एक लाख करोड़ डॉलर को पार कर जायेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस रफ्तार से भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग बढ़ रहा है इसमें एक अहम हिस्सा भारत का होगा। श्री मोदी ने कहा कि कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर की 10 परियोजनाओं में 18 अरब डॉलर (डेढ़ लाख करोड़ रुपये) से अधिक का निवेश हो रहा है। यह भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली लागू की है जिससे ''फाइल से फैक्ट्री'' का समय कम हुआ है और केंद्र तथा राज्यों की सारी मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। इससे निवेशकों पर कागजी कार्रवाई का दबाव समाप्त हो गया है। सरकार सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और डिजाइन आधारित प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इसका परिणाम है कि माइक्रॉन और टाटा ने टेस्ट चिप बनाने शुरू कर दिये हैं और इसी साल बाजार में स्वदेशी वाणिज्यिक चिप भी आ जायेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर्स की सफलता की कहानी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें डिजाइनिंग, विनिर्माण, पैकेजिंग और हाई-टेक डिवाइस आदि देश में उपलब्ध हो। सरकार ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रही है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाये। उन्होंने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर सेक्टर के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी लगातार काम कर रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत दुर्लभ खनिजों की मांग देश से ही पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। चार सालों में इस परियोजना पर काफी काम हुआ है। उन्होंने राज्यों से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद निवेशकों से उन्होंने अपील की, ञ्चहम खुले दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आपकी भाषा में कहूं, तो डिजाइन तैयार है, मास्क अलाइंड है। अब अब समय सटीकता के साथ क्रियान्वयन का है, और बड़े पैमाने पर परिणाम देने का है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां अल्पकालिक संकेत नहीं हैं, ये दीर्घावधि प्रतिबद्धताएं हैं। सरकार उद्योग की हर जरूरत पूरी करेगी और वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी - डिजाइंड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत परिवर्तनकारी विकास का केंद्र बनकर उभरा है। भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर का हब बन रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत पूरे विश्व की दिशा तय करने वाला है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना के जलस्तर एवं प्रभावित इलाकों में जलभराव की स्थिति का लिया जायजा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को गीता कॉलोनी फ्लाइओवर बनाएं गए बाढ़ शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने यमुना के जलस्तर और प्रभावित इलाकों में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रेखा गुप्ता ने यमुना के डूब रहे क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। गुप्ता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ हर पल खड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रहने की सुविधा, भोजन, पानी और दवा हर जरूरी इंतजाम पहले से ही कर दिए गए हैं। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि किसी भी नागरिक को कठिनाई न हो और हर परिवार सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। पिछले छह महीनों में दिल्ली सरकार द्वारा नालों और यमुना की डी-सिल्टिंग का जो व्यापक काम किया गया है,

उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। पानी का बहाव निर्बाध रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को सरकार किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नही करने देगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की कोशिश यही है कि समय रहते हर जरूरी कदम उठाया जाए ताकि जनता सुरक्षित रहे और किसी भी परिस्थिति में उन्हें चिंता न करनी पड़े। उल्लेखनीय है कि यमुना का जलस्तर 205.9 है जो खतरे के निशान से ऊपर है। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया हैं।

दस साल से फरार आजीवन कारावास का दोषी गुजरात से गिरफ्तार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे और पिछले 10 साल से फरार आरोपित को गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान मुज़फ्फरनगर उप्र निवासी हसीन हुसैन उर्फ हसीन हैदर (47) के रूप में हुई है।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार 27 मार्च 2006 को दिल्ली के वेलकम इलाके में आरोपित और उसके परिवार ने अपने पड़ोसियों पर हमला किया। इस घटना में पप्पू और अनीशा की हत्या कर दी गई। जबकि हेना (शिकायतकर्ता की बहन) पर चाकुओं से हमला किया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हमला दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश और शादी को लेकर विवाद के चलते किया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किशा। जांच के बाद 2013 में हसीन हुसैन समेत चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2015 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सजा को बरकरार रखा। लेकिन 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की पैरोल पर रिहा किया। जिसके बाद वह फरार हो गया और 10 साल तक गिरफ्तारी से बचता रहा। फरार रहने के दौरान आरोपित ने कपड़े बेचने का काम शुरू किया और जगह-जगह भटकता रहा। जांच में पता चला कि आरोपित पहले असम में करीब 3 साल रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश में तीन साल छिपकर गुजारे और पिछले 4 साल से गुजरात के गोधरा में रहकर कपड़े बेचकर गुजारा करता रहा। डीसीपी के अनुसार क्राइम ब्रांच की एआरएससी यूनिट टीम को गुप्त सूचना मिली कि फरार हसीन हुसैन गुजरात के गोधरा में रह रहा है। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे दबोचा गया।

संक्षिप्त समाचार

हत्या के मामले में वांछित आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिंदापुर इलाके में हत्या के मामले में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान भरत विहार राजापुरी निवासी अशद उर्फ अर्शद (20) के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा के अनुसार आरोपित बिंदापुर निवासीकुलदीप सिंह की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। 18 अगस्त को दर्ज मामले में अशद की तलाश की जा रही थी। हत्या की घटना 17 अगस्त को हुई थी, जब शिकायतकर्ता बंटी के चाचा कुलदीप सिंह का झगड़ा रितिक उर्फ़ डांसर और मुन्ना से हुआ। इसी दौरान रितिक ने अपने साथी से चाकू लेकर कुलदीप सिंह पर वार किया। जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में पहले ही पवन और मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अन्य आरोपित फरार थे। डीसीपी के अनुसार इस बीच क्राइम ब्रांच में कार्यरत एसआई अनुज छीकरा को सूचना मिली कि वांछित अपराधी अशद अपने साथियों से मिलने के लिए कटेवाड़ा गांव आने वाला है। सूचना को पुख्ता कर एक टीम गठित की गई। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपित का लोकेशन ट्रेस किया और कटेवाड़ा गांव में जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में अशद ने अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और वह अविवाहित है। शराब की लत और गलत संगत में पड़कर वह अपराध की दुनिया में आया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अक्सर मोबाइल नंबर बदल देता था।

पुलिस ने अगस्त में 130 लापता लोगों को परिवारों से मिलवाया

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने पुलिस ने 'ऑपरेशन मिलाप' के तहत एक महीने के भीतर 130 लापता लोगों को खोज निकाला। इनमें 48 नाबालिग बच्चे शामिल है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि गुमशुदगी की सूचना मिलते ही संबंधित थाने की टीमें सक्रिय हो गईं। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो-ई-रिक्शा स्टैंड पर फोटो दिखाकर पहचान करवाई गई। इसके अलावा अस्पताल, बस ड्राइवर, कंडक्टर, दुकानदार और स्थानीय मुखबिरों की मदद ली गई। डीसीपी के अनुसार वहीं अब तक दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने एक जनवरी से 31 अगस्त तक 931 लापता व्यक्तियों को ढूंढ चुकी है। जिनमें 306 नाबालिग और 625 वयस्क शामिल हैं। किस थाने से कितने लापता खोजे गएकापसहेड़ा-14 नाबालिग तथा 13 पुरुष/ महिलासागरपुर- 3 नाबालिग तथा 15 पुरुष/महिलापालम गांव-2 नाबालिग तथा 13 पुरुष/महिलावसंत कुंज साउथ- 2 नाबालिग तथा 9 पुरुष/महिलादिल्ली कैंट - 2 नाबालिग तथा 3 पुरुष/महिलाकिशनगढ़- 1 नाबालिग तथा 6 महिलाएंवसंत कुंज नॉर्थ- 4 नाबालिग तथा 6 पुरुष/महिलाआरके पुरम- 3 नाबालिग तथा 1 महिलासफदरजंग एन्क्लेव- 4 नाबालिग तथा 5 पुरुष/महिलावसंत विहार- 3 पुरुष/महिलासरोजनी नगर- 7 पुरुष/महिलासाउथ कैंपस- 2 महिलाएंएंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट- 14 नाबालिग।

बीएसएफ जवानों ने बाढ़ में फंसे 100 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

चंडीगढ़। पंजाब में आई बाढ़ के दौरान लोगों की मदद में जुटे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने सीमावर्ती जिला फिरोजपुर से सौ ग्रामीणों को सुरिक्षित निकाला है।बीएसएफ के अनुसार सतलुज नदी के लगातार उफान पर होने के कारण फिरोजपुर के निहाला लवेरा और ढेरा गढ़ी गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने प्रभु आश्रम कुराली के सहयोग से लगभग 100 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। गांवों में राहत सामग्री भी वितरित की गई।इसके अलावा फाजिल्का जिले में बीएसएफ जवानों ने सीमावर्ती गांव महार जमशेर के एक गंभीर रूप से घायल निवासी की मदद की। स्पीड बोट की मदद से पीड़ित को बाढ़ के पानी से सुरक्षित बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

उत्तराखंड में नदियां उफान पर, बारिश से भूस्खलन का खतरा, जन जीवन अस्त-व्यस्त

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से अब डर और भय का वातावरण बनता जा रहा है। भागीरथी नदी पर हर्षिल में और यमुना नदी पर स्याना चट्टी में बनी झील से खतरा बना हुआ है। स्याना चट्टी में यमुना नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से होटल व आवासीय भवन जलमग्न हैं। वहीं सरयू, गोमती, अलकनंदा, भिलंगना, काली नदी, मंदाकिनी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। मैदानी क्षेत्रवासी भी जलभराव से जूझ रहे हैं। अतिवृष्टि से संकट बढ़ता जा रहा है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी व चमोली में बारिश को देखते हुए कक्षा 1 से 12 व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भी देहरादून, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली व बागेश्वर जनपदों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेतावनी को देखते हुए नदियों के किनारे सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही लोगों को सतर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संपर्क में हैं और अपडेट पर लगाया नजर रखी जा रही हैं।

बारिश में खिसकते मुसीबतों के पहाड़, धौलीगंगा पर बनी झील से निचले इलाकों बढ़ा खतरा, सेना व बीआरओ पानी निकासी में जुटी

देहरादून। चमोली जिले में चीन सीमा तक पहुंच वाले मार्ग पर नीति घाटी में तमक नाले का बहा पुल आगे पत्थरों में फंसने से धौलीगंगा में एक बड़ी झील बन गयी है। इस झील से निचले इलाकों में खतरे की आशंका बढ़ गई है। बीआरओ ने इस झील का पानी की निकासी के प्रयास में जुटा है। पानी की तेज प्रवाह में बहे पुल के स्थान पर बीआरओ ने वैकल्पिक पुल बनाकर यातायात शुरू कर दिया है। इसके अलावा सड़कों पर भूस्खलन से लगातार मलबा आने से बंद चल रही चारधाम यात्रा के मार्ग खोलने के प्रयासों में प्रशासन जुटा है। चमोली राष्ट्रीय राजमार्ग बदरीनाथ कंचनगंगा, भनेरपानी, नन्दप्रयाग, चटवापीपल नंदप्रयाग, कामेडा में भूस्खलन से बंद हैं। रुद्रप्रयाग में बाईपास पर सड़क लगातार धंस रही हैं। इससे यहां वाहनों की आवाजाही खतरनाक हो सकती है। बागेश्वर जनपद में पिछले दो दिन से रुक-रुक कर लगातार से आठ ग्रामीण मोटरमार्ग बंद हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र बैसानी में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। यहां लापता दो लोगों की खोज में बचाव टीमें लगी हुई हैं। सरयू व गोमती नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

बिहार मंत्रिमंडल ने 49 एजेंडों पर लगाई मुहर

■राज्य के सात जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार में चुनावी माहौल के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और कल्याण योजनाओं को लेकर बड़े फैसले लिए गए, इसका सीधा लाभ लाखों छात्रों, कर्मचारियों और आम जनता पर पड़ेगा।

बिहार सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में पंचायती तकनीकी लेखपाल और आईटी सहायकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना को 241 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी गई है। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल के बड़े फैसलों में बिहार के सात जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला भी शामिल है। बिहार कैबिनेट ने गांधी मैदान में की गई अपनी घोषणा के आलोक में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। अरविंद चौधरी ने कहा कि बिहार गृहरक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये प्रत्येक कार्य दिवस से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के 1 दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप 1121 रुपये करने का फैसला लिया गया है, जबकि ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखंड लेखपाल, लेखा सहायक के मूल मानदेय में 25 प्रतिशत ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के मूल मानदेय में 20 प्रतिशत और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के मूल मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने कला एवं संस्कृति विभाग में 25 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल और संरचना निर्माण के लिए पुनपुन अंचल के डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 574 करोड़ 33 लाख 90125 रुपये भी मंजूर किए गए हैं, जबकि पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए 4,129 करोड़ 6 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। अरविंद चौधरी ने बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30 प्रतिशत जोखिम भत्ता, जो अधिकतम 25 हजार होगा, उसकी भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सौंपानों के लिए वेतन संरचना की भी मंजूरी मिली है।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और अधिक कीमत वसूलने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश

जालंधर। पंजाब में जालंधर के जिला उपायुक्त डा. हिमांशु अग्रवाल ने पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के मद्देनजर मंगलवार को जिले के दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और अधिक कीमत वसूलने वालों को चेतावनी दी। डा. हिमांशु ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ दुकानदार बाढ़ का हवाला देकर किराना, सब्जियां, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी लूट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने खुराक एवं सिविल सप्लाई विभाग को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए नियमित तौर पर बाजारों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

मुक्तसर साहिब में लॉरेंस गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार, हथियार बरामद

कैनविज टाइम्स संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने राज्य के मुक्तसर साहिब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और पांच अतिरिक्त मैगजीन बरामद की हैं। बरामद हथियारों में चार पिस्तौल (.32 बोर) और एक पिस्तौल (.30 बोर) शामिल है।पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि मुक्तसर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त आरोपित उनके एरिया में गतिविधि कर रहे हैं। सूचना के आधार पर तुरंत पुलिस द्वारा रेड की गई और दोनों को दबोच लिया गया। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और संगठित अपराध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे। पुलिस को शक है कि आरोपित राज्य में आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपितों द्वारा इन हथियारों का कहां इस्तेमाल किया जाना था, इस पर पूछताछ की जा रही है। आगे की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उक्त आरोपित लॉरेंस के किस हैंडलर के टच में थे।

विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पटियाला। पंजाब में पटियाला की सन्नौर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा मंगलवार को पुलिस हिरासत से फरार हो गए। विधायक को आज सुबह यौन उत्पीड़न के कथित आरोपों में हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पठानमाजरा को गिरफ्तार कर पंजाब लेकर आ रही थी। इस दौरान वह अपने साथियों के सहयोग से पुलिस हिरासत से फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार पठानमाजरा अपने साथियों के साथ एक फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में भाग गया। उसके समर्थकों के हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। एक दिन पहले ही उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों के संचालन को लेकर अपनी ही सरकार की आलोचना की थी और ''दिल्ली लॉबी'' पर पंजाब के मामलों में दखलंदाज़ी का आरोप लगाया था। सूत्रों के अनुसार पठानमाजरा के खिलाफ सोमवार शाम भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया और उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। गिरफ्तारी से पहले पठानमाजरा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि पंजाब पुलिस ने मेरी पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले में आईपीसी की धारा 376 (रेप) के तहत केस दर्ज किया है। यह केस जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर हुआ है, जिसने कहा है कि वह और पठानमाजरा 2013-14 में सोशल मीडिया पर मिले थे और 2021 में उन्होंने शादी कर ली थी। पठानमाजरा को मार्च 2022 में पटियाला के सन्नौर से चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इसके बाद, 23 अगस्त 2022 को उस महिला ने पंजाब हाईकोर्ट में अर्जी दी, जिसके बाद कोर्ट ने 2024 में पुलिस को इस मामले की जांच करने को कहा।

मसूरी गोलीकांड के बलिदानियों को मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धांजलि

कैनविज टाइम्स संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मसूरी गोलीकांड की बरसी पर बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृतसंकल्पित होकर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी के जन्मशताब्दी समारोह को भी भव्य तरीके से मनाएगी। मंगलवार को मसूरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री धामी ने संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी में बलिदान हुए आंदोलनकारी बलबीर सिंह नेगी, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी और मदन मोहन ममगई को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने गढ़वाल सभा भवन जल्द बनाने और सिफन कोर्ट का मामला जल्द हल करने की बात कही और मसूरी में वेंडर जोन की घोषणा सहित अन्य मांगों पर भी शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर 1994 का दिन राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। इस दिन मसूरी की वीरभूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। यह घटना उस समय के सत्ताधारी दलों के दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। साथ ही शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए तीन हजार रुपये मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को छह हजार रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को साढ़े चार हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब नए कानून के अंतर्गत चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित भी किया है।

चेयरमैन एवं प्रधान सम्पादक - राकेश कुमार पाण्डेय कार्यकारी सम्पादक* - अरशद सईद खान स्टेट हेड - संदीप मिश्रा

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा सरस्वती प्रिंटर्स वाटर वर्क्स रोड ऐशबाग, लखनऊ से मुद्रित एवं सी-46, कृष टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, पिन-226010 से प्रकाशित। * इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी।

समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय क्षेत्र के ही अधीन होंगे। फोन नं। 0522-4249333 फैक्स नं.- 4249333 e-mail : info@kanwhizztimes.com RNI NO - UPHIN/2012/42063